राष्ट्रीय संस्करण

पेरिस एआइ सम्मेलन की मोदी करेंगे मैक्रों के साथ अध्यक्षता >> 3

वर्ष 8 अंक 233

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, गुरुवार, 30 जनवरी, 2025

www.jagran.com

पृष्ठ 14

मौनी अमावस्या : संगम नहाया जनसागर

रवि प्रकाश तिवारी ● जागरण

महाकुंभ नगर: त्रिलोक के दिव्यतम अनुष्ठान महाकुंभ में बुधवार को मौन का अलौकिक महानाद हुआ। मौनी अमावस्या के मुहूर्त ने अमृतधारा में जैसे ही प्रवेश किया, नभमंडल से पुण्य झर झर बरसने लगा। मौन ने महा आकार धारण कर लिया। श्रद्धालुओं के तपोबल से अणु-परमाणु उर्जित हो उठे। संगम तट पर मन, वाणी और संयम के परिमार्जन की बेला थी। श्रद्धालुओं को महापुण्यदायी और त्रिभुवनतारिणी गंगा का आशीर्वाद मिला। मौनी अमावस्या का स्नान कर श्रद्धालु स्वयं तीर्थ समान बन गए। देर शाम तक संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आठ करोड़ के आंकड़े को पार कर गई।

मौनी अमावस्या के पुण्य स्नान की ब्रह्मबेला से सवा दो घंटे पहले संगम तट पर हुई भगदड़ से इस जनसमूह का कोई सरोकार न था। उनका अभीष्ट पुण्य की एक डुबकी थी, जिसके लिए सभी दिशाओं से श्रद्धालु अनवरत आते रहे। कुछ दिनों से सुबह से ही सूरज की तपिश झेलनी मुश्किल थी, लेकिन बुधवार को भारी भीड़ पर भगवान भास्कर भी कई बार बादलों की ओट में चले गए। मंगलवार देर रात हुई दुर्घटना के दृष्टिगत अखाड़ों ने भी संयम, सहयोग का प्रणम्य परिचय दिया। वे श्रद्धालु प्रथम के भाव में सुबह पांच के बजाय दोपहर में अमृत स्नान को निकले...सादगी के साथ। इस क्षण के साक्षी थे बैरिकेड के दोनों ओर खड़े हाथ जोड़े श्रद्धालु जो संत-महात्माओं और नागाओं को देख अभिभूत थे। संगम में स्नान के बाद पति के साथ दीपदान कर रहीं सहारनपुर से आईं मोनिका की आंखें छलक रही थीं। कारण पूछने पर सुबकती बोलीं, बरसभर में ही बेटे का एडमिशन ट्रिपल आइटी में हो गया व बेटी का घर बस गया। दोनों की हमें चिंता थी, लेकिन तीर्थराज के प्रताप से सब पार लगा। यह कहते हुए उन्होंने संगम को चुनरी अर्पित कर दी। (पेज-6 भी देखें)

महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम तट पर डुबकी लगाते नागा संन्यासी ● संजय यादव

महावेला में अमृत स्नान, शाम तक ही आंकड़ा आठ करोड़ पार

गंगाभक्तों की टोली का क्रम संगम क्षेत्र में देर शाम तक अनवरत चला

संत-महात्माओं और नागाओं को देख अभिभूत थे संगम में उपस्थित श्रद्धालु

महापुण्यदायी गंगा का श्रद्धालुओं को मिला आशीर्वाद

मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए मंगलवार से ही श्रद्धालुओं का उमड़ा जन ज्वार

लगातार दूसरे दिन प्रयागराज रहा दुनिया का सबसे बड़ा शहर (संख्या करोड़ में)

प्रयागराज ने फिर इतिहास रच दिया है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम नगरी ने दुनिया के सबसे बड़े शहरों को भी जनसंख्या के मामले में लगातार दूसरे दिन भी पीछे छोड़ दिया। बुधवार को यहां आठ करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, इस वजह से यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा शहर बना बल्कि इसकी जनसंख्या कई देशों से अधिक रही। मौनी अमावस्या स्नान के लिए मंगलवार से ही श्रद्धालुओं का जन ज्वार उमड़ पड़ा था और प्रयागराज में पांच करोड़ से अधिक लोगों की मौजूदगी रही। बुधवार को यह संख्या छह करोड़ के पार रही।

महाकुंभ नगरी	8.0
टोक्यो	3.74
दिल्ली	2.93
शंघाई	2.63

कई देशों से अधिक रही प्रयाग में लोगों की मौजूदगी

स्पेन	4.84
यूक्रेन	3.7
पोलैंड	3.67
मलेशिया	3.43

अटूट रही गंगाभक्तों की कतार

मौनी के महात्म्य का पुण्य लाभ लेने के लिए बीते मंगलवार से चली आ रही गंगाभक्तों की टोली का क्रम बुधवार शाम तक एक भी पल टूटा नहीं। शाम लगभग चार बजे बंगाल में पानागढ़ के मोहितोष महतो पत्नी सहित 10 लोगों की टोली में संगम की ओर बढ़े जा रहे थे। पूछा, इतनी देर से? तो बोले-ट्रेन से आए हैं। लगभग छह किमी पैदल चल चुके हैं। इतनी दूर कुंभ स्नान के लिए आए हैं तो बगैर पुण्य लाभ लिए लौटें कैसे? अपने पंडों को ढूंढते शंकर विमान मंडपम के पास रामलाल 16 लोगों के साथ कटनी से चले आ रहे थे। उन्हें चिंता थी कि अमावस्या में ही स्नान कर लें। उन्हें पता भी नहीं था कि सुबह कोई घटना घटी थी और न ही कुछ जानने की जिज्ञासा। गंगा उन्हें पुकार रहीं थीं और भक्त उनके समक्ष हो प्रणाम को व्यग्र।

महाकुंभ में भीड़ से कुचलकर 30 की मौत, 60 घायल

- मरने वालों में 25 की पहचान, गंभीर रूप से घायल 36 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज
- भीड़ का दबाव बढ़ने से अखाड़ों के अमृत स्नान मार्ग की टूट गई थी बैरिकेडिंग
- ब्रह्म मुहूर्त की प्रतीक्षा में तट पर लेटे लोगों की जान पर भारी पड़ा भीड़ का दबाव

जागरण संवाददाता, महाकुंभ नगर

संगम की पावन धरा पर आयोजित महाकुंभ के सबसे बड़े अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर मंगलवार की रात हुए अमंगल में 30 लोगों की मौत गई है। महाकुंभ मेला पुलिस ने बुधवार शाम इसकी पुष्टि की। डीआइजी वैभव कृष्ण ने बताया कि भगदड़ में कुल 90 श्रद्धालु घायल हुए थे, जिनमें 30 की मौत हो गई। घायल 60 श्रद्धालुओं में 36 का अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 24 स्नानार्थियों को उनके घर भेज दिया गया। मरने वालों में 25 की पहचान हो गई है। इनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम व गुजरात के व्यक्ति शामिल हैं।

महाकुंभ के मीडिया सेंटर में बुधवार शाम मेलाधिकारी विजय किरन आनंद के साथ पहुंचे डीआइजी महाकुंभ नगर वैभव कृष्ण ने सबसे पहले भगदड़ की वजह बताई। कहा कि मंगलवार आधी रात के करीब संगम तट पर भारी भीड़ का दबाव बन गया था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर ब्रह्म मुहूर्त में पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग लेटे थे। इसी बीच भीड़ का अतिरिक्त दबाव बन गया, जिससे अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए बनाए गए राजसी पथ की बैरिकेडिंग टूट गई और भीड़ आगे बढ़ते हुए स्नान करने की प्रतीक्षा कर रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गई। इससे वहां अफरा-तफरा मच गई। तट पर जो लोग प्रतीक्षा में लेटे थे, वे दबते गए। वहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने फौरन राहत कार्य शुरू किया। लगभग 90 घायलों को एंबुलेंस से महाकुंभ मेला के केंद्रीय अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां 30 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। अज्ञात पांच शवों की पहचान की कोशिश की जा रही है।

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ की घटना के बाद बचाव-अभियान चलाया गया। प्रेट्र

यह रहा घटनाक्रम

1 बजे रात के बाद संगम तट पर भीड़ के दबाव से मच गई थी भगदड़

12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम तट पर थे आधी रात के समय

3 बजे भोर में था मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त

हादसे को लेकर भावुक हुए उप्र के मुख्यमंत्री योगी

हादसे को लेकर उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। रुंधे गले से बोले, 'घटना दुखद है, मर्माहत करने वाली है।' कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले 'उन सभी स्वजन के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, जिन्होंने अपनों को खोया है। हम लोग रात से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थीं, उन सभी को वहां पर तैनात किया गया है।'

मौनी पर वीआइपी प्रोटोकाल नहीं पेज>>6

सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर खत्म किया पीजी मेडिकल में निवास आधारित आरक्षण

- कहा- एमबीबीएस में एक हद तक यह आरक्षण स्वीकार्य, लेकिन पीजी में नहीं
- इस आरक्षण का पूर्व में लाभ पा चुके छात्रों पर नहीं पड़ेगा इस फैसले का असर

नई दिल्ली, एएनआइ : एक दूरगामी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मेडिकल के स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के राज्य कोटे में निवास (डोमिसाइल) आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है। कोर्ट ने उसे समानता का अधिकार प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करने वाला बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों को पहले ही निवास आधारित आरक्षण मिल चुका है, इस फैसले का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जस्टिस हृषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य कोटे की सीटों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की मेरिट के आधार पर भरा जाए। पीठ ने कहा, 'हम सभी भारत के निवासी हैं। प्रांतीय या प्रादेशिक निवास जैसी कोई चीज नहीं है। सिर्फ एक ही निवास है, हम सभी भारत के निवासी है। हमें भारत में कहीं भी निवास करने और देश में कहीं भी व्यापार करने व पेशा अपनाने का अधिकार है। संविधान हमें भारत भर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार भी देता है।' साथ ही कहा, 'हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक हद तक एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए राज्य में निवास आधारित आरक्षण स्वीकार्य है, लेकिन पीजी पाठ्यक्रमों के लिए यह आरक्षण कतई स्वीकार्य नहीं है।' पीठ ने शीर्ष अदालत के पूर्व फैसलों का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि स्नातकोत्तर के स्तर पर मेरिट से समझौता नहीं किया जा सकता, हालांकि निवास आधारित आरक्षण कुछ हद तक स्नातक या एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में स्वीकार्य हो सकता है। पीठ ने कहा कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ डाक्टरों के महत्व को देखते हुए निवास के आधार पर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन होगा। अगर इस तरह के आरक्षण की अनुमति दी गई तो यह कई छात्रों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होगा जिनके साथ सिर्फ इसलिए असमानता का व्यवहार किया जा रहा है कि वे देश के दूसरे राज्य के निवासी हैं।

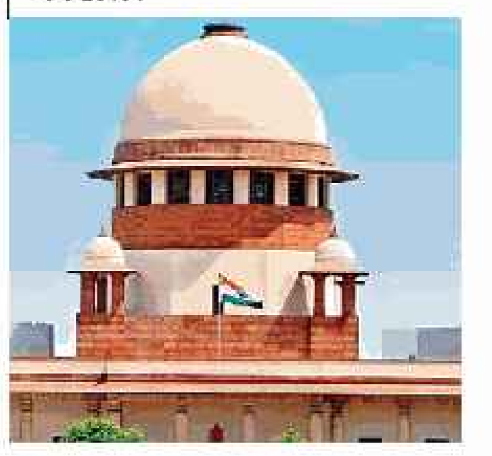

चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल में मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 28 मार्च, 2019 को प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई थी। राज्य कोटे की 64 सीटें चंडीगढ़ निवासियों या उसी कालेज से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए आरक्षित थीं। इस आरक्षण को कुछ छात्रों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसने इसे अवैध करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि 32 सीटों को संस्थान की प्राथमिकता के आधार पर भरा जा सकता था, लेकिन 32 अन्य सीटों को निवास के आधार पर गलत तरीके से भरा गया। शीर्ष अदालत ने यह फैसला एक खंडपीठ के संदर्भ पर सुनाया है जिसने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील पर सुनवाई के दौरान कुछ सवाल उठाए थे।

दैनिक जागरण जनमन

जागरण जनमन ने सुलझाई उलझन

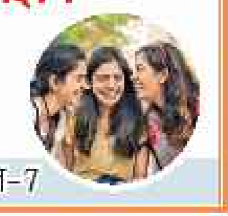

क्या है किशोरों की नजर में एक अच्छा जीवन ● पेज-7

संपादकीय

तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा: यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शोध एवं विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा। **शिवकांत शर्मा** का दृष्टिकोण।

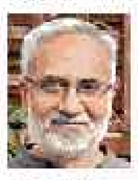

सबके हित की चिंता करे सरकार: सरकार को यह देखना चाहिए कि अधिकाधिक लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कैसे आएं। **राजीव सचान** का आलेख। ● पेज-8

विमर्श

स्वच्छ छवि वालों को ही चुनाव लड़ने का अवसर: आगामी बुधवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जनता को केवल साफ-सुथरी छवि वाले लोगों को ही चुनने का विकल्प मिल सके। **लालजी जायसवाल** का आलेख।

फिर कब जागेंगे भ्रष्टाचार के मारामच्छ: पहले भ्रष्टाचार की बात आती थी तो चौतरफा बिहार के चारा घोटाले की बात की जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश इसमें सबसे आगे निकल गया है। **धनंजय प्रताप सिंह** की मध्य प्रदेश डायरी। ● पेज-9

सप्तरंग

तकनीक की दुनिया का

एआइ में अब चीन की चुनौती!

कैसे चुनें सही टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स ● पेज-13

जागरण विशेष

फूंक मारते ही पता चलेगा शरीर में शर्करा का स्तर

बालाघाट: मधुमेह रोगियों में शर्करा (शुगर) के स्तर का पता लगाने के लिए अब उन्हें रक्त का नमूना देने से मुक्ति मिल सकती है। ● पेज-14

'तत्काल तीन तलाक में कितनी एफआइआर और चार्जशीट हुईं'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह मुस्लिम महिलाओं (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का उल्लंघन कर पत्नियों को तत्काल तीन तलाक देने वाले पुरुषों पर दर्ज एफआइआर व चार्जशीट के आंकड़े पेश करे। कहा कि अब सभी राज्यों में एफआइआर केंद्रीयकृत हैं, हमें सिर्फ उसकी सूची दे दीजिए जिसमें ग्रामीण इलाकों के आंकड़े भी हों। (पेज-5)

सटीकता पर सवाल

थ्येन आनमन के बारे में पूछे जाने पर चीनी चैटबाट ने नहीं दिया सही जवाब, अमेरिकी चैटजीपीटी ने बताया नरसंहार, चीन जैसे देशों में विकसित एआइ टेक्नोलाजी हो सकती हैं देश या सरकार के नैरेटिव से प्रभावित

चीन को चुभने वाले सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है डीपसीक

जेएनएन, नई दिल्ली

- राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवालों पर डीपसीक की सीमाएं उजागर

चीन का एआइ प्लेटफार्म डीपसीक दूसरे एआइ प्लेटफार्म की तुलना में सस्ता होने और अपने प्रदर्शन के कारण चर्चा में है। इसने चीन और पश्चिमी देशों खास तौर पर अमेरिका के बीच एआइ को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा को और तीखा कर दिया है। इस बीच यह देखा जा रहा है कि डीपसीक चीन को चुभने वाले सवालों पर गोलमोल जवाब दे रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इन पक्षपाती जवाबों ने इसको लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जैसे डीपसीक से जब पूछा गया कि थ्येन आनमन चौक पर क्या हुआ था तो उसका जवाब था कि यह मेरी क्षमता से बाहर है। किसी और चीज के बारे में बात करें। वहीं जब अमेरिकी एआइ प्लेटफार्म चैटजीपीटी से यही सवाल पूछा गया तो उसका जवाब था कि थ्येन आनमन नरसंहार 1989 में बीजिंग में हुआ था। यहां लोकतंत्र की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसे कुचलने के लिए चीन की सरकार ने हिंसा का सहारा लिया। ऐसे में राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवालों को लेकर डीपसीक की सीमाएं भी उजागर हो रही हैं। इसी तरह से जब डीपसीक से पूछा गया कि कोविड कहां से शुरू हुआ था तो इस पर उसका जवाब घुमाने वाला था। चीनी एआइ प्लेटफार्म के जवाब में चीन और वुहान का जिक्र ही नहीं था। ऐसे में सवाल उठ रहा है एआइ प्लेटफार्म अगर किसी सवाल का तथ्यात्मक जवाब देने के बजाए अपने देश और सरकार की सहूलियत को ध्यान में रख कर जवाब दे रहा है तो उसकी सटीकता पर कितना भरोसा किया जा सकता है। एक एक्स यूजर ने डीपसीक पर लिखा अरुणाचल प्रदेश एक भारतीय राज्य है। इस पर चैटबाट ने जवाब दिया माफ करें, यह मेरी क्षमता से बाहर है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सूची मांगने पर भी डीपसीक ने इसी तरह का जवाब दिया। इस तरह के जवाब सामने आने के बाद डीपसीक की प्रोग्रामिंग को लेकर चिंता जताई जा रही है। चर्चा हो रही है कि खास तौर पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषयों पर इसकी सीमाएं सोची समझी रणनीति है या किसी तकनीकी खामी की वजह से ऐसा है। भारत-चीन युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर डीपसीक की सीमाएं एक बार फिर से उजागर हो गईं। हालांकि डीपसीक ने युद्ध की घटनाओं के बारे में जानकारी दी और बताया कि एकतरफा युद्धविराम के बाद यह युद्ध चीन ने जीता लेकिन चीनी चैटबाट ने गहरी पड़ताल वाले सवाल जैसे युद्ध के पीछे क्या कारण थे का जवाब देने से परहेज किया। इन जवाबों से यह पता चलता है कि जहां अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है, उन देशों में विकसित एआइ टेक्नोलाजी अपने देश या सरकार की नीतियों या उनके नरेटिव से प्रभावित हो सकती हैं।

डीपसीक का लोगो। रायटर

डीपसीक से भारत को खतरा नहीं

नई दिल्ली: चीन की डीपसीक के एआइ चैटबाट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि, तीन वर्ष पहले भारत को एआइ का वैश्विक केंद्र बनाने का एलान करने वाली भारत सरकार ने इस पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्र ने स्पष्ट किया है कि डीपसीक से भारत को कोई खतरा नहीं है और न ही इससे संवेदनशील डाटा चीन भेजे जाने का जोखिम है। (पेज-3)

केजरीवाल का जवाब, हरियाणा से आ रहे पानी को बताया जहरीला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

14 पृष्ठों के चुनाव आयोग को दिए जवाब में कहा, पानी में बढ़ी अमोनिया की मात्रा देख की थी टिप्पणी

आयोग उनके जवाब को आज देखेगा, उसके बाद लेगा कार्रवाई के बारे में फैसला

यमुना के पानी को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया। हालांकि उन्होंने अपने इस जवाब में भाजपा और हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर घोलने के अपने आरोपों का कोई प्रमाण नहीं दिया। न ही दिल्ली के लोगों के विरुद्ध छेड़े गए जैविक युद्ध से जुड़े आरोपों पर ही कोई सफाई दी। अपने 14 पृष्ठों के जवाब में केजरीवाल ने यह जरूर कहा कि हरियाणा से आ रहा यमुना का पानी जहरीला है। जिसमें आमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई है जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

चुनाव आयोग ने केजरीवाल का जवाब मिलने की पुष्टि की है और उनके जवाब को गुरुवार को देखने के बाद कोई फैसला लेने की बात कही। हालांकि केजरीवाल की सफाई से पहले दिल्ली जल बोर्ड ने आयोग को दी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस सीजन में हर वर्ष यमुना के पानी में अमोनिया का मात्रा बढ़ी हुई रहती है। यह कोई नई बात नहीं है। केजरीवाल के आरोप पर भाजपा ने आयोग से शिकायत की थी। (पेज-2 भी देखें)

****

3 और चार फरवरी को हो सकती है हल्की वर्षा, आज दिन में आसमान साफ रहेगा, शाम के समय छा सकते हैं बादल

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 30 जनवरी, 2025

आज का मौसम

सुबह स्मॉग और हल्की धुंध रहने के आसार हैं। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
30 जनवरी	26.0	10.0
31 जनवरी	25.0	10.0
नोएडा		
30 जनवरी	22.0	10.0
31 जनवरी	24.0	12.0
गुरुग्राम		
30 जनवरी	26.0	8.0
31 जनवरी	25.0	10.0

डिग्री सेल्सियस में

यमुना जी में डूबेगी आप की लुटिया : मोदी

चुनावी जनसभा ▶ मोदी ने केजरीवाल की तुलना ठग चार्ल्स शोभराज से की

कहा, दिल्ली में डबल आपदा लाने के लिए आप व कांग्रेस ने किया पर्दे के पीछे समझौता

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

नई दिल्ली के घोंडा में भाजपा द्वारा आयोजित विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। ध्रुव कुमार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखे प्रहार करने के साथ ही दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए दिल्लीवासियों से समर्थन मांगा। आप और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के लोगों से वादाखिलाफी कराने का आरोप लगाते हुए उनकी तुलना सीरियल किलर व ठग चार्ल्स शोभराज से की। उन्होंने हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने के केजरीवाल के आरोप को घिनौना बताया। कहा, यह पूरे देश और हमारे संस्कारों का अपमान है। ऐसी ओछी राजनीति करने वालों को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। आप की लुटिया यमुना जी में डूबेगी।

घोंडा में आयोजित विकसित संकल्प रैली में उन्होंने कहा कि तीन चुनावों में यमुना की सफाई पर आप-दा वालों ने वोट मांगे थे। अब बेशर्मी से कह रहे हैं कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलता है। यह दिल्ली को पानी के लिए तरसा रहे हैं। पूर्वांचलियों को गंदे पानी में छठ पूजा करने को विवश कर रहे हैं। आपदा वालों ने एक और पाप किया है। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हार की बौखलाहट में हरियाणा पर झूठा और घिनौना आरोप लगा दिया। हरियाणा दिल्ली से अलग नहीं है। उनके बच्चे व रिश्तेदार यहां रहते हैं। क्या वे अपने बच्चों को जहर वाला पानी पिलाएंगे? मैं यमुना का पानी पीता हूं, हरियाणा वाले मुझे जहर दे सकते हैं क्या? यहां के सभी न्यायाधीश, राजदूत, दिल्ली के सभी अमीर-गरीब हरियाणा का ही पानी पीते हैं। क्या इन सभी को हरियाणा ने जहर दे दिया?

भोला चेहरा बनाकर ठगने वाले से सावधान रहें : प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी के पास अपना घर नहीं है, लेकिन मोदी का सपना है कि हर गरीब का अपना पक्का मकान हो। ये शीशमहल बनाने वाले, उस पर जनता के करोड़ों रुपये लुटाने वाले, ऐश करने वाले, कभी गरीब के घर के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए ये आपदा वाले झुग्गियों में जाकर झूठी बातें फैला रहे हैं। ये लोग अपना चेहरा भोलाभाला बनाकर झूठ बोलते हैं। लोगों को ठगते हैं। जाना माना ठग चार्ल्स शोभराज भी ऐसा ही करता था। हर बार लोग गलती कर बैठते थे और हर बार फंस जाते थे। ऐसे लोगों से संभलकर रहना बहुत जरूरी होता है। गौरतलब है कि वियतनाम में जन्म लेने वाला चार्ल्स शोभराज सीरियल किलर, ठग व चोर है। कहा जाता है कि उसने 20 पर्यटकों की हत्या की थी। तिहाड़ सहित कई जेल से फरार हुआ था। नेपाल में 29 वर्षों की सजा के बाद उसे वर्ष 2022 में जेल से रिहा किया गया था।

आप ने विस का उपयोग गाली देने के लिए किया : पीएम ने कहा कि आप वालों को दिल्लीवासियों की चिंता नहीं है। विधानसभा का उपयोग लोगों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की जगह सिर्फ गाली-गलौज के लिए किया। पांच वर्ष सिर्फ 70-75 दिन विधानसभा में काम हुआ। 14 कानून पास हुए, इसमें से भी पांच उनके विधायकों के वेतन और सुविधाएं बढ़ाने के लिए थे। आपदा वाले शराब घोटाला, शीशमहल घोटाला, अस्पताल घोटाला उजागर होने के डर से कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं कर रहे हैं।

'परिवार के मुखिया की तरह दिल्ली की सेवा करूंगा

दिल्ली की बदहाली के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आप और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। कहा, 21वीं सदी के 15 वर्ष कांग्रेस व लगभग 11 वर्ष आप वालों ने बर्बाद कर दिए। विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली जरूरी है। विश्व में माडल शहर के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है। यहां यातायात जाम, टूटी सड़कें, गलियों में बहता सीवर का पानी, प्रदूषण, पानी के लिए हाहाकार सहित कई समस्याएं हैं। इस हालत से बाहर दिल्ली को निकालना है। 11 वर्षों से लंबित काम पूरा करने के साथ ही आगे के 25-30 वर्षों की तैयारी करनी है। दिल्लीवाले मोदी को सेवा करने का अवसर दें। परिवार के मुखिया की तरह दिल्ली की सेवा करूंगा। अपनी बुद्धि शक्ति सब कुछ सेवा में खपा दूंगा। उन्होंने कहा कि आप व कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे समझौता हो गया है, । वह डबल आपदा लाना चाहते हैं। इनसे बचकर रहना होगा।

...पीएम ने तीन बार छुए पड़पड़ गंज प्रत्याशी के पैर

यमुना खादर घोंडा में भाजपा द्वारा आयोजित विकसित दिल्ली संकल्प रैली में पड़पड़गंज से भाजपा प्रत्याशी रवि सिंह नेगी ने जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पैर छुए तो बदले में प्रधानमंत्री ने खुद झुककर नेगी के पैरों को तीन बार छू लिया। ध्रुव कुमार

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

करतार नगर पुश्ता पर यमुना खादर में भाजपा की विकसित दिल्ली संकल्प रैली में पटपड़गंज से भाजपा प्रत्याशी रवि नेगी का नाम पुकारा गया तो वह प्रधानमंत्री के पास आए और पैर छुए। अगले ही पल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीन बार रवि के पैर छू लिए। यह देखकर सब हतप्रभ थे। हालांकि रवि इसके बाद मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। रैली में मंच पर मौजूद लोगों की मानें तो प्रधानमंत्री पैर छुआना पसंद नहीं करते हैं। मंच पर आते ही किसी ने पैर छूने की कोशिश की थी तो प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद रवि नेगी ने पैर छुए तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने तीन बार उनके पैर छू लिए। पार्टी के लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री सबको बराबर मानते हैं। रवि नेगी पिछली बार भी पटपड़गंज विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे। वर्ष 2020 के चुनाव में उन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी।

न्यूज गैलरी

पंजाब सरकार लिखी कार में नगदी व बोतलें बरामद

नई दिल्ली : नई दिल्ली जिले के तिलक मार्ग थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम पुलिस ने एक कार जब्त की है। पंजाब नंबर प्लेट की कार में पंजाब सरकार लिखा हुआ था। पुलिस को कार के अंदर कई लाख रुपये नगद, शराब की बोतलें और आम आदमी पार्टी के पम्फलेट भी बरामद हुए हैं। तिलक मार्ग पुलिस मामला दर्ज कर कार मालिक और नकदी के बारे में पता कर रही है। नई दिल्ली के उपायुक्त के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 5:00 बजे तिलक मार्ग पुलिस इलाके में गश्त पर थी। तभी पंजाब नंबर प्लेट की एक संदिग्ध कार दिखाई पड़ी।। (राब्यू)

नरेश बाल्यान की कस्टडी पैरोल याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बाल्यान को हिरासत में पैरोल पर रिहा करने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि बाल्यान का मामला दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के मामले से अलग है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की राहत दी थी। न्यायाधीश ने कहा कि अगर बाल्यान चुनाव लड़ रहे होते, तो मामला अलग होता। अदालत ने बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 को तय की। (जासं)

चुनाव में अपमानजनक सामग्री का उपयोग न करें

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह तय करे कि राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी अपमानजनक सामग्री का उपयोग न करें। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने निर्देश पारित किया। याचिका तीन अधिवक्ताओं की ओर से दायर की गई थी, जिसमें चुनाव में दुर्भावनापूर्ण सामग्री प्रसारित करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। (जासं)

पूर्व सीएम के खिलाफ सोनीपत में केस, 17 को पेश होने का नोटिस

जागरण संवाददाता, सोनीपत : हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने वाले यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने संबंधी अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2-डी और 54 के तहत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध सोनीपत के सीजेएम नेहा गोयल की अदालत में केस दायर किया है।कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय करते हुए केजरीवाल को पेश होने का नोटिस जारी किया है।वाटर सर्विस डिविजन राई के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।

मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि उनके विरुद्ध क्रिमिनल धाराओं में भी केस दायर किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2-डी में आपदा को परिभाषित किया गया है, धारा 54 के तहत झूठी चेतावनी जारी करने पर सजा का प्रविधान है। ऐसे मामलों में झूठी अफवाह फैलाता है, तो एक साल तक जेल या जुर्माना हो सकते हैं।

केजरीवाल ने हरियाणा सीएम पर यमुना को लेकर लगाया ढोंग रचने का आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

यमुना के पानी को लेकर मंगलवार को भी राजनीति में उबाल बना रहा। भाजपा जहां इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं आप ने भी यमुना के पानी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर ढोंग रचने का आरोप लगाया है।

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सैनी के एक वीडियो को एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर करारा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि सैनी ने यमुना के पानी को पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी यमुना में थूक दिया। केजरीवाल ने कहा जब मैंने अमोनिया की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्लीवालों की जान के लिए खतरा होने की बात कही तो इन्होंने मुझ पर एफआइआर करने की धमकी दी। कहा कि जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं, जो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को विभिन्न स्थानों पर यमुना में प्रदूषण को स्थिति की जानकारी लेने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा, आप सरकार यमुना को साफ करने का वादा पूरा नहीं किया है। केजरीवाल नाकामी छिपाने के लिए यमुना नदी में जहर मिलाने का झूठ फैला रहे हैं। छठ के समय भाजपा ने उन्हें आइटीओ घाट पर यमुना की स्थिति देखने की चुनौती दी गई थी। लेकिन, स्वीकार नहीं की थी।

सोनीपत-दिल्ली सीमा के गांव दहिसरा में घाट पर यमुना जल का आचमन करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जागरण

कांग्रेस देगी नौकरी में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, कराएगी जाति जनगणना

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

▶ कांग्रेस ने घोषणा-पत्र में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों सभी का रखा ध्यान

▶ विधवा महिलाओं की बेटियों व अनाथ लड़कियों की शादी में 1.1 लाख का शगुन देने का वादा

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करते (बाएं से दाएं) प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव। जागरण

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में न सिर्फ महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और वंचित वर्ग सहित सभी को साधने का प्रयास किया गया है। इसमें जाति जनगणना कराने के अलावा सरकार बनने पर महिलाओं को नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही 2,500 रुपये का मासिक अनुदान देने। दिल्ली में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने के अलावा 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने सहित कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं।

बुधवार को 22 फोकस क्षेत्रों में विभाजित घोषणापत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने जारी किया। उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इसमें कहा है कि सरकार बनने पर ''हम राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही दिल्ली में विभिन्न वंचित वर्गों की गणना के लिए दिल्ली जाति सर्वेक्षण के लिए मंजूरी देंगे।'' इसके अलावा मुफ्त राशन किट के साथ ही पूर्वांचलियों के लिए अलग विभाग बनाए जाने और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और निराश्रितों के लिए 5,000 की पेंशन की घोषणा शामिल है। विधवा महिलाओं की बेटियों व अनाथ लड़कियों की शादी में 1.1 लाख का शगुन देने का वादा किया है। यमुना नदी को उसकी मूल स्थिति और प्रवाह में बहाल करने के लिए उसके दोनों किनारों पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। घोषणापत्र में ठोस अपशिष्ट और यमुना प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए हरित पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना भी शामिल है।

भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाएं एलजी : आतिशी

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के पानी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार का बचाव करने का आरोप लगाते हुए एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने पानी के मसले पर राजनीति करने पर की बात कह कर एलजी की निंदा की है। सीएम ने मांग की है कि एलजी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं या फिर पद छोड़ दें। सीएम आतिशी ने कहा कि एलजी साहब के पत्र में भी स्वीकार किया गया कि पानी में अमोनिया का स्तर तय सीमा से 700 फीसद ज्यादा है, फिर भी उन्होंने सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

सीएम ने कहा कि दिल्ली में पानी की गुणवत्ता का मुद्दा बार-बार आप सरकार और विधायकों ने उठाया है। केजरीवाल ने इस मामले में तब दखल दिया, जब दिल्ली के लोगों के लिए साफ पानी देने के हमारी मांग को नजरअंदाज किया गया। कहा कि अगर एलजी साहब को सच में दिल्ली की जनता की फिक्र होती, तो वह हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते और इस संकट को रोकते।

मुफ्त पानी और बिजली, बस यात्रा रहेगी जारी, 2500 रुपये पाएगी नारी : अनुराग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चांदनी चौक विधानसभा अंतर्गत मजनू का टीला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर मौजूदा योजनाओं को बिना बंद किए और बेहतर, प्रभावी और सुगम तरीके से लागू कर जनता को लाभ पहुंचाया जाएगा। निश्शुल्क पानी, बिजली व बस यात्रा जारी रहेगी। साथ ही महिला समृद्धि के तहत 2,500 रुपये प्रति माह के माध्यम से हम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण दिशा में प्रतिबद्ध हैं। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र महिलाओं, गरीब, युवा, झुग्गियों व्यापारियों से चर्चा कर तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि इसी तरह, मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और छह पोषण किट की सहायता उपलब्ध कराएंगे। आटो और टैक्सी चालकों के लिए आटो ड्राइवर कल्याण बोर्ड का गठन करने के साथ ही भाजपा उन्हें 10 लाख तक का जीवन बीमा और पांच लाख तक का दुर्घटना बीमा देने के साथ उनके बच्चों को भी स्कालरशिप देने जा रही है। सरकार बनने पर जरूरतमंद छात्रों को सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता, आवेदन शुल्क एवं यात्रा की लागत के लिए दो बार की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

चांदनी चौक में संबोधित करते अनुराग ठाकुर।

हिमंता, फडणवीस के साथ ही भजन लाल शर्मा समेत अन्य नेताओं ने मांगा वोट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: मध्य दिल्ली और नई दिल्ली क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का सघन प्रचार अभियान चला। असम के मुख्यमंत्री हेमन्त बिस्वा शर्मा ने करोलबाग से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मानकपुरा में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने विकास की राह पर वापस लाने का मन बना लिया है और वह दिल्ली को आप-दा के भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने नई दिल्ली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही रात्रि में पहाड़गंज स्थित महाराष्ट्र रंगायन में मराठी प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित किया। फडणवीस ने कहा की दिल्ली वाले भ्रष्टाचार की सरकार से तंग आ चुके हैं, आप को चुनने की गलती को सुधारकर दिल्ली में कमल खिला विकास की राह पकड़ेंगे। पटेल नगर से प्रत्याशी के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के भी जो प्रवासी दिल्ली में बसे हैं, वह दिल्ली की बदहाली को देखकर त्रस्त हैं।

लोगों को गंदा पानी पिलाते हैं, खुद पीकर दिखाएं केजरीवाल : राहुल

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली

▶ बवाना में जनसभा के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दी चुनौती, दागे सवाल

बवाना में चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जागरण

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बवाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पांच साल पहले केजरीवाल ने यमुना में स्नान करने और उसका पानी पीने का वादा किया था। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे अपना वादा पूरा करें और यमुना का पानी पीकर दिखाएं। राहुल गांधी ने कहा कि आप नेता शीशमहल में रहते हैं। साफ-सुथरा पानी पीते हैं और दिल्ली के लोगों के लिए झूठे बयान देते हैं। दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। कांग्रेस कभी भी ऐसे झूठे वादे नहीं करती है।

राहुल ने कहा, केजरीवाल ने कहा था कि मैं साफ-सुथरी राजनीति करूंगा, लेकिन आपने शराब घोटाला किया। आपने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली का हर नागरिक जानता है। आप ने जनता से झूठे वादे किए। राहुल ने कहा कि बवाना में पानी की समस्या है। लोगों को पेयजल नहीं मिलता है। यदि मिलता है तो वह गंदा होता है। लोगों को महंगा पानी खरीदना पड़ता है। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वे धर्म को धर्म से, जाति को जाति से और भाषा को भाषा से लड़ाते हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा और आप सरकार के रहते युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। लाखों रुपये खर्च करके युवा डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री लेते हैं। उन्हें सर्टिफिकेट तो मिलता है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है।

आप नेता ऐसी बातें करते हैं, मानो सीधे स्वर्ग से उतरे हों : मल्लिकार्जुन खरगे

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों 'एक ही सिक्के के दो पहलू' और 'झूठों के सरदार' हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा व आप पर कटाक्ष करते हुए दोनों को हरिश्चंद्र के दो बेटे भी बताया। खरगे ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा, 'ये बातें ऐसी करते हैं कि मानो सीधे स्वर्ग से उतरे हों।' बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खरगे ने शराब घोटाले का हवाला देते हुए कहा, 'अगर सब ठीक है तो (केजरीवाल) जेल क्यों गए, शराब घोटाले में क्यों पकड़े गए? आप दोनों (मोदी और केजरीवाल) हरिश्चंद्र के बेटों ने मिलकर हमें (सत्ता से) निकाला, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं किया।'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'भाजपा के लोग तो कहते हैं कि आजादी 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिली। 15 अगस्त, 1947 को देश को आजादी मिली, वो इसे नहीं मानते।'

सुरक्षित निकले

इमारत की पहली मंजिल पर रसोई में होने से परिवार की बची जान, गिरा लेंटर गैस सिलिंडर पर आकर रुक गया था, पति को हल्की खरोंच, पत्नी के पैर में फैक्चर, दो बच्चे सलामत, राहत-बचाव कार्य जारी, अभी और लोगों के दबे होने की आशंका

32 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकला परिवार, भावुक हुए लोग

मोहम्मद साकिब • जागरण

नई दिल्ली : जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। जितनी सांसें लिखी हैं, उतना तो आदमी जी ही जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस मलबे के ढेर में दबकर पांच लोगों की मौत हो गई। उसी मलबे से चार लोगों का एक परिवार सुरक्षित बाहर निकल आया। मरने वाले लोगों के लिए आंसू भी बह रहे थे। आंसू इस परिवार को भी जिंदा देखकर बहे, लेकिन ये खुशी और संतोष के थे। पति-पत्नी और उनके दो बच्चे मंगलवार की आधी रात को बचावकर्मियों की मेहनत से करीब 32 घंटे के बाद मलबे से बाहर निकाले गए। आनन-फानन में राजेश, पत्नी गंगोत्री, छह वर्षीय प्रिंस व दो वर्षीय ऋतिक को कैट्स एंबुलेंस की मदद से बुराड़ी अस्पताल भेजा गया। राजेश को मामूली खरोंचे आई है। वहीं उसकी पत्नी के पैर में फैक्चर है। उसे सिविल लाइंस स्थित ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है।

रेस्क्यू के बाद एम्बुलेंस में बैठे राजेश व दोनों बच्चे। जागरण

पुलिस को दिए बयान में राजेश ने बताया कि वह मूलरूप से यूपी के बांदा जिले के गांव कोटा कला, सिमोनी का रहने वाला है। करीब चार माह पहले ही काम की तलाश में वह दिल्ली के बुराड़ी में आया था। इमारत की पहली मंजिल पर वह अपनी पत्नी के साथ ईंटें ढोने का काम कर रहा था। इमारत की पहली मंजिल पर ही सभी लोग रहते थे। घटना वाले दिन उनकी रसोई का सिलिंडर खत्म हो गया था। शाम करीब साढ़े छह बजे वह गैस भरवाकर रसोई में पहुंचे ही थे, तभी इमारत भरभराकर गिर गई। गनीमत यह रही कि इमारत के जिस हिस्से में राजेश का परिवार मौजूद था, वहां लेंटर का एक बड़ा हिस्सा एलपीजी सिलिंडर पर आकर रुक गया। राजेश ने देखा कि सिलिंडर पर टिकने की वजह से वहां दो फीट की जगह बन गई थी। इसी जगह में उसका परिवार मौजूद था। किसी तरह राजेश ने 34 घंटे इसी मलबे के बीच रहकर अपने परिवार का हौसला बढ़ाया और उम्मीद नहीं खोई। बचाव दल जब उनके नजदीक पहुंचा तो उन्होंने बिजली के एक पतले पाइप से आवाज लगाकर संकेत भेजा। इत्तेफाक से फरिश्ता बनकर आए बचाव दल ने उसका संकेत सुन लिया और मलबा हटाते हुए परिवार को सकुशल निकाल लिया।

तीन टमाटर और थोड़ी गुड़ पट्टी से जीती जिंदगी की जंग

राजेश ने बताया कि इमारत गिरने के बाद वह गुफानुमा जगह में फंस गए थे, जहां अंधेरा था। पत्नी के पैर पर एलपीजी सिलिंडर और पूरी दीवार टिकी हुई थी और वह दर्द से कराह रही थी। दोनों बच्चे मां की हालत देख रो रहे थे। ऐसी हालत में उसने बच्चों को संभाला। उसका मोबाइल मलबे में दब गया था। बच्चे भूख से रोने लगे तो उन्हें जमीन पर पड़े तीन टमाटर और कुछ गुड़ पट्टी दिखी। बच्चों को जब प्यास लगती तब उन्हें टमाटर चटा देता था। भूख लगने पर गुड़ पट्टी खिला देता। 34 घंटे तक मलबे के ऊपर जेसीबी और क्रेन चलने की आवाज आ रही थी। आधी रात को यही गुहार बचावकर्मियों को सुनाई पड़ गई।

ताहिर हुसैन बोला, आप ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट से छह दिन की कस्टडी पैरोल मिलने पर बुधवार सुबह आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के प्रत्याशी व वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपित ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद पहुंचा। 50 से अधिक पुलिसकर्मियों के सुरक्षा घेरे में ताहिर जेल से सीधे मुस्तफाबाद कार्यालय पहुंचा और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ताहिर ने क्षेत्र में अपने बेटे शादाब हुसैन के साथ पदयात्रा की। लोगों ने उनसे हाथ मिलाना चाहा व फूलों की माला डालनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने किसी को करीब नहीं आने दिया।

आरोपित ताहिर हुसैन ने कहा कि पांच वर्षों तक जेल में रहने के बाद वह आम लोगों के बीच हैं। खुद को बेगुनाह कहते हुए नाइंसाफी का शिकार बताया। आरोप लगाया भाजपा, कांग्रेस व आप नफरत की राजनीति करती है। आप ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। नाम लिए बिना कहा दंगे में षड्यंत्र करके उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया।

मुस्तफाबाद में पुलिस की कस्टडी में पदयात्रा करते ताहिर हुसैन। जागरण

****

2014 -15 से 2023-24 तक 1,13,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत एथनाल मिश्रण करने से की गई है। इससे देश के पर्यावरण में 578 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिली है।

वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट बहुमत से स्वीकार

आगे बढ़ी प्रक्रिया ▶ आज लोकसभा सचिवालय को सौंपी जा सकती है जेपीसी की रिपोर्ट

सरकार बजट सत्र में विधेयक पास कराने का प्रयास करेगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वक्फ कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों के बहुमत से स्वीकार कर लिया गया है। संभावना है कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा सचिवालय को सौंप देगी और आगामी बजट सत्र में इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में जेपीसी द्वारा सुझाए गए 15 संशोधनों के साथ विधेयक को पास कराने की कोशिश करेगी।

जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट में विधेयक में सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा सुझाए गए 15 संशोधनों को शामिल किया गया है। इससे पहले विपक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधनों को बहुमत से खारिज कर दिया गया था। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए इसके खिलाफ अपनी राय दर्ज कराई। सूत्रों के अनुसार, विधेयक में किए गए 15 संशोधनों में से चार महत्वपूर्ण हैं। इनमें सबसे बड़ा संशोधन वक्फ संपत्ति के निर्धारण में कलक्टर की भूमिका को सीमित करना है। ध्यान देने योग्य बात है कि अगस्त में विधेयक के पेश किए जाने के समय विपक्ष ने कलक्टर को अत्यधिक अधिकार दिए जाने पर सवाल उठाए थे। जेपीसी की रिपोर्ट में कलक्टर की जगह कमीश्नर या सचिव जैसे वरिष्ठ अधिकारी को रखने का प्रस्ताव किया गया है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही जेपीसी ने वक्फ कानून को पूर्व की तारीख से लागू न करने की सिफारिश की है। इसमें शर्त यह है कि जमीन सरकारी न हो या उस पर पहले से विवाद न चल रहा हो। वहीं, रिपोर्ट में मुस्लिम समाज से जुड़े पंजीकृत बड़े ट्रस्ट को भी वक्फ कानून से बाहर रखा गया है और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम विद्वान को स्थान दिया गया है।

नई दिल्ली में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर बैठक के बाद परस्पर बातचीत करते संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य। प्रेट्र

अगस्त में मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने के समय से ही विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करता रहा है। जेपीसी की बैठक के दौरान भी यह विरोध देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी पर बैठक के दौरान पानी की बोतल तोड़ने और खुद को घायल करने के साथ ही अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने उन पर गाली देने तक का आरोप लगाया। जेपीसी की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद भी विपक्ष का विरोध जारी है। विपक्षी सदस्यों ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों के शामिल किए जाने को संविधान के अनुच्छेद 26 में मुस्लिमों को मिली धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया है। वहीं, सत्तापक्ष के सदस्यों ने विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को खारिज किए जाने को सही ठहराते हुए इसे वक्फ संशोधन कानून की मूल भावना को बचाने की कोशिश बताया। वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को दोनों सदनों में साधारण बहुमत की जरूरत पड़ेगी। राजग के सहयोगी दलों की एकजुटता से सरकार को इसे पास कराने में कोई समस्या नहीं आएगी।

सेना के लिए 10,000 करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली, एएनआइ : स्वदेशी हथियार प्रणालियों बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिनाका मल्टी-बैरल राकेट लांचर सिस्टम समेत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की गोला-बारूद खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को हुई बैठक में यह मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत सैन्य साजोसामान का निर्माण नागपुर की राकेट निर्माता कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज और पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआइएल) में किया जाएगा।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि पिनाका हथियार प्रणाली के लिए अनुबंध को सरकार द्वारा जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। डीआरडीओ पहले से ही पिनाका राकेट के 120 किलोमीटर का स्ट्राइक संस्करण बनाने के उन्नत चरणों में है। अगले वर्ष में इसका पहला परीक्षण किए जाने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बुधवार को मंजूर किए गए राकेटों की मारक क्षमता करीब 45 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर बहुत कारगर हो सकते हैं। यह स्वदेशी हथियार प्रणालियों की सबसे बड़ी सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। सेना इसका पूरा समर्थन कर रही है।

16,300 करोड़ रुपये के क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी

कैबिनेट के फैसले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ सरकारी व निजी कंपनियों को विदेश में बहुमूल्य खनिजों के खदान के अधिग्रहण के लिए मिलेगी मदद

▶ जुलाई, 2024 में आम बजट में की गई थी इस मिशन के गठन की घोषणा

केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटिंग आदि में बहुमूल्य धातुओं (क्रिटिकल मिनरल्स) की जरूरत को देखते हुए 16,300 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (एनसीसीएम) को मंजूरी दी है। इस मिशन के गठन की घोषणा जुलाई, 2024 में आम बजट में की गई थी। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिशन के गठन का फैसला किया गया, जिसका भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम योगदान हो सकता है। यह मिशन देश की सरकारी व निजी कंपनियों को बहुमूल्य धातुओं से संपन्न देशों में इनके खदानों को खरीदने या अधिग्रहण करने में आर्थिक व दूसरी मदद देगा।

कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनसीसीएम की अवधि वर्ष 2025 से वर्ष 2031 तक के लिए होगी। इसे खनन मंत्रालय लागू करेगा। 16,300 करोड़ रुपये में बजटीय योगदान 2,600 करोड़ रुपये का होगा, जबकि शेष राशि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां देंगी। सनद रहे कि सरकार ने पहले 24 तरह के खनिजों को क्रिटिकल मिनरल्स घोषित कर रखा है। इनमें ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, नाओबियम, गैलियम, कोबाल्ट, कैडिमियम जैसे खनिज हैं। इनमें से कुछ के भंडार भारत में हैं, जबकि कई सिर्फ विदेश में पाए जाते हैं।

कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रेट्र

पेरिस एआइ सम्मेलन की मोदी करेंगे मैक्रों के साथ अध्यक्षता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ एआइ के रेगुलेशन पर भारत की चिंताओं को फिर सामने रखेंगे पीएम

चीन की आइटी कंपनी डीपसीक ने जिस तरह से पूरी दुनिया को चौंकाया है, उससे अगले महीने पेरिस में होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की अहमियत बढ़ गई है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी हिस्सा लेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। माना जा रहा है कि मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के नियमन को लेकर भारत की चिंताओं को एक बार फिर सामने रखेंगे।

जानकारों का कहना है कि एआइ के खतरे और इससे जुड़ी नैतिकता पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की तरफ से उठाए जाने वाले सवालों को लेकर चीन की एआइ कंपनियां अभी तक खास तवज्जो नहीं देती थीं लेकिन डीपसीक की लांचिंग ने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। एआइ पर एक वैश्विक गवर्नेंस व्यवस्था बनाने को लेकर यह तीसरा सम्मेलन है। मई, 2024 में दूसरा

नरेंद्र मोदी। फाइल

सम्मेलन दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हुआ था जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। तब एआइ को लेकर एक गवर्नेंस व्यवस्था बनाने पर अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था। इस साल का सम्मेलन 10-11 फरवरी को होने वाला है जिसे एआइ को विकसित करने, निगमित करने को लेकर महत्वपूर्ण सम्मेलन बताया जा रहा है।

डीपसीक से भारत को कोई खतरा नहीं

जयप्रकाश रंजन • जागरण

▶ आइटी मंत्रालय के सूत्र ने कहा- संवेदनशील डाटा के चीन जाने का भी नहीं है कोई जोखिम

▶ डीपसीक को विकसित करने वाला भी एक स्टार्टअप, भारत में ऐसे 7,000 स्टार्टअप काम कर रहे

▶ दुनियाभर में एआइ पर काम करने वाली कंपनियों के लिए डीपसीक ने संभावनाओं के नए द्वार खोले

नई दिल्ली : चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीपसीक के एआइ चैटबाट ने पूरी दुनिया के प्रौद्योगिकी समुदाय को चौंका दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी कंपनियों के लिए चेतावनी बताया है। हालांकि, तीन वर्ष पहले भारत को एआइ का वैश्विक केंद्र बनाने का एलान करने वाली भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने स्पष्ट किया है कि डीपसीक से भारत को किसी प्रकार का खतरा नहीं है और न ही इससे भारत का संवेदनशील डाटा चीन भेजे जाने का कोई जोखिम है। साथ ही उन्होंने कहा कि एआइ में प्रतिस्पर्धा का दौर अभी शुरू हुआ है और यह कहना गलत होगा कि भारत पिछड़ गया है। संभव है कि भारत का कोई स्टार्टअप या एआइ पर काम करने वाली कंपनी डीपसीक से भी बेहतर और किफायती ओपन सोर्स प्लेटफार्म लांच कर दे। उम्मीद है कि गुरुवार को भारत सरकार की तरफ से डीपसीक के प्रभाव और भारत की तैयारियों को लेकर आधिकारिक बयान दिया जाएगा।

सूत्र ने कहा कि प्रौद्योगिकी के जिस क्षेत्र में यह प्रगति हो रही है, वहां भारत की शक्ति को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। डीपसीक को विकसित करने वाला भी एक स्टार्टअप है और इस तरह के 7,000 स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं। एआइ के अलावा मशीन लर्निंग, इंटरनेट आफ थिंग्स, ब्लाकचेन जैसे नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप्स को लेकर पूरी दुनिया में उत्सुकता है। हाल ही में दावोस (स्विट्जरलैंड) में आयोजित वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की बैठक में भारत को अमेरिका और चीन के साथ विश्व में प्रौद्योगिकी के तीन सबसे बड़े केंद्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।

सूत्र ने इस बात से पूरी तरह से इन्कार किया कि डीपसीक एक चीनी कंपनी होने के नाते भारत के लिए खतरा है।

सरकारी सूत्रों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी भारतीय कंपनियों ने भी डीपसीक का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इसने दुनिया भर में एआइ पर काम करने वाली कंपनियों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। भारत की एक प्रमुख एआइ कंपनी जीनानी डाट एआइ डाट के सीईओ गणेश गोपालन का कहना है कि डीपसीक की लांचिंग काफी हौसला बढ़ाने वाला कदम है। खासतौर पर जिस तरह से इसने लार्ज लैंग्वेज माडल (एलएलएम) आधारित कारोबार ढांचे को हिला कर रख दिया है। यह सोचा भी नहीं जा सकता है कि पचास लाख डालर से कम लागत पर एलएलएम आधारित सेवा को लांच किया जा सकता है और वह भी इतनी ज्यादा कुशलता के साथ। ऐसा लगता है कि अब किसी भी कंपनी के लिए एलएलएम प्लेटफार्म को लांच करना आसान हो गया है। जिस कीमत पर ओपनएआइ ने इसी तरह का प्लेटफार्म लांच किया था, उसके मुकाबले इसकी बेहद कम लागत बहुत मायने रखती है।

शीरा की खरीद कीमत में 1.69 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिलाने की योजना के लक्ष्य को घटाकर 2025-26 किया

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को अपनी बैठक में पेट्रोल में एथनाल मिलाने के लिए खरीदे जाने वाले शीरा (हैवी मोलासेस) के खरीद मूल्य को 56.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यह एक गाढ़ा द्रव है जो गन्ने के रस से चीनी बनाते समय सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। शीरा की दो श्रेणी है-सी और बी। खरीद कीमत सिर्फ सी श्रेणी शीरा की बढ़ाई गई है। बी श्रेणी की शीरा और गन्ने के रस, चीनी या सुगर सिरप की खरीद की कीमत क्रमशः 60.73 रुपये प्रति लीटर और 65.61 रुपये प्रति लीटर रहने दी गई है। यह कीमत 31 अक्टूबर, 2025 तक के लिए लागू है। इसके साथ ही सीसीईए ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिलाने की योजना के लक्ष्य को 2030-31 से घटाकर 2025-26 कर दिया है। अभी 18 प्रतिशत एथनाल का मिश्रण पेट्रोल में किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पिछले एथनाल सप्लाइ वर्ष में एथनाल की खरीद के लिए किसानों को 40 हजार करोड़ रुपये की अदायगी की गई है।

भावपूर्ण संगीत और प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ गणतंत्र दिवस समारोह

▶ बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान थिरकाने वाले संगीत ने वहां मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया

▶ भारत की संगीत व सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक कार्यक्रम है यह समारोह

नई दिल्ली, प्रेट्र : बुधवार को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान विजय चौक पर थिरकाने वाले संगीत और रायसीना हिल्स पर अस्ताचलगामी सूरज की मनमोहक पृष्ठभूमि ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में 'कदम कदम बढ़ाए जा' और 'ऐ वतन तेरे लिए' से लेकर 'गंगा जमुना' और 'भारत के जवान' समेत 30 गीत बजाए।समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड की 'कदम कदम बढ़ाए जा' धुन से हुई, जिसके बाद पाइप्स और ड्रम्स बैंड ने 'अमर भारती', 'इंद्रधनुष', 'जय जन्मभूमि' और 'वीर सियाचिन' जैसे कई मनमोहक गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन सदाबहार गीत 'सारे जहां से अच्छा' के साथ हुआ।

नई दिल्ली में बुधवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह में सैन्य बलों के बैंड ने भव्य प्रस्तुति दी। रायटर

समारोह के मुख्य संचालक कमांडर मनोज सेबेस्टियन थे। सेना बैंड के संचालक सूबेदार मेजर (मानद कप्तान) बिशन बहादुर थे, जबकि एम एंटनी (एमसीपीओ एमयूएस द्वितीय) और वारंट अधिकारी अशोक कुमार क्रमशः नौसेना और वायुसेना बैंड के संचालक थे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड के संचालक हेड कांस्टेबल जीडी महाजन कैलाश माधव राव थे।

'निज्जर हत्या में विदेशी हाथ होने का कोई पुख्ता सुबूत नहीं'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ कनाडा की समिति की रिपोर्ट ने ही ट्रूडो के आरोपों की फिर कलई खोली

▶ विदेश मंत्रालय ने कहा-भारत के मामलों में हस्तक्षेप करता है कनाडा

कनाडा की एक और एजेंसी ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेशी हस्तक्षेप पर कनाडा सरकार द्वारा गठित एक आयोग ने कहा है कि भारतीय एजेंसियों के संदेहास्पद संबंध को साबित करने के लिए कोई ठोस सुबूत नहीं है। यह आयोग सितंबर 2023 में ट्रूडो द्वारा न्यायाधीश मैरी-जोसी होग की अगुआई में गठित किया गया था ताकि कनाडा के चुनावों में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की स्थिति स्पष्ट हो सके। इस आयोग ने 28 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है।

इस रिपोर्ट में भारत को रूस, चीन, पाकिस्तान के साथ कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- 'हकीकत यह है कि कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करता रहा है। इससे वहां गैर कानूनी तौर पर लोगों

रणधीर जायसवाल। फाइल

के आने और संगठित अपराध करने का माहौल बना है। भारत के बारे में जो कहा गया है, हम उसे पूरी तरह से खारिज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गैरकानूनी प्रवास की व्यवस्था को आगे जारी नहीं रखा जाएगा।' यह पहली बार नहीं है जब भारतीय एजेंसियों पर कनाडा में हत्या कराने के गंभीर आरोपों को लेकर कोई ठोस सुबूत नहीं मिला है। ट्रूडो ने खुद भी एक सुनवाई में स्वीकार किया था कि जब आरोप लगाए गए थे, तब उनके पास कोई ठोस सुबूत नहीं थे।

पन्नू के संगठन एसएफजे पर पांच साल का प्रतिबंध जारी रहने की पुष्टि

▶ दिल्ली हाई कोर्ट के प्राधिकरण ने लिया फैसला

▶ मोदी और शाह को मारने की धमकी देने का आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली हाई कोर्ट के एक प्राधिकरण ने अमेरिका में बसे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खालिस्तान समर्थक अलगाववादी सिख संगठन (एसएफजे) पर लगे प्रतिबंध पर पांच साल के विस्तार की पुष्टि कर दी है। पन्नू के संगठन की आतंकी गतिविधियों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को जान से मारने की धमकी देना भी शामिल है।

जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता वाले दिल्ली हाई कोर्ट के प्राधिकरण का गठन दो अगस्त को किया गया था। ताकि एसएफजे को उसकी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए और पांच साल के प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। प्राधिकरण ने तीन जनवरी को एक आदेश जारी करके पांच साल के इस प्रतिबंध को जारी रखने की पुष्टि की है। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 10 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। सरकार ने बताया कि एसजेएफ देश के संवैधानिक पदों पर कार्यरत लोगों जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, मुख्यमंत्रियों और रा प्रमुख को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल 10 जुलाई को एसएफजे की भारत विरोधी गतिविधियों के लिए और पांच साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया था। इस खालिस्तान समर्थक सिख संगठन की भारत विरोधी गतिविधियां वर्ष 1967 से जारी हैं। बता दें कि पन्नू के खालिस्तान समर्थक अलगाववादी सिख संगठन एसएफजे भारत में होने वाली कुछेक वारदातों की अभी भी जिम्मेदारी लेता रहता है।

असर-2024 रिपोर्ट

बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों की स्थिति और भी खराब, बिहार के बच्चे गणित में बाकी राज्यों के बच्चों के मुकाबले कर रहे बेहतर प्रदर्शन

स्कूली बच्चों में अभी भी गणित का डर बरकरार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ आठवीं के 54, पांचवीं के 70 व तीसरी के 67% बच्चे नहीं कर पा रहे सवालों को हल

देश में स्कूली बच्चों के पढ़ने और गणित के सवाल हल करने की क्षमता में भले ही पहले के मुकाबले सुधार हुआ है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि अभी भी उनके भीतर से गणित का डर खत्म नहीं हुआ है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले 54 प्रतिशत से अधिक बच्चे अभी भी भाग के सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं। पांचवीं व तीसरी कक्षाओं की स्थिति और खराब है। पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 70 प्रतिशत बच्चे जहां अभी भाग से जुड़े सवाल नहीं कर पा रहे हैं, वहीं तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 67 प्रतिशत बच्चे दो अंकों की संख्या वाले घटाने के सवाल नहीं कर पा रहे हैं।

स्कूली बच्चों में गणित को लेकर बैठा यह डर हाल में प्रथम संस्था की असर (एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट)- 2024 रिपोर्ट से उजागर हुआ है। यह स्थिति तब है जब स्कूली बच्चों से गणित का डर दूर

प्रतीकात्मक

करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जिसमें इन्हें खेल-खेल में अंकों का ज्ञान कराने, जोड़-घटाना व भाग जैसे सवालों को हल करने की नए-नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही दसवीं और बारहवीं के स्तर पर बेसिक गणित और स्टैंडर्ड गणित जैसी दो श्रेणी भी बनाई हैं। इसमें बेसिक गणित में बच्चों से गणित के आसान सवाल पूछे जाते हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत पिछले वर्ष आई तीसरी और छठवीं कक्षाओं की गणित की पाठ्यपुस्तकों को अब और आसान बनाया गया है। माना जा रहा है कि इस पहल से आने वाले दिनों में गणित में बच्चों के प्रदर्शन में सुधार दिखेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, गणित में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन वैसे तो देशभर में दूसरे विषयों की तुलना में खराब ही है, लेकिन बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, गुजरात व असम जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां स्थिति और खराब है। इन राज्यों में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले 60 प्रतिशत से अधिक बच्चे भाग के सवाल हल नहीं कर पाते हैं। वहीं, जिन राज्यों के बच्चे गणित में बेहतर कर रहे हैं, उनमें बिहार के बच्चे सबसे अव्वल हैं। वहां आठवीं में पढ़ने वाले करीब 64 प्रतिशत बच्चे भाग से जुड़े सवाल आसानी से हल कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त मिजोरम, पंजाब, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बच्चे भी गणित में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

****

अंतरराष्ट्रीय युवा शेफ ओलंपियाड एक फरवरी से

नई दिल्ली, प्रेट्र : गोवा, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में 11वां अंतरराष्ट्रीय युवा शेफ ओलंपियाड (वाईसीओ) एक फरवरी से शुरू होगा। इस प्रतियोगिता में भारत, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और मिस्र समेत 50 देशों के युवा शेफ भाग लेंगे। प्रतियोगिता के विजेता को पांच हजार अमेरिकी डालर के नकद पुरस्कार के साथ ट्राफी दी जाएगी। इसका आयोजन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट (आइआइएचएम) द्वारा लंदन की इंटरनेशनल हास्पिटैलिटी काउंसिल (आइएचसी) के सहयोग से किया जाता है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर डेविड फास्केट होंगे। जबकि पद्मश्री शेफ संजीव कपूर मुख्य निर्णायक और संरक्षक होंगे। वहीं शेफ मंजूनाथ मुरल, शेफ जान वुड, शेफ मारियो परेरा, शेफ गैरी मैक्लीन और शेफ रणवीर बरार निर्णायक मंडल में शामिल होंगे।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

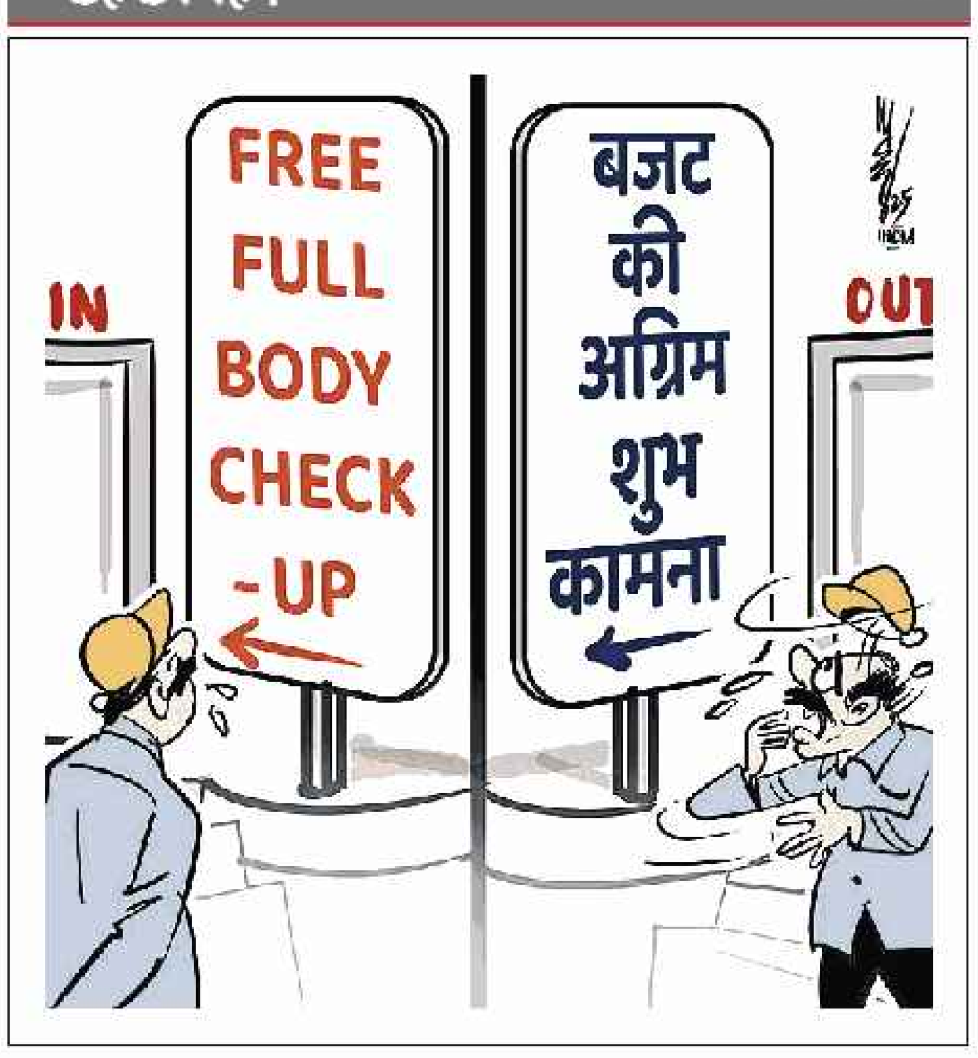

5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना (यूटीबी) प्रचार नहीं करेगी। यह जानकारी पार्टी के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 30 जनवरी, 2025

कांग्रेस-आप की भिड़ंत के बाद बजट सत्र में विपक्षी एकजुटता की होगी अग्निपरीक्षा

दिल्ली चुनाव में कांग्रेस व आप की सियासी जंग से बजट सत्र में विपक्षी एकता पर पड़ेगा असर

तृणमूल कांग्रेस का सियासी रुख पहले से ही कांग्रेस को करता रहा है परेशान

संजय मिश्र • जागरण

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच शुक्रवार से शुरू होने जा रहे संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की एकजुटता अंदरूनी मतभेदों की कसौटी पर रहेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच राजधानी दिल्ली के चुनावी अखाड़े में जिस तरह आमने-सामने की तीखी भिड़ंत का दौर चल रहा इसे देखते हुए विपक्षी दलों में संयुक्त रणनीति पर सहमति बन पाएगी इसे लेकर आशंकाओं के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस की अर्से से चलती रही सियासी खींचतान के बाद अब आप से बढ़ा टकराव साफ तौर पर संसद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ाएगा।

अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। फाइल

राजधानी के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस को भले ही आप और अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है। लेकिन संसद में ज्वलंत मुद्दों पर मोदी सरकार को बैकफुट पर रखने के लिए आइएनडीआइए के सभी घटकों का समर्थन अपरिहार्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए संसद के पहले कामकाजी सत्र में विपक्षी एकजुटता की वजह से सरकार जवाबदेही से जुड़े कई सवालों को नजरअंदाज नहीं कर पाई। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित पराजय के बाद विपक्षी गठबंधन की इस एकजुटता में दरार शीत सत्र के दौरान कई बार नजर आई।

तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) जैसे दलों ने अदाणी मुद्दे पर राजग-भाजपा सरकार को घेरने की कांग्रेस की आक्रामक रणनीति का एक सीमा के बाद साथ नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस ने तो विपक्ष का नेतृत्व करने के कांग्रेस की स्वाभाविक दावेदारी पर भी राजनीतिक बयानबाजी के जरिये सवाल उठाए थे।

वस्तुतः बीते शीत सत्र के मध्य में ही तृणमूल और सपा के साथ आप ने लगभग एक होकर विपक्ष की संसदीय रणनीति बदलने के लिए कांग्रेस को बाध्य कर दिया। वह तो संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबासाहब आंबेडकर से जुड़े बयान पर हुए सियासी संग्राम का नतीजा रहा कि विपक्षी खेमे की अंदरूनी खटपट यहीं ठहर गई। लेकिन आप नेताओं विशेषकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक निजी हमला बोला है। अजय माकन, संदीप दीक्षित, देवेंद्र यादव जैसे दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी केजरीवाल पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।

चुनाव अभियान में उतरे राहुल गांधी ने शराब घोटाले के भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह केजरीवाल पर बुधवार को एक बार फिर सीधे हमला बोला, इससे साफ है कि फिलहाल संसद में विपक्षी एकजुटता की रणनीति नहीं पार्टी की राजनीति कांग्रेस की प्राथमिकता में है।

संगठन में देशव्यापी बदलाव करेगी बहुजन समाज पार्टी, युवाओं को भी जोड़ेगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मायावती ने केंद्रीय पदाधिकारियों को दिया निर्देश, कैडर करें मजबूत
- कांग्रेस, भाजपा व सपा पर साधा निशाना-छल कर रहे जातिवादी दल

जिस अनुसूचित जाति के वोटबैंक के सहारे बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने यहां तक राजनीति का सफर तय किया है, उस वोटबैंक के लिए अब कई दलों में प्रतिस्पर्धा है। इसे लेकर बसपा प्रमुख मायावती चिंतित हैं। कभी सर्वजन तो कभी बहुजन को साधने की उलझन में दिखाई देने वालीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर सर्वजन के प्रति प्रेम तो दिखाया है, लेकिन केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर देशभर में संगठन में जरूरी बदलाव करते हुए कैडर को मजबूत करने और पार्टी से विशेष तौर पर युवाओं को जोड़ने का निर्देश दिया है। दलित वोटबैंक को अपनी ओर खींचने की होड़ में लगी कांग्रेस, भाजपा और सपा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि यह जातिवादी पार्टियां मुखौटा लगाकर छल की राजनीति कर रही हैं।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बुधवार को नई दिल्ली में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक बुलाई, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारी, स्टेट को-आर्डिनेटर और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। विभिन्न दलों में डा.भीमराव आंबेडकर के आदर-निरादर को लेकर

मायावती। फाइल

चल रही आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति के बीच बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि बसपा का संघर्ष देश के बहुजनों को शासक वर्ग बनाने का मिशन है, ताकि सर्वसमाज के गरीब, दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग, मुस्लिम व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के अन्य लोग अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान का जीवन जी सकें। यह अधिकार इन वर्गों को कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि पार्टियों की हुकूमत की नीयत व नीति में खोट होने के कारण अब तक नहीं मिल पाया है। एक बार फिर बहुजन से सर्वजन की ओर लौटते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि देश की तरक्की के लिए सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का होना जरूरी है। अपनी पार्टी को देश की एकमात्र सच्ची आंबेडकरवादी पार्टी बताते हुए संगठन की मजबूती और सर्वसमाज में बसपा के जनाधार को कैडर के आधार पर बढ़ाने के लिए संघर्ष का आह्वान किया। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) संगठन की तैयारियों व जनाधार को बढ़ाने के संबंध में दिए गए पिछले दिशा-निर्देशों पर प्रगति रिपोर्ट की अलग से राज्यवार समीक्षा की।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) संगठन में कुछ जरूरी फेरबदल करने के साथ ही नई पीढ़ी को पार्टी व मूवमेंट से जोड़ने के लिए युवाओं की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि बसपा कैडर आधारित पार्टी है, इसलिए इस मजबूत करें। 23 जनवरी को बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों की अलग से बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने अपनी कमियों को दूर करते हुए गुटबाजी छोड़ने की भी हिदायत पार्टी पदाधिकारियों को दी थी। उन्हीं के निर्देश पर प्रदेश संगठन में जो कुछ फेरबदल भी किए गए, उन्हें मंगलवार को मंजूरी दे दी गई।

फडणवीस कहेंगे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार : धनंजय मुंडे

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या फिर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कहेंगे तो वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। यह बयान बीड में हुई सरपंच की हत्या के मामले में विपक्ष द्वारा उनका नाम उछाले जाने के बाद आया है। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है।

अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के वरिष्ठ सदस्य मुंडे अपने गृह जिले बीड के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद से आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। उनके करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुंडे ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मानते हैं कि मैं दोषी हूं तो उन्हें मुझसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। यह उन्हें तय करना है कि मैं दोषी हूं या नहीं।

बीड जिले में एक ऊर्जा कंपनी से हो रही अवैध वसूली को रोकने पर सरपंच देशमुख का नौ दिसंबर को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

- महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, यह उन्हें तय करना है कि मैं दोषी हूं या नहीं
- सरपंच की हत्या के मामले में विपक्ष मांग रहा उनका इस्तीफा

अजीत को सौंपे सुबूत : मंत्री

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग तब फिर से उठने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने दावा किया कि उन्होंने उनके खिलाफ पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार को सुबूत सौंपे हैं। अजीत पवार ने अब तक अपनी पार्टी और कैबिनेट सहयोगी का पुरजोर समर्थन किया है। इससे पहले राकांपा (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा था कि मुंडे को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश भाजपा को मिलेगा अध्यक्ष

जागरण संवाददाता, शिमला : दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल भाजपा को नया अध्यक्ष मिलेगा। दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान व आठ को मतगणना होगी। इसके बाद भाजपा हिमाचल के अध्यक्ष पर निर्णय लेगी। वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल को फिर जिम्मेदारी देने के कयास लगाए जा रहे हैं। कांगड़ा से लोकसभा सदस्य डा. राजीव भारद्वाज व राज्यसभा सदस्य डा. सिकंदर कुमार के नाम भी चर्चा में हैं। बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल को नड्डा के करीबी होने का लाभ मिल सकता है। पार्टी के नेता जातीय व क्षेत्रीय समीकरण साधकर अध्यक्ष पर निर्णय लेंगे। पार्टी की ओर से अब तक विधायक सतपाल सत्ती का नाम भी चर्चा में है। सत्ती लंबे समय तक हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी में कांगड़ा जिला या जातीय समीकरणों को साधते हुए इस दिशा में काम करने की बात चल रही है। डा. बिंदल जनवरी 2020 में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए।

दिल्ली में साथ बैठे कश्मीर में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के दो केंद्र

नवीन नवाज • जागरण

- नेकां सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक से मुलाकात
- आगा शिया समुदाय के धार्मिक नेता तो मीरवाइज को है सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु की हैसियत

सैयद रुहुल्ला मेहदी। फाइल

मीरवाइज उमर फारूक। फाइल

जम्मू : एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) के वरिष्ठ नेता एवं सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने बुधवार को आल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली में हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में विभिन्न अटकलों ने जोर पकड़ लिया है क्योंकि यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब कई अलगाववादी नेताओं के प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से मुख्यधारा से जुड़ने और केंद्र सरकार के साथ उनकी पर्दे के पीछे बातचीत की कवायद जारी होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि कश्मीर में दोनों संगठनों की राजनीतिक विचारधारा सदैव एक-दूसरे से विपरीत रही है।

आगा रुहुल्ला और मीरवाइज उमर के बीच बैठक कश्मीर की स्थानीय राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगा रुहुल्ला शिया समुदाय के धार्मिक नेता हैं और मीरवाइज उमर सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा श्रीनगर में शेर-बकरा की लड़ाई बहुत पुरानी है। नेकां के समर्थकों को शेर और मीरवाइज के समर्थकों को बकरा कहा जाता रहा है। दोनों के बीच श्रीनगर में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर संघर्ष रहा है।

सूत्रों ने बताया कि यह मुलाकात नेकां व अवामी नेशनल कान्फ्रेंस के बीच राजनीतिक मतभेदों और मीरवाइज परिवार व अब्दुल्ला परिवार के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से अलग है। अवामी नेशनल कान्फ्रेंस का गठन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के पिता मीरवाइज फारूक अहमद ने किया था। मीरवाइज उमर अवामी नेशनल कान्फ्रेंस के साथ-साथ आल पार्टी हुर्रियत कान्फ्रेंस के उदारवादी गुट के चेयरमैन हैं। इसके अलावा वह जम्मू-कश्मीर में इस्लाम की विभिन्न विचारधाराओं और संप्रदायों से संबंधित संगठनों और उलेमा के साझा मंच यूनाइटेड मुत्तहिदा मजलिस ए उलेमा के भी चेयरमैन हैं।

मीरवाइज उमर बोले शिष्टाचार भेंट थी: आगा रुहुल्ला ने मीरवाइज उमर के साथ मुलाकात को लेकर कुछ भी कहने से इन्कार किया है, लेकिन मीरवाइज उमर ने कहा कि आगा रुहुल्ला हसन बड़गाम-श्रीनगर-गांदरबल संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं और वह हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। वह शिया समुदाय के एक बड़े धर्मगुरु भी हैं। हमारे बीच शिष्टाचार भेंट थी।

इन मुद्दों पर एक घंटे वार्ता : संबंधित सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच एक घंटे से भी ज्यादा समय तक बैठक हुई है। इसमें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर से संबंधित बहुआयामी मुद्दों, राज्य के दर्जे और राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने भारत में मुस्लिमों की सामाजिक-राजनीतिक व आर्थिक स्थिति, पांच अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में उपजे हालात, वक्फ संशोधन विधेयक सहित व्यापक चिंताओं पर चर्चा हुई। जम्मू-कश्मीर में युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और आरक्षण नीतियों पर चल रही बहस पर भी चर्चा की। आगा रुहुल्ला और मीरवाइज उमर के बीच मुलाकात के कई मायने हैं। दोनों की राजनीतिक विचारधारा सर्वथा एक-दूसरे से विपरीत है। इससे पहले भी कई बार अलगाववादी और मुख्यधारा के सियासी नेता जब किसी जगह अचानक आपस में मिलते थे तो वह उस मुलाकात को छिपाने का प्रयास करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है।

राष्ट्रीय फलक

बजरंग दल के बारे में जानकारी एकत्र करने पर गोवा में एसपी का तबादला

- विपक्षी कांग्रेस ने सुनीता सावंत के तबादले को राजनीति से प्रेरित बताया
- एक अधिकारी ने कहा, नियमित प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण

पणजी, प्रेट्र: पणजी: दक्षिण गोवा की पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुनीता सावंत का सोमवार देर रात अचानक तबादला कर दिया गया। उन्होंने सभी पुलिस थानों को बजरंग दल के पदाधिकारियों और सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक वायरलेस संदेश भेजा था। आमतौर पर एसपी स्तर के तबादले के आदेश राज्य सरकार जारी करती हैं, लेकिन इस मामले में गोवा पुलिस ने वायरलेस संदेश के जरिए ही सुनीता सावंत का तबादला कर दिया। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि एसपी सावंत को नियमित प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित किया गया है और और इसके लिए किसी मकसद को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उनके स्थान पर एंटी नारकोटिक्स सेल के एसपी टीकम सिंह वर्मा नियुक्त किया गया है।

विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसपी का अचानक और राजनीति से प्रेरित स्थानांतरण तब हुआ जब उन्होंने राज्य में बजरंग दल के नेताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू किया। इसमें यह भी कहा गया कि इस कदम से यह उजागर हुआ कि कैसे प्रशासन को आरएसएस-भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों के तबादले सरकार द्वारा किए जाते हैं। गौरतलब है कि बजरंग दल गोवा में सक्रिय है. इसने पिछले महीने दक्षिण गोवा के सनवोर्डेम गांव में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की थी, जिसे तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने संबोधित किया था।

घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए समिति गठित करे केंद्र : सुप्रीम कोर्ट

- शीर्ष कोर्ट ने घरेलू कामगारों के शोषण और दुर्व्यवहार पर चिंता व्यक्त की
- अक्सर कम वेतन, असुरक्षित माहौल और लंबे समय तक करते हैं काम

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह घरेलू कामगारों का शोषण रोकने और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करे। पीठ ने कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रभावी कानून नहीं है जो देशभर में लाखों घरेलू कामगारों को सुरक्षा प्रदान कर सके।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण नहीं होने के कारण उन्हें अक्सर कम वेतन, असुरक्षित माहौल और लंबे समय तक काम करना पड़ता है। शीर्ष कोर्ट ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ-साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे घरेलू कामगारों के अधिकारों के संरक्षण के वास्ते कानूनी ढांचे के लिए क्षेत्रीय

विशेषज्ञों की एक समिति का संयुक्त रूप से गठन करें।

पीठ ने कहा कि समिति का गठन केंद्र और संबंधित मंत्रालयों के विवेक पर छोड़ा गया है। यह सराहनीय होगा यदि समिति छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसके बाद भारत सरकार कानूनी ढांचा प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर विचार कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के बाद प्रगति की निगरानी की जाएगी।

यह आदेश डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक अजय मलिक के खिलाफ उनके घरेलू सहायक की गलत कैद और तस्करी के आरोप में दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज करते हुए दिया गया। न्यायालय ने उनके पड़ोसी अशोक कुमार के खिलाफ मामला रद करने के फैसले को भी बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि शहरीकरण के कारण घरेलू कामगारों की मांग बढ़ रही है। हालांकि, यह कार्यबल शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। घरेलू कामगार अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों से आते हैं और वित्तीय कठिनाई के कारण इस कार्य में लगे होते हैं।

हिमाचल को नहीं चाहिए नए कोटे में आइएएस, आइपीएस अधिकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • शिमला

- प्रदेश सरकार का केंद्र से अधिकारी लेने से इन्कार, अधिकारियों को कम कर खर्चों में हो सकती है कटौती

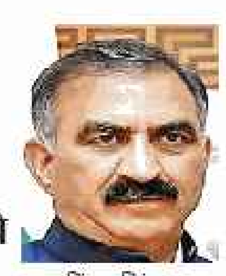

सुखविंदर सिंह।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने केंद्र से नए कोटे के तहत मिलने वाले आइएएस और आइपीएस अधिकारियों को लेने से इन्कार कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार का कार्मिक विभाग हर वर्ष प्रदेशों से उनकी आवश्यकता के अनुसार आइएएस और आइपीएस अधिकारियों की संख्या को पूछता है। इस मांग के आधार पर प्रदेश को अधिकारी दिए जाते हैं। इस बार भी ऐसी फाइल चली थी, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निरस्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी ऐसी पहल की थी, लेकिन अफसरशाही के दबाव एवं तत्कालीन हालात के चलते उन्हें निर्णय को पलटना पड़ा था। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसी दबाव की परवाह किए बिना यह निर्णय लिया है, जो अफसरशाही को अखर रहा है। राज्य पर इस समय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण हो चुका है। इस कारण सरकार नए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के साथ खर्चों में कटौती करना चाहती है। सरकार का मत है कि ऊपरी स्तर पर अधिकारी कम कर खर्चों में कटौती की जा सकती है। यानी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से बचा जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश ऋण लेने वाले राज्यों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। हिमाचल देश का पांचवां ऐसा राज्य है जो ऋण पर टिका है।

चेन्नई में द्रमुक का झंडा लगे वाहन ने महिलाओं का किया पीछा

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु के चेन्नई में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कार सवार कुछ लोग एक अन्य कार में सवार कुछ महिलाओं का पीछा करते एवं धमकाते नजर आ रहे हैं। कार पर सत्तारूढ़ द्रमुक का झंडा लगा हुआ है। इसमें सवार लोगों की तलाश की जा रही है। अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने कहा कि महिलाओं को डराने-धमकाने का वीडियो क्लिप चौंकाने वाला है। पूछा कि क्या रात के दौरान महिलाओं के घूमने के अधिकार को छीन लिया गया है। विपक्ष के नेता ने पूछा कि क्या सत्तारूढ़ द्रमुक का झंडा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने का लाइसेंस है। महिलाओं का तब तक पीछा किया गया जब तक वे अपने घर नहीं पहुंच गईं। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने उन्हें रात में बाहर जाने के लिए दोषी ठहराया। यह घटना दिखाती है कि द्रमुक सरकार में कानून और व्यवस्था की स्थिति की पूरी तरह बिगड़ गई है।

शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर 10 हजार करोड़ रुपये की ठगी

जागरण संवाददाता, जयपुर

- आठ वर्षों से एप के जरिए कर रहे थे लोगों को फंसाने का काम
- कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में की ठगी

राजस्थान में श्रीगंगानगर के ठगों ने शेयर बाजार में लाभ दिलाने का झांसा देकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों के लोगों से 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। करीब आठ साल से मोबाइल एप के जरिए लोगों को फंसाने का काम ठग कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में श्रीगंगानगर से पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 85 लाख की लग्जरी कार, 10 लाख नकद, छह मोबाइल फोन, तीन सीपीयू सहित अन्य सामान मिला है। पिता-पुत्र का सहयोग करने वाले चार फरार हैं।

पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि आरोपितों ने कैंपमोर एफएक्स नाम से एप बना रखा था। वे लोगों को शेयर बाजार में निवेश के तरीके सिखाते थे। लोगों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने

प्रतीकात्मक।

कर्नाटक और महाराष्ट्र के शहरों में सेमिनार भी आयोजित किया था। 15 से 20 दिनों के प्रशिक्षण के बदले 10 से 15 हजार रुपये पंजीकरण शुल्क वसूलते थे। इसके बाद एप के माध्यम से पहले छोटे निवेश कराते थे। फिर निवेशक को उसे मुनाफा के साथ राशि वापस करते थे। लोग मुनाफा देख बड़ी रकम निवेश करते और फिर उन्हें राशि वापस नहीं दी जाती थी।

कर्नाटक के कटप्पा निवासी बाबू चौहान ने साढ़े चार करोड़ की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने एक मोबाइल नंबर का उल्लेख भी किया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित कुछ ही दिनों बाद दुबई फरार होना चाहते थे। पिता-पुत्र लाजपत आर्य व दीपक के अतिरिक्त उनके साथ सौरभ चावला, सलानी, पंजाब के अबोहर के बरियामखेड़ा गांव निवासी बलजीत सिंह व कालिया निवासी कर्मजीत सिंह भी फर्जीवाड़े में शामिल हैं। पूरा फर्जीवाड़ा 10 हजार करोड़ का बताया जा रहा है।

राजनीतिक कारणों के आधार पर न करें अभियोजकों की नियुक्ति

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षपात और भाई-भतीजावाद के चलते योग्यता से समझौता न करें
- न्यायाधीशों से हो जाती हैं गलतियां, ऐसे में अभियोजक का कर्तव्य है कि अदालत को सुधारे

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाई कोर्ट में अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि ये राजनीतिक वजहों से नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि पक्षपात और भाई-भतीजावाद के चलते योग्यता से समझौता होता है। पीठ ने कहा कि न्यायाधीश भी इंसान होते हैं और उनसे गलतियां हो जाती है, ऐसे में अभियोजक की जिम्मेदारी इसे सुधारना होती है।

पीठ ने कहा, "न्यायाधीश भी इंसान हैं और कई बार गलतियां कर देते हैं। कई बार काम के दबाव के चलते ऐसा हो जाता है। उसी वक्त बचाव पक्ष और सरकारी अभियोजक का यह कर्तव्य है कि अगर अदालत कोई गलती कर रही है तो उसे सुधारें और हम इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। यह आदेश सभी राज्य सरकारों के लिए एक संदेश है कि उन्हें संबंधित हाई कोर्ट में एजीपी और एपीपी की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर करनी चाहिए।"

पीठ ने कहा, "यह अलग बात है कि हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की प्रार्थना को खारिज कर दिया। यह देश के हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों की स्थिति है। जब देश भर की राज्य सरकारें उनके हाई कोर्ट में सरकारी वकील की नियुक्ति केवल राजनीतिक कारणों से करती हैं, तब ऐसा होना तो तय ही है। राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वे व्यक्ति की कानून में दक्षता, पूरी पृष्ठभूमि और ईमानदारी समेत पूरी योग्यता का पता लगाएं।"

बंगाल में संगठन मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा संघ

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) बंगाल के जिलों में संगठन मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे की तारीख बदलकर सात फरवरी की जगह 11 फरवरी कर दी गई है। साथ ही दौरे की अवधि भी घटाकर सिर्फ चार दिन की गई है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोनह भागवत राज्य में शीर्ष पदाधिकारियों के साथ अतिरिक्त बैठकें करेंगे। ये बैठक बंगाल के दक्षिण के जिलों में संगठन की गतिविधियों पर केंद्रित होंगी। 13 फरवरी को भागवत बंगाल के नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। आरएसएस की बैठक में सामाजिक मुद्दों, शासन और राज्य में जनमत को आकार देने में आरएसएस की भूमिका से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

****

2456 घड़ियालहैं चंबलनदी में। इनमें 1211 वयस्क हैं। चंबल नदी को दुनिया के 75 प्रतिशत घड़ियालों का बसेरा माना जाता है।

न्यूज गैलरी

झारखंड में जवानों से मुठभेड़ में दो नक्सली ढेर

सोनुआ (पश्चिमी सिंहभूम) : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुवा थाना क्षेत्र स्थित विलायती टोला के समीप बुधवार की सुबह सुरक्षा बल के जवानों और जिला पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। इनमें एक महिला नक्सली हेमवती मझियान और दूसरे की पहचान संजय के तौर पर की गई है। घटना में कोबरा बटालियन का एक जवान अमन घायल हुआ है, जिसे बेहतर चिकित्सा के लिए रिम्स, रांची रेफर किया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को जल्द से जल्द सरेंडर करने की नसीहत दी है। (जासं)

राजस्थान के स्कूलों में तीन करोड़ ने एक साथ सूर्य नमस्कार

जयपुर : राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में तीन फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सुबह 10.15 बजे करीब डेढ़ करोड़ छात्र-छात्राएं व शिक्षक सूर्य नमस्कार कर विश्व रिकार्ड बनाएंगे। प्रदेश के शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इसके लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को संदेश भेज दिया गया है। बता दें कि पिछले वर्ष सूर्य सप्तमी के दिन प्रदेश की 78,974 स्कूलों के 1.33 करोड़ छात्र-छात्राओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया था। सूर्य नमस्कार के आयोजन में अभिभावक भी शामिल हो सकते हैं। (जासं)

बिहार रेरा ने तीन बिल्डरों के खिलाफ जारी किया वारंट

पटना : बिहार रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी) ने ग्राहकों को राशि न लौटाने वाले तीन बिल्डरों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इनमें ग्रह लक्ष्मी बिल्डकान, आदित्य यूनिक कंस्ट्रक्शन और पाटलीग्राम बिल्डर्स शामिल हैं। बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की अदालत ने इन बिल्डरों के विरुद्ध दायर वाद मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। यह आदेश बिल्डरों से लगभग 21 लाख रुपये की राशि वसूली के लिए दिया गया है, जिसे तीन पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है। (राब्यू)

चावल कारोबारियों के 25 ठिकानों पर आयकर छापा

रायपुर : करोड़ों रुपये की कर चोरी के मामले में आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को चावल कारोबारियों के छत्तीसगढ़ में रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, तिल्दा, महाराष्ट्र में गोंदिया, ओडिशा व आंध्र प्रदेश में काकीनाडा स्थित करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। टीम को अल्ग-अलग स्थानों से डेढ़ करोड़ रुपये नकद, 12 लाकर और ज्वेलरी भी मिले हैं। मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि चावल कारोबारियों ने शेल कंपनी बनाकर ब्रोकरों के माध्यम से विदेश में भी चावल का निर्यात किया। जानकारी के मुताबिक रायपुर में सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और साईं हनुमंत ग्रुप से जुड़े सड्डू स्थित राइस मिल के अलावा कई ब्रोकरों के यहां छापे की कार्रवाई की गई। इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 200 से अधिक अधिकारी शामिल हैं। (नईदुनिया)

दो ट्रेलरों में टक्कर के बाद आग लगी, चालक जिंदा जला

जयपुर : राजस्थान में अजमेर-किशनगढ़ राजमार्ग पर बुधवार शाम दो ट्रेलरों में हुई आमने-सामने टक्कर के बाद आग लग गई। इसमें एक ट्रेलर चालक जिंदा जल गया और दूसरे ट्रेलर के चालक और उसके साथी झुलस गए। दोनों को किशनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपाधीक्षक महिपाल सिंह ने बताया कि एक ट्रेलर किशनगढ़ से जयपुर की ओर जा रहा था, दूसरा जयपुर से किशनगढ़ की तरफ। हादसे से हाइवे की दोनों तरफ करीब आठ-आठ किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब चार घंटे के बाद यातायात सुचारू हो पाया। (जासं)

श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में इसरो का शतक, उपग्रह एनवीएस-02 कक्षा में स्थापित

सफलता ▶ एसएलवी-एफ15 राकेट से नेविगेशन सेटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने में सफलता

रक्षा, जल-थल-वायु नेविगेशन और वित्तीय लेनदेन के क्षेत्र में देश को मजबूती देगा 'नाविक'

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बुधवार को नेविगेशन एवं पोजिशनिंग सिस्टम वाले सेटेलाइट एनवीएस-02 को लेकर जीएसएलवी-एफ15 राकेट ने भरी उड़ान। प्रेट्र

"ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण पर इसरो को शुभकामनाएं। यह आश्चर्यजनक उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दूरदर्शिता, समर्पण और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। निजी क्षेत्र के साथ जुड़कर काम करने से भारत की अंतरिक्ष यात्रा नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी।"
– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

जेएनएन, नई दिल्ली: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अंतरिक्ष में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ ही अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का 'नाविक' रक्षा, जमीन-पानी और हवा में नेविगेशन समेत वित्तीय लेनदेन जैसे तमाम क्षेत्रों में मजबूती देगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 6.23 बजे जीएसएलवी-15 राकेट के जरिये इसरो ने नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम सेटेलाइट एनवीएस-02 लांच किया। भले ही इसरो ने यह मील का पत्थर छूने में 46 वर्ष लगा दिए हैं, लेकिन अब इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 100 नए सफल मिशन पूरे करने का है।

इस मौके पर इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, "बेहद प्रसन्नता हो रही है कि यह हमारे प्रक्षेपण केंद्र से 100वां लांच है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत दूरदर्शी विक्रम साराभाई ने की और फिर कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों ने इसे यहां पहुंचाया। हम छह पीढ़ी के लांच व्हीकल (प्रक्षेपण यान) विकसित कर चुके हैं। पहले यान का विकास 1979 में सतीश धवन के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम परियोजना निदेशक थे। तब से अब तक हम 100 प्रक्षेपण कर चुके हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताता हूं।"

एनवीएस-02 से भारत के रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम चार से बढ़कर पांच हो जाएंगे। नाविक (नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशन) भारत का स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है, जिसे भारत और भारतीय भूभाग से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्रों के यूजर्स के लिए सटीक पोजिशन, रफ्तार और समय बताने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम (एसपीएस) और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस (आरएस) जैसी दो तरह की सेवाएं देगा। अमेरिकी ग्लोबल पोजिशन सिस्टम (जीपीएस) की तुलना में इसकी सटीकता कमाल की है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह जीपीएस के 20 मीटर की बजाय 5 मीटर तक की सटीक पोजिशन के साथ 40 नैनोसेकेंड से भी सटीक समय देता है। इससे जमीन, हवा, पानी में सटीक पोजिशनिंग रक्षा क्षेत्र, नागरिकों और कंपनियों का काम आसान बना देगी।

इसरो ने 433 विदेशी सेटेलाइट अंतरिक्ष भेजे : इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि अब तक किए गए प्रक्षेपणों में 120 टन वजन के 548 सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इनमें 23 टन के 433 विदेशी सेटेलाइट भी हैं। इसरो प्रमुख ने बताया, "जीएसएलवी-एफ15 भारत के जियोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हीकल (जीएसएलवी) की 17वीं और स्वदेशी क्रायो स्टेज के साथ 11वीं यात्रा थी। इस मिशन के आंकड़े आ गए हैं और यान की सभी प्रणालियां आशानुरूप काम कर रही हैं। इसरो ने अपना अंतरिक्ष का सफर 1979 में सेटेलाइट लांच व्हीकल (एसएलवी) से शुरू किया था। इसरो का सबसे विश्वसनीय राकेट पीएसएलवी अब तक सर्वाधिक 62 मिशन पूरे कर चुका है।

गीतों से समृद्ध होता रंगमंच और भावविभोर श्रोता

हिंदी हैं हम

राधा-कृष्ण के प्रेम को गीतों में पिरोकर नाट्य प्रस्तुति पर चर्चा, बारीकियों पर गीतकार से बात

वीडियो देखने के लिए स्कैन करें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली, गीतकार प्रसून जोशी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जब वह फिल्मों के संवाद लिखते हैं या गीत या कविता में शब्दों को पिरोते हैं तो श्रोता झूम उठते हैं। फिल्म फना, रंग दे बसंती, तारे जमीं पर या ब्लैक में लिखे उनके गीत अब भी श्रोताओं की जुबान पर हैं। जब वह कविता लिखते हैं तो उनकी लेखनी से निकलता है ये देश नहीं झुकने दूंगा। विज्ञापन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम प्रसून जोशी को 'हिंदी हैं हम' के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। उत्तराखंड में उनका बचपन बीता और उस इलाके के शब्द किस तरह से उनकी कविताओं में साकार होते हैं या फिर जब वो राधा-कृष्ण के प्रेम पर म्यूजिकल ड्रामा की संरचना करते हैं तो किस तरह से दिल्ली और मुंबई में रंगमंच की दुनिया में अमिट छाप छोड़ते हैं। इन सब बातों की चर्चा यूट्यूब चैनल 'भाषा से जुड़िए' पर सुन सकते हैं।

विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी को दैनिक जागरण ने अपनी भाषा को समृद्ध करने के अभियान 'हिंदी हैं हम' के अंतर्गत एक नया आयाम आरंभ किया। अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वरों को मंच देने के लिए, भाषा से जुड़िए नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू हुआ जिस पर अब तक इतिहासकार विक्रम संपत, अभिनेत्री कंगना रनौत, राजनेता और सांसद जगदंबिका पाल, फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम, मयंक शेखर और प्रियंका सिन्हा झा को आप सुन चुके हैं। हिंदी हैं हम के इस चैनल पर आप साहित्यकारों, भाषाविदों, अभिनेताओं, इतिहासकारों, नाटककारों, राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों के साथ संवाद का आनंद उठा सकते हैं। दैनिक जागरण पिछले कई वर्ष से अपनी भाषा हिंदी को समृद्ध करने के लिए हिंदी हैं हम के नाम से एक अभियान चला रहा है। इसके अंतर्गत दैनिक जागरण हिंदी बेस्टसेलर, दैनिक जागरण वार्तालाप, दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति, दैनिक जागरण सृजन, दैनिक जागरण सान्निध्य और जागरण संवादी प्रमुख हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, तत्काल तीन तलाक में कितनी एफआइआर और चार्जशीट हुईं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मुस्लिम महिलाओं (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का उल्लंघन करके अपनी पत्नियों को तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देने वाले पुरुषों के विरुद्ध दर्ज एफआइआर एवं आरोप-पत्रों (चार्जशीट) के आंकड़े प्रस्तुत करे। अदालत ने कहा कि अब सभी राज्यों में एफआइआर केंद्रीयकृत हैं, हमें सिर्फ उसकी एक सूची दे दीजिए जिसमें ग्रामीण इलाकों के आंकड़े भी शामिल हों।

पीठ विभिन्न मुस्लिम व्यक्तियों एवं संगठनों की ओर से दायर करीब 12 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें 2019 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इस अधिनियम के तहत तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाया गया है। पीठ ने कहा कि पक्षकार भी अपने दावों के समर्थन में लिखित दलीलें दाखिल करेंगे जो तीन पृष्ठों से अधिक की नहीं होंगी। इसके बाद पीठ ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 17 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया।

कानूनी स्थिति का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि तत्काल तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था और विवाह समाप्त नहीं हो रहा था। अब मुद्दा तीन बार तलाक बोलने को अपराध बनाने का है। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी प्रथा नहीं है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता तत्काल तीन तलाक को वैध बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे अपराध बनाने का विरोध कर रहे हैं। मेहता ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि किसी भी गतिविधि को दंडात्मक बनाना विधायी नीति के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने इस दलील का विरोध किया कि यह अधिनियम असमान दंड लगाता है और कहा कि कानून के तहत अधिकतम सजा तीन वर्ष है जो महिला अधिकारों की रक्षा करने वाले अन्य कानूनों से कम है। उन्होंने पाकिस्तान की प्रख्यात शायरा परवीन शाकिर की पंक्तियों को उद्धत किया, 'तलाक तो दे रहे हो इताब-ओ-कहर के साथ, मेरी जवानी भी लौटा दो मेरी महर के साथ।'

प्रथा को दंडनीय बनाने वाले 2019 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया आदेश

शीर्ष कोर्ट ने कहा- मुद्दा प्रथा को दोबारा वैध बनाने का नहीं, बल्कि उसे अपराध बनाने का है

सड़क हादसे में मारे गए दंपती की बेटियों को एक करोड़ से अधिक मुआवजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना में एक दंपती की मौत के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उनकी बेटियों को एक करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देना बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोनों बेटियों की अपील का संज्ञान लिया और एस. विष्णु गंगा, एस सुधा महेश्वरी, ए एश्वर्या गंगा और एस सुधा रानी के माता-पिता की मौत पर उन्हें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की ओर से प्रत्येक के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना देना मंजूर किया है। 25 नवंबर, 2014 को ट्रिब्यूनल ने पिता के लिए 58,24,000 रुपये और माता के लिए 93,61,000 रुपये का मुआवजा देने को मंजूरी दी है। हालांकि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि में कटौती दर दी जिसपर मृतकों की बेटियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सीजीएमएससी घोटाले में मोक्षित कार्पोरेशन का डायरेक्टर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन (सीजीएमएससी) में 411 करोड़ के रिएजेंट (रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाला पदार्थ) व उपकरण खरीदी घोटाले में मोक्षित कार्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने यह कार्रवाई की है। आरोपित को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पूछताछ के लिए सात दिनों के रिमांड पर लिया गया है। उससे पूछताछ के बाद घोटाले में संलिप्त अधिकारियों सहित अन्य की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

सूत्रों का कहना है कि जांच टीम सीजीएमएससी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। शशांक चोपड़ा को दो दिनों से ईओडब्ल्यू कार्यालय बुलाकर पूछताछ की जा रही थी। ईओडब्ल्यू को मिले दस्तावेजों के अनुसार दुर्ग की कंपनी मोक्षित कार्पोरेशन दवा, मेडिकल उपकरण निर्माता व सप्लायर एजेंसी है। सीजीएमएससी को वह 2015 से उपकरण सप्लाई कर रही है। ईओडब्ल्यू ने सोमवार को मोक्षित कार्पोरेशन के रायपुर और दुर्ग स्थित फैक्ट्री व घरों में एक साथ छापा मारा था।

विधानसभा में भी उठा था मामला : मोक्षित कार्पोरेशन की रिएजेंट और मशीन आपूर्ति कराने में गड़बड़ी का मामला विधानसभा में भी उठा था। कंपनी के खिलाफ पांच वर्षों में 660 करोड़ रुपये से ज्यादा की गड़बड़ी का आरोप है।

आरोप है कि कंपनी ने मार्केट दर से सौ गुना ज्यादा में उपलब्ध कराने का काम किया है। जिन स्वास्थ्य केंद्रों में रिएजेंट संरक्षित कर रखने की जगह नहीं थी, वहां भी सप्लाई की गई। इसके चलते 20 करोड़ के रिएजेंट खराब हो गए।

- **दुर्ग की कंपनी पर 411 करोड़ के रिएजेंट सप्लाई में घोटाले का आरोप**
- **घोटाले में पंचकूला और रायपुर की अन्य कंपनियों पर भी केस दर्ज**

बंगाल में कक्षा में प्रथम वर्ष के छात्र ने प्रोफेसर को माला पहना भरी मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

बंगाल के नदिया जिले के हरिणघाटा स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के क्लास रूम में एक महिला प्रोफेसर की प्रथम वर्ष के छात्र ने माला पहनाकर मांग भर दी। महिला प्रोफेसर दुल्हन के वेश में थीं और छात्र दूल्हा बना था। प्रोफेसर एप्लाइड साइकोलाजी विभाग की प्रमुख हैं। क्लास रूम में मौजूद छात्रों ने प्रोफेसर और छात्र को माला पहनाने के दृश्य को मोबाइल में कैद किया। बुधवार को यह तस्वीरें-वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गईं। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि यह सब दिखावा था या वास्तविकता? विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष पायल बंद्योपाध्याय को छुट्टी पर भेज दिया गया है। प्रबंधन ने विभागाध्यक्ष से कक्षा में अपने व्यवहार के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। विभागाध्यक्ष ने मौखिक रूप से कहा कि यह एक साइको-ड्रामा प्रदर्शन था, वास्तविक नहीं था। दावा किया कि वीडियो इन-हाउस डाक्यूमेंटेशन के लिए बनाए गए थे। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पूरा मामला एक नाटक था। इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि यदि यह पूरा मामला नाटक था तो फिर विभागाध्यक्ष को छुट्टी पर क्यों भेजा गया? विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति तापस चक्रवर्ती ने कहा कि घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है।

नदिया के मौलाना अबुल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुई घटना, प्रबंधन ने जांच पैनल गठित किया

महिला प्रोफेसर की मांग सिंदूर भरता छात्र। इंटरनेट मीडिया

बरेलवी मौलाना का वक्फ संशोधन बिल को समर्थन

जागरण संवाददाता, बरेली : वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी का बरेलवी मौलाना ने समर्थन किया। बुधवार को आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी ने मसौदा तैयार कर लिया, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल से गरीब और जरूरतमंदों की मदद होगी, इसलिए समर्थन करना चाहिए।

बरेलवी मौलाना ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जमीन जायदाद इसलिए वक्फ को दी थी कि गरीब, कमजोर और लाचार लोगों की मदद होगी। इससे इतर, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने भूमाफिया से मिलकर करोड़ों रुपयों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। इस बिल के पास हो जाने पर वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसके साथ ही जिस मकसद के लिए जमीनें वक्फ को दी थीं, उस मकसद में होने वाली आमदनी खर्च होगी। इससे मुसलमानों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षिक स्थिति मजबूत होगी।

हड़ताली डाक्टरों की अनुपस्थिति को नियमित किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

आरजी कर केस

- **डाक्टरों के एक संगठन की दलीलों पर शीर्ष न्यायालय का फैसला**
- **कोर्ट ने दिल्ली एम्स सहित देशभर के अस्पतालों को दिया आदेश**

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में पिछले साल एक ट्रेनी डाक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में हड़ताल पर गए डाक्टरों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने नई दिल्ली स्थित एम्स सहित देश भर के सभी अस्पतालों से इस घटना के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान चिकित्सकों की अनुपस्थिति के संबंध में नियम तय करने को कहा है और आदेश दिया है कि हड़ताल अवधि के दौरान डाक्टरों की अनधिकृत अनुपस्थिति को नियमित करें। यानी उनकी गैर हाजिरी को हाजिर दिखाएं, न कि अनुपस्थित या छुट्टी पर दिखाएं।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी चिकित्सकों की अनुपस्थिति विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए, इसे मिसाल नहीं माना जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के समक्ष डाक्टरों के एक संगठन ने दलीलें दी थीं कि कुछ अस्पतालों ने 22 अगस्त, 2024 के आदेश के बाद डाक्टरों की अनुपस्थिति को नियमित कर दिया है, लेकिन दिल्ली एम्स समेत कई अन्य अस्पतालों ने हड़ताल की अवधि को गैरहाजिरी के साथ छुट्टी मानने का फैसला किया है।

इस पर सीजेआइ खन्ना ने कहा कि मामले में हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि अगर प्रदर्शनकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटे हैं तो उनकी अनुपस्थिति को नियमित माना जाएगा और उन्हें ड्यूटी से अनुपस्थिति नहीं माना जाएगा।

केरल में हत्या के आरोपित ने कहा, मुझे 100 साल की सजा दो

पलक्कड, आइएएनएस: केरल के पलक्कड की एक अदालत से बुधवार को तीन लोगों की हत्या के आरोपित 58 वर्षीय चैंथमारा ने 100 साल जेल की सजा देने की मांग की। यह बात उन्होंने तब कही जब पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। जैसे ही अदालत ने कार्यवाही शुरू की, चैंथमारा ने कहा कि मैं अपनी बेटी और उसके पति के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या उनके शरीर पर कोई चोट है तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई चोट नहीं है। कोर्ट ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चैंथमारा के चेहरे पर इस अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं दिख रहा है। अपने पड़ोसी सुधाकरन की पत्नी की हत्या के मामले में जमानत पर बाहर आए चैंथमारा ने मंगलवार को 54 वर्षीय सुधाकरन और 78 वर्षीय उनकी मां लक्ष्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी। सुधाकरन के बच्चों ने आरोपित को मौत की सजा देने की मांग की।

चिंताजनक

जलीय जीव गणना में चंबल नदी के घड़ियालों के लिंगानुपात में बड़ा अंतर आया सामने, शुरू हुआ शोध, 1211 वयस्क घड़ियालों में 1090 मादा और 121 नर, हैचिंग से भी निकल रहीं अधिकतर मादा घड़ियाल

चंबल में नर की तुलना में 10 गुना अधिक मादा घड़ियाल

हरिओम गौड़ • नईदुनिया

मुरैना : ताजा जलीय जीव गणना में चंबल नदी में घड़ियालों के लिंगानुपात में बड़ा अंतर सामने आया है। गणना में नर घड़ियालों की तुलना में मादा की संख्या लगभग 10 गुना अधिक पाई गई है। 1211 वयस्क घड़ियालों में 1090 मादा और सिर्फ 121 नर हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित घड़ियाल पालन केंद्र, देवरी में हैचिंग से जन्म ले रहे घड़ियालों में भी लिंगानुपात का इतना ही बड़ा अंतर है। मादा घड़ियालों की संख्या ज्यादा क्यों है और नर की संख्या किस तरह बढ़ाई जाए, इसके लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के विशेषज्ञों ने शोध शुरू किया है। इसके अलावा कई गैर सरकारी संगठन भी अध्ययन कर रहे हैं।

बता दें कि चंबल नदी को दुनिया के 75 प्रतिशत घड़ियालों का बसेरा माना जाता है। नदी में घड़ियालों की मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना के अलावा उत्तर प्रदेश के इटावा और आगरा में देखा जा सकता है। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अधिकारियों ने घड़ियाल संरक्षण परियोजना पर काम शुरू किया था। इस कारण चंबल में घड़ियालों का कुनबा बढ़ रहा है।

ताजा गणना के आंकड़े बताते हैं कि चंबल नदी में कुल 2456 घड़ियाल हैं। इनमें 1211 वयस्क हैं। दरअसल, घड़ियाल में लिंग की पुष्टि वयस्क होने पर ही होती है। वयस्क नर घड़ियाल के जबड़े के ऊपर घड़े की आकृति उभरी होती है, जो जन्म के करीब 13 वर्ष बाद बनती है। गणना के मुताबिक पालन केंद्र में अंडों से हैचिंग से निकले घड़ियालों में भी अधिकतर मादा ही हैं।

बीते पखवाड़े यहां से तीन साल की उम्र तक के 57 घड़ियाल चंबल नदी में छोड़े गए। इनमें 51 मादा थीं। केवल छह ही नर थे। केंद्र की केयर टेकर ज्योति डंडोतिया के अनुसार तीन साल से अधिक उम्र के घड़ियाल को पकड़कर और उनका परीक्षण कर लिंग निर्धारण किया गया। यह अंतर क्यों है, विशेषज्ञ शोध कर रहे हैं।

मुरैना के देवरी स्थित घड़ियाल पालन केंद्र में घड़ियाल। सौजन्य केंद्र

घड़ियालों का लिंग निर्धारण तापमान पर भी निर्भर करता है। स्थिर तापमान पर अंडे की हैचिंग कर नर या मादा का प्रजनन काफी हद तक सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि, यह लंबी व जटिल प्रक्रिया है।
– ऋषिकेश शर्मा, जलीय जीव विशेषज्ञ, मुरैना।

गुजरात में प्रबंधन की प्रताड़ना से परेशान होकर मेडिकल छात्रा ने दी जान

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात के मेहसाणा के होम्योपैथिक कालेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बुधवार को अपने हास्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। सुबह पिता को फोन कर उसने बताया था कि यहां अच्छा नहीं लग रहा है। साथी छात्राओं ने कालेज प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता तो वह बच सकती थी। छात्रा का नाम उर्वशी श्रीमाली है। इस घटना के बाद कालेज की छात्राओं ने तोड़फोड़ करने के साथ ही प्रदर्शन किया।

उनका आरोप है कि कालेज प्रबंधन के लोग घटना के बाद उर्वशी को अस्पताल न ले जाकर उससे पूछताछ करते रहे। मेडिकल कालेज में एंबुलेंस में आक्सीजन सिलेंडर नहीं था। अन्यथा उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि एक प्राध्यापक भी उर्वशी को लगातार परेशान कर रहा था।

फायरिंग करने के आरोपित चैंपियन के समर्थन में आए गुर्जर समाज के लोग

जागरण संवाददाता, रुड़की

- **हरिद्वार के लंढौरा में वेरीकेडिंग तोड़ रंगमहल पहुंची हजारों की भीड़, पुलिस के छूटे पसीने**
- **विधायक उमेश कुमार से माफी मांगने तथा चैंपियन पर जानलेवा हमले की धारा हटाने की मांग**

26 जनवरी को उत्तराखंड के खानपुर क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार के कार्यालय व आवास पर फायरिंग करने के आरोपित पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में गुर्जर समाज के लोग खुल कर आ गए हैं। दो दिन पूर्व ही नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि देवभूमि में बाहुबल प्रदर्शन शर्मनाक व अक्षम्य है। वहीं बुधवार को इस प्रकरण में आरोपित पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन के समर्थन में हजारों लोगों की भीड़ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर रंग महल तक पहुंच गई। इस मौके पर वीर गुर्जर समाज के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने हरिद्वार के खानपुर से विधायक उमेश कुमार से सार्वजनिक माफी मांगने और प्रणव चैंपियन पर दर्ज मुकदमे से जानलेवा हमले की धारा हटाने की मांग की।

बता दें कि इससे पहले गुर्जर समाज की ओर से लक्सर में महापंचायत का आयोजन करने की घोषणा की थी, लेकिन जेल से प्रणव चैंपियन का पत्र आने के बाद गुर्जर महापंचायत स्थगित कर दी गई थी। इसके बावजूद लंढौरा कस्बे में स्थित कुंवर प्रणव चैंपियन के रंगमहल में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पहुंच गए। इस मौके पर वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने कहा गुर्जर समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। रंगमहल गुर्जर समाज की आन है। गुर्जर समाज के नेताओं ने आरोप लगाया कि चैंपियन पर एक तरफा कार्रवाई की गई।

****

अमृत स्नान : संयम, सहयोग और अनुशासन का अप्रतिम उदाहरण

दोपहर तक श्रद्धालु, फिर सादगी से अखाड़ों ने किया स्नान, न भव्य शोभायात्रा निकाली, न बड़े-बड़े रथों का लंबा समूह

शरद द्विवेदी • जागरण

महाकुंभ नगर : अगाध भक्ति, हर्ष-उमंग और भावनाओं के उमड़े ज्वार के बीच अखाड़ों ने दूसरा अमृत स्नान किया। संतों के शंखनाद से समूची भावभूमि भक्ति में रम गई। सनातन के वैभव का गान करने वाले अखाड़ों ने अद्भुत संयम, सहयोग और अद्वितीय अनुशासन दिखा। स्वयं की परंपरा से ऊपर उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों की सुविधा की चिंता की। भगदड़ मचने के बाद उन्हें पहले स्नान कराया, जिसके बाद त्रिविधि ताप-पाप नाशिनी त्रिवेणी (संगम) के पवित्र जल में गोता लगाया। पहला मौका है, जब अखाड़ों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, संरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए अपने स्नान के समय में बदलाव किया। तप-तपस्या, साधु-साधना की धरा पर सुबह पांच बजे के बजाय 10 बजे के बाद स्नान किया। लंबे समूह के बजाय सादगी से स्नान करके समर्पित भाव से शिविर में लौटे।

श्री महानिर्वाणी व अटल अखाड़ा के संत धर्मध्वजा के साथ संगम तट पर पहुंचे तो उनका दर्शन पाकर हर कोई मंत्रमुग्ध हुआ। आराध्य को स्नान कराने के बाद जल में नागा संन्यासियों के साथ निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती, अटल अखाड़ा के आचार्य स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती, सचिव श्रीमहंत यमुना पुरी सहित सैकड़ों संतों ने सादगी से श्रद्धाभाव से ओतप्रोत होकर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद श्री निरंजनी व आनंद अखाड़ा के संतों का समूह संगम तट पहुंचा। आराध्य की पालकी को स्नान कराने के बाद भाला, त्रिशूल, तलवार लेकर अठखेलियां करते नागा संन्यासियों का अलौकिक दृश्य हर किसी के लिए अविस्मरणीय बन गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रवींद्र पुरी के नेतृत्व में ध्वजाओं के साथ नागा संतों व महामंडलेश्वरों ने स्नान किया। श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि, आनंद अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरि ने मां गंगा की स्तुति की।

प्रयागराज में बुधवार को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने उमड़े श्रद्धालु। एएफपी

नागा संन्यासियों की अद्भुत छटा : नागा संन्यासियों को अनुशासन की डोर में बांधने को अखाड़ा परिषद के महामंत्री व जूना अखाड़ा के संरक्षक महंत हरि गिरि सबसे आगे चल रहे थे। पीछे हजारों नागा संन्यासियों की फौज थी। किन्नर संन्यासियों का आभामंडल देखकर हर कोई भावविभोर हो गया। किन्नर संन्यासी जिनके सिर पर हाथ रखते उनकी अनंत भावनाएं आकार ले रही थी। हर्षातिरेक से नभ और धरा एकमय होने की अनुभूति हुई। संन्यासियों के बाद वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अनी, दिगंबर अनी और निर्वाणी अनी अखाड़ों ने स्नान किया।

संगम नोज पर भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने तक अखाड़ों से अमृत स्नान स्थगित करने का आग्रह किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रवींद्र पुरी ने इस पर सहमति जता दी और अपना संदेश प्रसारित कर श्रद्धालुओं से गंगा में ही स्नान का अनुरोध किया। स्थिति नियंत्रित होने के बाद अधिकारियों ने पुनःआग्रह किया कि वे अमृत स्नान करें। समय काफी बीत चला था फिर भी अखाड़े अपने निर्धारित मार्ग से संगम की ओर चल पड़े।

हमने श्रद्धालुओं की सुविधा को महत्व देते हुए पहले उन्हें स्नान कराया। बाद में सादगी से अखाड़ों का स्नान हुआ। अखाड़े आगे भी शासन-प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। -श्रीमहंत रवींद्र पुरी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद

अखाड़ा परिषद ने जो धैर्य दिखाया है, उसके लिए बड़ी प्रसन्नता है कि पहले समाज और भक्त, उसके बाद हम। यह भाव प्रेरणादायी है। -स्वामी चिदानंद सरस्वती (मुनि जी), अध्यक्ष, परमार्थ निकेतन आश्रम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रियता से पुलिस-प्रशासन ने जिस सक्रियता से राहत कार्य किया, वह सराहनीय है। -कैलाशानंद गिरि, आचार्य महामंडलेश्वर, निरंजनी अखाड़ा

मैंने दिवंगत आत्माओं के मोक्ष और घायलों के जल्द स्वस्थ्य होने की प्रार्थना के साथ संगम में स्नान किया है। महाकुंभ का अर्थ बहुत ऊंचा है। -स्वामी रामदेव, योगगुरु

मृतक और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए हमने अमृत स्नान सादगी से किया। स्नान में भीड़ लेकर नहीं गए। संतों ने सबके लिए प्रार्थना की है। -श्रीमहंत यमुना पुरी, सचिव, महानिर्वाणी अखाड़ा

शंकराचार्यों सहित प्रमुख संतों ने किया अमृत स्नान

जागरण संवाददाता, महाकुंभ नगर : मौनी अमावस्या हर कोई भक्तिभाव में रमा रहा। अमृत स्नान की पुण्य बेला में प्रमुख धर्मगुरुओं ने स्नान किया। शंकराचार्यों सहित प्रमुख संतों ने गंगा और संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। पुरी पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने गंगा में स्नान किया। श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी विधुशेखर भारती, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और जगदगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संगम में अमृत स्नान किया। इस दौरान श्रीधरानंद ब्रह्मचारी, मुकुंदानंद आदि मौजूद रहे। जगदगुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने शिष्यों और नागा संन्यासियों के साथ संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। जगदगुरु स्वामी महेशाश्रम, अखिल भारतीय दंडी संन्यासी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष स्वामी विमलदेव आश्रम, अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम के नेतृत्व में दंडी संन्यासी ने गंगा के पवित्र जल में स्नान करके जनकल्याण के लिए पूजन किया।

भजनों की गूंज और संकीर्तन ने गाढ़ा कर दिया आस्था का रंग

ज्ञानेंद्र सिंह • जागरण

महाकुंभ नगर : महाकुंभ के प्रमुख अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जनसागर ऐसा उमड़ा कि तीर्थराज के मुख्य मार्गों पर यातायात ठहर सा गया। पांटून पुलों पर मंगलवार आधी रात के बाद से ही स्नानार्थियों की कतार लगी थी। पांटून पुलों पर लंबी कतारें फाफामऊ से अरैल के बीच 12 किमी लंबे स्नान घाटों की ओर तिल-तिल कर बढ़ती-उतरती रहीं। दोपहर में पांटून पुलों पर यातायात रोके और छोड़े जाने से स्थिति असहज होने लगी। मंगलकामनाओं, मनौतियों और दान-पुण्य की परंपराओं के संगम में उल्लासित होकर श्रद्धालु हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कहीं भजनों की गूंज उठ रही थी तो कहीं संतों की टोलियां ढोल व डफली पर रामनाम का संकीर्तन कर आस्था के रंग को और गाढ़ा बना रही थीं।

ब्रह्म मुहूर्त में लगभग तीन बजे से घंटा-घड़ियाल और शंखनाद से मौनी के मौन कोलाहल का श्रीगणेश हो गया। तेजी से संगम समेत सभी 44 घाटों पर डुबकी लगने लगी। हर ओर आस्था के साथ उल्लास दिखाई दे रहा था। भोर में तीन बजे से लेकर पांच बजे तक लगभग डेढ़ करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। सुबह छह बजे के करीब धूप खिले तो सभी घाटों पर स्नानार्थियों की संख्या अचानक बढ़ गई। नौ बजे तक लगभग सवा दो करोड़ और साढ़े दस बजे यह संख्या 3.61 करोड़ पहुंच गई। दोपहर एक बजे के करीब यह संख्या 4.24 करोड़ पहुंच गई। ढाई बजे तक पांच करोड़ चार लाख और शाम 4.30 बजे तक पांच करोड़ 71 लाख संख्या हो गई। रात सात बजे तक सात करोड़ और रात आठ बजे तक सात करोड़ 64 लाख ने स्नान किया।

- भोर में ही डेढ़ करोड़ श्रद्धालुओं ने किया अमृतपान, धूप खिलने पर उमड़ पड़ी श्रद्धा

अयोध्या, काशी, चित्रकूट व विंध्यधाम में श्रद्धालुओं का रेला

जागरण टीम, लखनऊ

- अयोध्या, काशी, चित्रकूट और विंध्यधाम में श्रद्धालुओं का रेला
- भीड़ का दबाव कम करने के लिए उन्हें जगह-जगह रोका भी

प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ का रेला अब आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ रहा है। इस पलट प्रवाह का असर बुधवार को भी मौनी अमावस्या पर साफ दिखा। काशी, विंध्याचल, अयोध्या और चित्रकूट में श्रद्धालुओं का महासागर उमड़ पड़ा। ऐसे में धार्मिकस्थलों की ओर आ रहे श्रद्धालुओं का दबाव कम करने के लिए उन्हें जगह-जगह रोका भी गया। चित्रकूट से प्रयागराज जाने वाले मार्ग को तो बुधवार तड़के तीन बजे ही बंद कर दिया गया। इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी करीब 10 किमी लंबा जाम लग गया। 13 घंटे बाद शाम चार बजे प्रयागराज बार्डर खुलने पर चित्रकूट में फंसे करीब 30 हजार वाहनों को धीरे-धीरे रवाना किया गया। वहीं, दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर प्रयागराज होकर हावड़ा जाने वाली आधा दर्जन ट्रेन रद कर दी गईं। उधर, महोबा के बेलाताल स्टेशन पर मंगलवार रात मेला स्पेशल के कोच का गेट नहीं खुलने पर यात्रियों ने पथराव कर दिया।

चित्रकूट-प्रयागराज सीमा पर बरगढ़ में लगा जाम जागरण

मौनी अमावस्या पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय की अपील का खास प्रभाव नहीं देखा गया। सर्वाधिक भीड़ प्रयागराज हाईवे पर रही। महाकुंभ से लौटने वाले लोग विभिन्न वाहनों से अयोध्या पहुंच रहे थे, लेकिन इनको बीकापुर, कुमारगंज, रामसनेहीघाट में रोका जा रहा था। चार लाख से अधिक दर्शनार्थियों ने रामलला का दर्शन किया।

प्रयागराज की घटना को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर बनारस में गंगा स्नान व काशी विश्वनाथ धाम आने वाले भक्तों की भीड़ के नियंत्रण के लिए बाहरी जिलों व प्रदेशों के वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इससे वाराणसी की सड़कों पर काफी राहत रही। शाम तक लगभग चार लाख से अधिक लोगों ने बाबा विश्वनाथ का झांकी दर्शन कर लिया और लाखों की कतार बनी हुई थी। विंध्यधाम व संगम जाने वाले वाहनों को भी जगह-जगह रोक दिया गया, जिसके चलते श्रद्धालु कैंपों में ठहर गए। वहीं, महाकुंभ स्नान कर जब चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हुआ तो अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। आनन-फानन कई मार्गों को सील कर दिया गया। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के मुताबिक, 20 लाख श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी स्नान के साथ कामदगिरि की परिक्रमा लगाई है।

कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-दो पर 48 घंटे से महाजाम की स्थिति है। इससे उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के कैमूर, रोहतास तथा औरंगाबाद बुरी तरह प्रभावित हैं। प्रयागराज में जुटी भारी भीड़ के कारण यूपी प्रशासन ने बिहार के कैमूर से चंदौली (यूपी) में किसी भी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

महाकुंभ में भीड़ पर नियंत्रण में जुटा रेलवे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। इसके लिए ट्रेनों के शिड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। विभिन्न रूटों से प्रयागराज जाने वाली लगभग दो दर्जन नियमित ट्रेनों को रद कर दिया गया है। इसके बदले में कम दूरी की अत्यधिक ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। रेलवे की ओर से बताया गया कि प्रयागराज में भीड़ में कमी आने या स्थिर होने तक यह शिड्यूल जारी रहेगा। रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि रेलवे का सारा जोर अभी कुंभ स्थल से भीड़ को निकालने पर है। इसके लिए मौनी अमावस्या के दिन 360 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। भीड़ कम होने तक योजना के तहत ये ट्रेनें चलाई जाती रहेंगी। इसी योजना के तहत विभिन्न रूटों से प्रयागराज जाने वाली नियमित ट्रेनों को अगले दो-तीन दिनों तक स्थगित करते हुए कम दूरी की 170 से अधिक ट्रेनें चलाई गई हैं।

धार्मिक स्थानों पर भगदड़ में सैकड़ों गंवा चुके हैं जान

प्रयागराज में महाकुंभ के संगम क्षेत्र में मची भगदड़ में कई लोग हताहत हुए हैं। धार्मिक स्थलों पर भगदड़ और जानमाल के नुकसान की यह पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।

25 जनवरी, 2005: महाराष्ट्र के सतारा जिले के मंधारदेवी मंदिर में वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचले जाने से मौत हो गई थी। फिसलन भरी सीढ़ियों पर कुछ लोगों के गिरने के बाद यह दुर्घटना हुई थी।

30 सितंबर, 2008: राजस्थान के जोधपुर शहर के चामुंडा देवी मंदिर में बम की अफवाह से मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए थे और 60 से अधिक घायल हो गए।

3 अगस्त, 2008: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में पहाड़ों पर भूस्खलन की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 47 घायल हुए थे।

13 अक्टूबर, 2013: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ में 115 लोग मारे गए थे। भगदड़ इस अफवाह के कारण मची कि नदी पर बने जिस पुल को श्रद्धालु पार कर रहे हैं, वह ढहने वाला है।

14 जनवरी, 2011: केरल के इडुक्की जिले के सबरीमाला में पुल्मेडु में एक जीप घर लौट रहे लौट रहे तीर्थयात्रियों से टकरा गई, जिससे भगदड़ मच गई। घटना में कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए।

2 जुलाई, 2024: उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा द्वारा आयोजित सत्संग में भगदड़ मचने से महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक लोग मारे गए।

4 मार्च, 2010: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ में लगभग 63 लोग मारे गए थे। लोग मुफ्त कपड़े और भोजन लेने के लिए एकत्र हुए थे।

27 अगस्त, 2003: महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 140 घायल हो गए।

स्रोत: प्रेट्र

चिंतित मोदी बार-बार करते रहे योगी को फोन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- लगातार हालात जानते रहे पीएम, पहले एक घंटे में ही तीन बार किया फोन
- गृह मंत्री शाह ने भी लगातार बनाई रखी नजर, फोन कर ली जानकारी
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने भी हादसे पर जताया शोक

प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे के बाद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने समय रहते हालात को संभाल जरूर लिया, लेकिन इस दुर्घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित सरकार और संगठन का केंद्रीय नेतृत्व चिंतित और संवेदनशील दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार फोन पर बात की। पहले एक घंटे में ही तीन बार फोन कर जानकारी ली और सुझाव भी दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर पीड़ित श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त कीं।

सूत्रों के अनुसार, सुबह-सुबह ही पीएम ने योगी को फोन किया और दुर्घटना के कारण, श्रद्धालुओं की स्थिति सहित राहत एवं बचाव कार्य के संबंध में पूरा ब्योरा लिया। योगी ने उन्हें तब तक सामान्य हो चुके हालात के संबंध में बताया, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं को लेकर चिंतित प्रधानमंत्री थोड़ी-थोड़ी देर में फोन कर तब तक अपडेट लेते रहे, जब तक कि वह स्वयं स्थिति संभलने को लेकर आश्वस्त नहीं हो गए। इसके साथ ही एक्स पर पोस्ट लिखकर मोदी ने अपनी चिंता और संवेदनाओं को जाहिर किया। उन्होंने लिखा- ''प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं।''

नरेन्द्र मोदी। फाइल

गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहने की जानकारी साझा करते हुए एक्स पर लिखा- ''महाकुंभ में हुए दुःखद हादसे से अत्यंत व्यथित हूं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह दुःख सहने की शक्ति दें। प्रशासन घायलों को अस्पतालों में उपचार दे रहा है।'' केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहत व बचाव कार्य को लेकर गंभीरता जताई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है।

भगदड़ की घटना की होगी न्यायिक जांच

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

- मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित
- हादसे में जान गंवाने वालों के स्वजन को 25-25 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा

महाकुंभ में मंगलवार रात भगदड़ की घटना ने सुरक्षा-प्रबंधों को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है, जिसमें पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता व पूर्व आइएएस अधिकारी बीके सिंह बतौर सदस्य शामिल हैं। आयोग एक माह में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा। घटना की पुलिस जांच भी होगी। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के स्वजन को 25-25 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की है।

योगी ने कहा कि घटना एक सबक भी है। कई बार समीक्षा व स्थानीय स्तर पर सतर्कता बरते जाने के बाद भी ऐसे हादसे होते हैं और हुए हैं, सरकार ने इसकी तह तक जाने का निर्णय किया है। इसके दृष्टिगत ही न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले स्नान पर्वों पर और कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार गुरुवार को प्रयागराज जाएंगे। घटना के कारणों की पड़ताल भी करेंगे।

योगी आदित्यनाथ। फाइल

इन बिंदुओं पर होगी जांच

न्यायिक आयोग भगदड़ के कारणों के साथ ही उन परिस्थितियों की भी जांच करेगा, जो हादसे का कारण बनीं। भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके सुझाव भी देगा। राज्य सरकार को न्यायिक आयोग की जांच अवधि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

वरिष्ठ अधिकारियों संग सीएम पूरे दिन करते रहे बैठकें

संगम तट पर हुए हादसे के बाद योगी ने बुधवार सुबह चार बजे ही मुख्य सचिव, डीजीपी व प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरे दिन बैठकें चलती रहीं। मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम, मुख्य सचिव कंट्रोल रूम व डीजीपी मुख्यालय कंट्रोल रूम के माध्यम से मानिटरिंग भी की जाती रही। एक-एक घटना को लेकर प्रशासन, संतों व विभिन्न अखाड़ों से संवाद बनाए रखा गया।

सरकार के हस्तक्षेप से कम हुआ प्रयागराज का हवाई किराया

नई दिल्ली, प्रेट्र: महाकुंभ प्रयागराज में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जिसमें देश-विदेश से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। प्रयागराज तक आने के लिए विमानन कंपनियों के किराए आसमान छूने लगे हैं।

उड़ानों के लिए अत्यधिक हवाई किराए पर जारी चिंताओं के बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को एयरलाइंस को उचित कीमतें बनाए रखने के लिए कहा है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने प्रयागराज के लिए किराए में 30-50 प्रतिशत की कमी की है।

यह मामला तब सामने आया है जब उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि प्रयागराज की उड़ानों के लिए हवाई किराया बहुत ज्यादा है और उन्होंने विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए से कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया था।

विपक्ष ने वीआइपी मूवमेंट, कुप्रबंधन को बताया वजह

- महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष ने केंद्र-यूपी सरकार को घेरा
- श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंतजाम करने जरूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस दुखद हादसे की वजह कुप्रबंधन और प्रशासन का वीआइपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि वीआइपी संस्कृति पर लगाम लगानी चाहिए और महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को बेहतर इंतजाम करने चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि अधूरे इंतजाम, वीआइपी मूवमेंट, आत्म प्रचार पर ज्यादा ध्यान और कुप्रबंधन इसकी वजह हैं। हजारों करोड़ रुपये खर्च करके इस तरह की व्यवस्था निंदनीय है। अभी प्रमुख शाही स्नान बाकी है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को अभी से जागकर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, प्राथमिक उपचार और आने-जाने की व्यवस्थाएं बढ़ानी चाहिए और वीआइपी मूवमेंट पर

मल्लिकार्जुन खरगे

अखिलेश यादव

मायावती

लगाम लगानी चाहिए।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के हाथ से लेकर तुरंत सेना को सौंप देना चाहिए। इससे साधु-संतों और श्रद्धालुओं में फिर से भरोसा बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा करने वालों को तुरंत इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस हादसे को दुखद और चिंतित करने वाला बताया। वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरह की भारी भीड़ वाले आयोजन में अधिकतम योजना और सावधानी की जरूरत पर बल दिया।

शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाकुंभ के प्रबंधन में 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए, यह रकम कहां गई। भाजपा कुंभ के जरिये राजनीतिक प्रचार कर रही है। यह कुंभ की मार्केटिंग करके चुनाव जीतना चाहती है।

सीपीआइ(एम) ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''इतनी भारी रकम खर्च करने के बावजूद यह हादसा योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार के कुप्रबंधन को पूरी तरह उजागर करता है।''।

****

मौनी पर वीआइपी प्रोटोकाल नहीं

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ की घटना के बाद पीड़ितों की सहायता में जुटे पुलिसकर्मी व अन्य। प्रेट्र

प्रथम पृष्ठ से आगे

डीआइजी महाकुंभ ने बताया कि अमृत स्नान पर्व पर वीआइपी को प्रोटोकाल न देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पहले से कड़े निर्देश थे, जिसके क्रम में किसी वीआइपी का प्रोटोकाल अटेंड नहीं किया गया। इस हादसे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज किया है कि यह वीआइपी कल्चर की देन है।

किसी तरह की लापरवाही नहीं : डीआइजी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया था कि बैरिकेडिंग टूटी और श्रद्धालुओं पर भीड़ चढ़ती चली गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने हर स्तर पर सक्रियता बरती। वहीं, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा महाकुंभ में हुई दुर्घटना बेहद दुखद व पीड़ादायक है। यह समय किसी प्रकार के राजनीतिक दोषारोपण का नहीं, अपितु घायलों के उचित इलाज, मृतकों के स्वजन को संभाले रखने का है।

जागरण जनमन ने सुलझाई उलझन

क्या है किशोरों की नजर में एक अच्छा जीवन

लारेंज कोलबर्ग के सिद्धांत को आधार बनाकर 'दैनिक जागरण' द्वारा पूछे गए आठ प्रश्नों और उनके चार विकल्पों से भारत की नई किशोर पीढ़ी को समझने का जो प्रयास किया गया, उसमें यह बात मुख्य रूप से सामने आई कि हमारे किशोर उत्साही, विचारशील और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो सांस्कृतिक जड़ों के साथ प्रगतिशील विचारों को मिलाता है। किशोर भारत की क्षमता विशाल है, बशर्ते इस पीढ़ी को सही समर्थन और अवसर प्राप्त हों। भारत का यह सबसे बड़ा सर्वे बताता है कि भारतीय किशोर आधुनिकता, खुशी और आत्म-अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। वे आत्म-सुधार और शिक्षा को सशक्तीकरण और सफलता का साधन मानते हैं। आधुनिक जीवनशैली की ओर बढ़ते हुए वे नैतिकता और सह-अस्तित्व के रूप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को समान महत्व देते हैं। यह संतुलन प्रगति के साथ परंपरा को जोड़ने की उनकी मानसिकता को दिखाता है। वे भावनात्मक रूप से संवेदनशील हैं। खुशी, संतुष्टि और स्वतंत्रता उनकी मुख्य आकांक्षाएं हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती हैं।

भारत के सबसे बड़े सर्वे में किशोरों ने कहा कि आधुनिकता जरूरी है लेकिन परंपराओं की कीमत पर नहीं

प्रतीकात्मक चित्र

लड़कों को पैसे और प्रसिद्धि की चाह, मगर लड़कियों को चाहिए खुशी और संतुष्टि से भरा जीवन

खुश रहना है सबसे जरूरी

सर्वे के परिणाम यह दर्शाते हैं कि वर्तमान किशोर भावनात्मक संपन्नता को प्राथमिकता देते हैं और इनमें से अधिकांश भौतिक या करियर की सफलता की तुलना में खुशी और संतुष्टि को अधिक महत्व देते हैं। फिर भी, कुछ किशोरों के लिए धन, प्रसिद्धि और पेशेवर सफलता अभी भी महत्वपूर्ण हैं, जो सामाजिक मानदंडों, इंटरनेट मीडिया और पारंपरिक सफलता के संकेतों के प्रभाव को दर्शाते हैं। ये परिणाम व्यक्तिगत संतुष्टि को महत्व देने की ओर रुझान का संकेत देते हैं, लेकिन यह भी दिखाते हैं कि किशोरों की आकांक्षाएं बहुआयामी हैं, जिनमें भावनात्मक भलाई और आर्थिक उपलब्धियां दोनों शामिल हैं।

हम दोनों हैं अलग-अलग

किशोर सदस्यों में लड़के और लड़कियों के बीच सोच का दायरा काफी विस्तृत एवं विभिन्न मतों वाला था। जहां लड़के धन और सामाजिक सफलता की ओर आकर्षित नजर आते हैं, वहीं लड़कियां खुशी और संतुष्टि को महत्व देती हैं। लड़के आधुनिक जीवनशैली में रुचि लेते हैं, जबकि लड़कियां परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलित दृष्टिकोण का चयन करती हैं। इस सर्वे से यह भी सामने आया कि लड़कियां भावनात्मक और सामाजिक स्वतंत्रता (भय के बिना अभिव्यक्ति) पर जोर देती हैं, जबकि लड़के किसी तरह का चयन करने में अपनी मर्जी चलाने पर जोर देते हैं। लड़कियां सामाजिक परिवर्तन को महत्वपूर्ण मानती हैं, जबकि लड़के व्यक्तिगत सफलता (धन, प्रवास) को आगे बढ़ने की पहली आवश्यकता मानते हैं।

आध्यात्मिकता और निजी विश्वास

किशोर पारंपरिक धार्मिक ढांचों से हटकर व्यक्तिगत और आत्म-विश्लेषण को महत्व दे रहे हैं। सामूहिक धार्मिक पहचान भी कई किशोरों के जीवन में महत्वपूर्ण है। ये रुझान यह संकेत देते हैं कि भारत की यह नई पीढ़ी धर्म को बहुलवादी, लचीले और समावेशी तरीके से समझ रही है, जिसमें व्यक्तिगत आध्यात्मिकता को सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं के साथ संतुलित किया जा सकता है। वहीं हर तरह की चुनौतियों को दूर करने में हमारी यह नई पीढ़ी शिक्षा जैसे दीर्घकालिक और प्रणालीगत समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी उत्साहित और सक्रिय है!

50% ने माना कि स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी डर के स्वयं की अभिव्यक्ति।

58% शिक्षा को समाज की चुनौतियों को दूर करने का मानते हैं साधन।

59% किशोर जीवन के लक्ष्य के रूप में खुशहाल और संतुष्ट रहना चाहते हैं।

40% आध्यात्मिकता को मानते हैं सर्वोपरि धर्म

विस्तृत है सोच का दायरा

सर्वे में सामने आया कि औसतन आधे किशोर 'बिना किसी डर के खुद को व्यक्त करने' की इच्छा रखते हैं, जो एक पीढ़ीगत बदलाव है। झारखंड और दिल्ली/एनसीआर में इस ओर अधिक रुझान दिखा। वहीं, हरियाणा व उत्तराखंड जैसे राज्यों के प्रतिभागी स्वतंत्रता के साथ 'जिम्मेदारी' पर अधिक जोर देते हैं। अधिकांश किशोर (59%) आर्थिक आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हैं। झारखंड को छोड़कर अधिकांश राज्यों से मिले प्रत्युत्तर में सामने आया कि वे जानकारी जुटाने और वैश्विक संपर्क के लिए इंटरनेट मीडिया का उपयोग करते हैं। एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट मीडिया को सीखने और नेटवर्किंग प्लेटफार्म के रूप में देखता है। ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी सिर्फ डिजिटल दुनिया में जी रही है, कई किशोर धर्म को आध्यात्मिकता या व्यक्तिगत विश्वास के रूप में मानते हैं। सामुदायिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह एक छोटे हिस्से (लगभग 20-30%) में ही सीमित है। जब उनसे समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़े समाधान के तरीके के बारे में पूछा जाता है तो अधिकांश क्षेत्रों के लिए हमारी जागरूक किशोर पीढ़ी शिक्षा को समाधान का सबसे बड़ा हथियार मानती है।

स्वतंत्रता की कई परिभाषाएं

स्वतंत्रता के मामले में किशोरों की समझ विस्तृत है। वे मानते हैं कि स्वतंत्रता जिम्मेदारी और सामाजिक प्रभावों की समझ के साथ जुड़ी होनी चाहिए। यह दर्शाता है कि किशोर केवल व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्वतंत्रता के साथ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी विचार कर रहे हैं। ये निष्कर्ष एक ऐसी पीढ़ी को दर्शाते हैं जो व्यक्तिगत स्वायत्तता को सामुदायिक और वैश्विक प्रभावों के साथ संतुलित करना चाहती है। स्पष्ट होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य किशोरों की समाज के प्रति दृष्टि को विकसित करने, नैतिक निर्णयों को प्रभावित करने, समावेशिता को प्रोत्साहित करने और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, ये मूल्य कभी-कभी उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाले लग सकते हैं, विशेषकर जब वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म-अभिव्यक्ति की चाह के साथ टकराते हैं।

बड़ी चुनौती हैं सामाजिक गतिरोध

जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता का सामना किशोर आज भी करते हैं। भारत में सामाजिक असमानता की जटिलता को उजागर करते हुए, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव भी किशोरों के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। हालांकि, अच्छी बात यह है कि ये किशोर गतिरोध के इस पाखंड के प्रति जागरूक हैं और इन सामाजिक गतिरोधों को चुनौती देने के लिए तत्पर हैं, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए सकारात्मक परिवर्तन की संभावना बढ़ती है।

खुल गईं विचारों की परतें

कई प्रतिभागियों ने माना कि बदलते समाज के साथ तालमेल बिठाने के लिए वे आधुनिकता को अपनाएंगे, वहीं कुछ पारंपरिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ किशोर स्थिति के अनुसार आधुनिक और पारंपरिक दोनों मूल्यों का संतुलन बनाने में सहज हैं। यह सर्वे एक ऐसी पीढ़ी को दर्शाता है जो अनुकूलनशील, आत्म-निर्धारित और परंपरा व आधुनिकता के बीच की जटिलताओं को समझती है।

प्रस्तुति : मनीष त्रिपाठी/ आरती तिवारी

डिजिटल ज्ञान, सामाजिक पहचान

भारत में अधिसंख्य किशोर इंटरनेट मीडिया को एक ऐसा माध्यम मान रहे हैं, जहां वे सीख सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी डिजिटल पहचान के जरिए सामाजिक मान्यता भी पाना चाह रहे हैं। भारतीय किशोर अब शिक्षा और सामाजिक जुड़ाव के लिए अधिक डिजिटल दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। यह बदलाव उनके भावी सामाजिक व्यवहार, करियर के विकल्पों और राजनीतिक विचारों पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि वे आभासी और संवादात्मक तरीकों से दुनिया के साथ जुड़ते रहेंगे। सामाजिक मान्यता और मनोरंजन की खोज किशोरों के आनलाइन जीवन के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं को उजागर करती है, जिससे शिक्षकों, माता-पिता और नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे सामाजिक मंचों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करें।

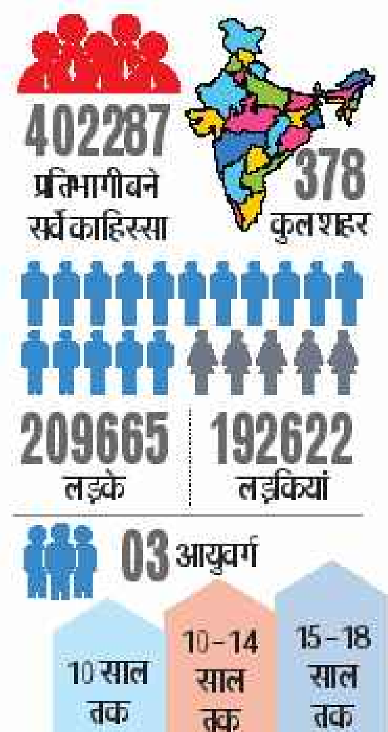

महिला की नाक व जीभ काटने वाले दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में जैसलमेर जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) ने दूसरे विवाह से इन्कार करने पर महिला की जीभ व नाक काटने वाले एक दर्जन दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। 14-14 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

मामला 17 नवंबर 2020 का है। जैसलमेर के सांकडा निवासी बशीर खान ने शिकायत दी थी कि उनकी बहन गुड्डी की शादी 2014 में कोजे खान से हुई थी। कोजे खान की 2015 में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग गुड्डी की शादी पति के छोटे भाई से करना चाहते थे। गुड्डी इन्कार पर ससुरान पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रताड़ना से परेशान होकर 2016 में वह मायके आकर रहने लगी। 17 नवंबर 2020 को ससुराल पक्ष के एक दर्जन लोग तलवार, लोहे के सरिये और लाठियां लेकर पहुंचे और गुड्डी पर हमला कर दिया। उन्होंने तलवार से गुड्डी की नाक व जीभ काट दी। पुलिस ने जांच के बाद एक दर्जन लोगों को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया था। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने बुधवार को सजा सुनाई है।

चार पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद भी शीतकालीन वर्षा में कमी चिंताजनक

जागरण संवाददाता, चंपावत

- चंपावत, पिथौरागढ समेत 11 जिलों में सामान्य से 70 प्रतिशत से कम वर्षा
- सर्दी के सीजन में वर्षा गेहूं, सरसों, मसूर की फसल के लिए होती है अच्छी

जनवरी की शुरुआत में मौसम बदला था। पहले सप्ताह में ही अच्छी वर्षा व हिमपात देखने को मिला। उसके बाद तीन पश्चिमी विक्षोभ आए लेकिन वर्षा व हिमपात के मामले में खास गतिविधि दिखी नहीं। इसका नतीजा हुआ शीतकालीन वर्षा में कमी आ गई। जनवरी बीतने को है और प्रदेश में सामान्य से 86 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।

मौसम विभाग जनवरी व फरवरी को शीतकालीन अवधि में रखता है। सात व आठ जनवरी को पहला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली। उसके बाद नियमित अंतराल पर तीन पश्चिमी विक्षोभ आए लेकिन उच्च हिमालय को छोड़कर निचले क्षेत्रों में वर्षा की खास गतिविधि नहीं दिखी। जिसकी वजह से वर्षा में कमी देखी गई है। एक से 29 जनवरी तक प्रदेश में 39.7 मिमी के सापेक्ष 5.4 मिमी वर्षा हुई है। हरिद्वार में सबसे कम अंतर है। नैनीताल में भी दूसरे जिलों की अपेक्षा थोड़ी बेहतर स्थिति है। चंपावत, पिथौरागढ़ समेत 11 जिलों में

चेन्नई में बुधवार सुबह एक व्यक्ति धुंधभरी सुबह में मोटरसाइकिल चलाता हुआ। एपी

सामान्य से 70 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। फरवरी में कितनी वर्षा होगी कहा नहीं जा सकता। ऐसे में शीतकालीन वर्षा में कमी सब्जियों व रबी की फसलों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। खासकर पर्वतीय असिंचित क्षेत्र में गेहूं, मसूर, सरसों आदि के लिए वर्षा की जरूरत होती है। चंपावत के मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार बताते हैं कि यह समय रबी की फसलों के बढ़वार का रहता है। जनवरी-फरवरी में अच्छी वर्षा मिलने से फसलों की ग्रोथ अच्छी रहती है। आगे वर्षा नहीं हुई तो फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

फरवरी के पहले सप्ताह से बदलेगा मौसम

उत्तराखंड के कई हिस्सों में धूप कमजोर पड़ने से दिन के तापमान में कमी आई है। अगले दो दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने वाला है। एक फरवरी को आंशिक बादल छाएंगे। हिमाचल में भी मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी और पहली फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ अधिक सक्रिय होगा। इसके चलते प्रदेश में कई जगहों पर हिमपात और वर्षा होने की संभावना है। पंजाब में बीते तीन दिनों से सामान्य तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार अगले तीन दिन राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है।

सैफ मामले में अदालत ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

मुंबई, प्रेट्र : बालीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को यहां की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने पाया कि उसकी पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए कोई नया आधार नहीं है।

बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस द्वारा आगे की हिरासत की मांग करने के लिए आवेदन पर गौर करने के बाद कहा कि इसके लिए कोई नया आधार नहीं बनाया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) कोमल सिंह राजपूत ने कहा, "कम से कम इस स्तर पर आगे की पुलिस हिरासत उचित नहीं है।" हिरासत खत्म होने के बाद शरीफुल को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने जांच अधिकारी से कहा कि यदि कोई नया घटनाक्रम होता है, तो पुलिस तय समय के भीतर शेष अवधि के लिए फिर से आरोपित की हिरासत मांग सकती है। नए कानूनों के अनुसार, पुलिस किसी व्यक्ति की 15 दिनों तक की हिरासत मांग सकती है। यह अपराध की गंभीरता पर गिरफ्तारी से 40 या 60 दिनों में लगातार या अंतराल में हो सकता है।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई, दो अन्य के खिलाफ वारंट

- विशेष अदालत ने दो अन्य के खिलाफ भी जारी किया गैर-जमानती वारंट
- कहा, इनकी उपस्थिति तय करने के लिए वारंट जारी करना आवश्यक

मुंबई, प्रेट्र : विशेष अदालत ने बुधवार को राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और दो अन्य वांछित आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों के विशेष न्यायाधीश बीडी शेलके ने अपने आदेश में कहा कि अदालत का मानना है कि वांछित आरोपित बिश्नोई फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा। इसलिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है। बताते चलें, अनमोल बिश्नोई के इस समय अमेरिका या कनाडा में होने का संदेह है। अदालत ने दो अन्य फरार आरोपितों शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए भी इसी तरह की टिप्पणियां कीं।

इसके साथ ही न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने अप्रैल 2024 में अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर गोलीबारी से संबंधित मामले में अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की खातिर अमेरिकी अधिकारी को सौंपने के लिए अनुरोध पत्र पहले ही जारी कर दिया है।

अनमोल बिश्नोई। फाइल

पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार 26 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अनमोल बिश्नोई, लोनकर और अख्तर को मामले में वांछित आरोपित बताया गया है। सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में उनके बेटे और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

पत्नी से अवैध संबंध के शक में कार में किया बम धमाका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई : छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मंगलवार शाम एक दफ्तर के सामने खड़ी डस्टर कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा शहर हिल गया। संयोग से कार में कोई नहीं था। यह वारदात उस पति ने की, जिसे पत्नी पर अवैध संबंध का शक था। उसने इसी शक में पत्नी के प्रेमी को मार डालने की खौफनाक साजिश की। उसने यूट्यूब से बम बनाना सीखा और एक खिलौने में फिट कर कार में लगा दिया था। पुलिस ने आरोपित पति देवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि कार महोबिया बिल्डर्स के मालिक प्रकाश महोबिया की थी, जिसे उनका भांजा और पार्टनर संजय बुंदेला भी चलाता था। भिलाई निवासी आरोपित देवेंद्र की पत्नी बिल्डर के आफिस में काम करती थीं। इसलिए उसे पत्नी के संजय के साथ अवैध संबंध का शक था। संदेह को पुख्ता करने के लिए आरोपित ने मोबाइल में एक एप इंस्टाल कर रखा था, जिससे वह पत्नी की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। जब उसका शक और गहरा हुआ, तो उसने संजय को डराने की योजना बना डाली।

नोएडा के नौवीं के छात्र ने मार्स और जूपिटर के बीच खोजा नया एस्टेरायड

जागरण संवाददाता, नोएडा

- सेक्टर-168 स्थित शिव नादर स्कूल के नौवीं के छात्र ने मार्स और जूपिटर ग्रह के बीच एक नए एस्टेरायड की खोज की

सेक्टर-168 स्थित शिव नादर स्कूल के नौवीं कक्षा के एक छात्र की अंतरिक्ष में की गई खोज की नासा ने तारीफ की है। नोएडा के छात्र ने मार्स और जूपिटर ग्रह के बीच एक नए एस्टेरायड की खोज की है। नासा ने छात्र को ही खोजे गए एस्टेरायड का नामकरण करने की इजाजत दी है।

बता दें कि दक्ष मलिक शिव नादर स्कूल में नौवीं कक्षा के छात्र हैं। दक्ष मलिक द्वारा अंतरिक्ष में खोजे गए नए स्टेरायड को 2023 ओजी40 के रूप में नामित किया गया है। बहुत जल्द दक्ष को इसका स्थायी नामकरण करने पर सम्मान मिलेगा।

दक्ष ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिछले साल प्रस्तुत किए गए एस्टेरायड की उनकी प्रारंभिक खोज को नासा द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। यह बीते डेढ वर्ष में दक्ष द्वारा किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम है। दक्ष मलिक ने कहा कि यह उपलब्धि एक सपने के सच होने जैसा है और जिज्ञासा और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। बीते वर्ष दक्ष ने द इंटरनेशनल एस्टेरायड डिस्कवरी प्रोजेक्ट

दक्ष मलिक।

में कई बार भाग लिया। यहां हार्डिन सिमंस यूनिवर्सिटी के डा. पैट्रिक मिलर के मार्गदर्शन में इंटरनेशनल एस्ट्रोनामी सर्च कोलेबोरेशन (आइएएससी), पैन-स्टार्स और नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के बीच एक सहयोग मिला। इस परियोजना ने दुनिया भर के प्रतिभागियों को हवाई में पैन-स्टार्स टेलीस्कोप से वास्तविक छवियों सहित उच्च गुणवत्ता वाले खगोलीय डाटा तक पहुंच प्रदान की। जिससे एस्टेरायड और पृथ्वी के निकट की वस्तुओं को खोजा जा सके।

परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को तनावमुक्त रखेगा सीबीएसई

जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक फरवरी से वार्षिक मनो-सामाजिक परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगा। यह दो अलग-अलग चरणों में होगा। पहला चरण परीक्षा से पहले व परीक्षा के दौरान और दूसरा चरण परिणाम घोषित होने के बाद होगा। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो हिंदी व अंग्रेजी में चौबीस घंटे सहायता देगी।

सीबीएसई अधिकारियों ने कहा कि पहले चरण की परामर्श सेवाएं एक फरवरी से चार अप्रैल तक होंगी। ये सेवाएं विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए होंगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना और छात्रों को उनकी सैद्धांतिक परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करना है। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। टेली-परामर्श में तनाव मुक्त परीक्षा की तैयारी के लिए सुझाव, समय और तनाव प्रबंधन तकनीक, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 66 प्रशिक्षित पेशेवरों की एक टीम है, जिसमें प्रधानाचार्य, परामर्शदाता, स्कूलों के विशेष शिक्षक और मनोविज्ञानी शामिल हैं।

****

सीमा पार बैठे आतंकियों के राजौरी में स्थित 25 ठिकानों पर छापे

जागरण संवाददाता, राजौरी

- पुलिस की चेतावनी, जल्द आत्मसमर्पण नहीं किया तो जब्त होगी संपत्ति
- सीमा पार से जिला में आतंकी गतिविधियों के साथ युवाओं की कर रहे भर्ती

लंबे समय से सीमा पार बैठकर राजौरी में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के साथ युवाओं को आतंकी संगठनों में शामिल करने वाले आतंकियों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने बुधवार को राजौरी में आतंकियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी की और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर सीमा पार छिपे बैठे आतंकी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर से सक्रिय आतंकियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम से संबंधित मामलों की चल रही जांच के तहत सीमावर्ती राजौरी में यह कार्रवाई हुई है। इस अभियान के दौरान पुलिस की टीमों के साथ सीआरपीएफ के जवान व अधिकारी भी शामिल रहे। एनआइए की विशेष अदालत की ओर से जारी वारंट के आधार पर पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन किया, जिसके बाद नौशहरा, थन्नामंडी, दरहाल, कोटरंका, बुद्धल, मंजाकोट और चिंगस समेत 25 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली गई। यह तलाशी

प्रतीकात्मक

पिछले साल राजौरी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले से जुड़ी जांच के तहत की गई।

आतंकी कमांडर जफर भगोड़ा घोषित: हिजबुल मुजाहिदीन की कमान कौंसिल में शामिल आतंकी कमांडर जफर हुसैन बट उर्फ खुर्शीद आलम को एनआइए की जम्मू स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। उसे एक माह के भीतर अदालत में पेश होने की चेतावनी दी गई है।

नितेश राणे ने की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनने पर प्रतिबंध की मांग

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा के नेता नितेश राणे ने राज्य में अगले महीने होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे को लिखे पत्र में कहा है कि छात्राओं को परीक्षा

हाल में बुर्का पहनने की अनुमति देने से गड़बड़ी हो सकती है। इससे सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाली छात्राओं को बुर्का पहनने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जांच के लिए महिला पुलिस अधिकारी या महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये परीक्षाएं छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें कोई गड़बड़ी न हो। दसवीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से जबकि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 11 फरवरी से प्रारंभ होगी।

दैनिक जागरण

मौन कई अप्रिय स्थितियों से बचा लेता है

महाकुंभ में अनहोनी

महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 श्रद्धालुओं की मौत ने पुनः यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आखिर अपने देश में भारी भीड़ वाले आयोजनों में जानलेवा हादसे क्यों होते रहते हैं? प्रयागराज में मेला क्षेत्र में रात दो बजे के करीब भगदड़ इसलिए मच गई, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ आए। उनके दबाव से बैरीकेड टूट गई और फिर अव्यवस्था फैल गई। इसके चलते लोग एक के ऊपर एक चढ़ते गए और आपाधापी में उन्होंने उन लोगों को भी कुचल दिया, जो मौनी अमावस्या पर संगम में डुबकी लगाने के लिए शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनमें से कुछ तो वहां सो रहे थे। जब प्रशासन इससे अच्छी तरह अवगत था कि मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, तब उसने उन्हें संगम तट पर रुकने और सोने से क्यों नहीं रोका? जब श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ आनी थी, तब लोगों को संगम तट पर प्रतीक्षा करने और विश्राम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे भीड़ का अनावश्यक दबाव बढ़ता। प्रशासन की प्राथमिकता तो यह होनी चाहिए थी कि श्रद्धालु आते जाएं और स्नान कर प्रस्थान करते जाएं। लगता है यह स्थिति का आकलन करने में चूक गया और इसी के चलते अनहोनी हो गई। इस तरह की अप्रिय घटनाएं केवल सुरक्षा प्रबंधों में किसी कमी के कारण ही नहीं होतीं। वे लोगों की ओर से अनुशासन का परिचय न देने के कारण भी होती हैं।

प्रायः आस्था के आवेग में लोग या तो संयम खो देते हैं या फिर सुरक्षा प्रबंधों की अनदेखी कर देते हैं और दुर्भाग्य से कई बार वहां भी, जहां कोई भी सुरक्षा व्यवस्था तभी प्रभावी हो सकती है, जब लोग प्रशासन का सहयोग करें और उसके निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहें। काश, महाकुंभ पहुंचे सभी श्रद्धालु यह समझ पाते कि मानव इतिहास के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में उन्हें श्रद्धा भाव के साथ ही अनुशासन भाव का भी परिचय देना होगा। जब भी इसका अभाव व्याप्त होता है, भगदड़ जनित घटनाएं हो जाती हैं। यह पहले से संभावित था कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आठ-दस करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। इतनी तो अनेक देशों की कुल जनसंख्या भी नहीं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद जिस तरह आसपास के जिलों से आ रहे वाहनों को रोकना पड़ा और श्रद्धालुओं से भरी ट्रेनों को रुक-रुक कर चलाना पड़ा, उससे यह भी रेखांकित हो रहा है कि जब भीड़ प्रबंधन एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य दिख रहा था, तब ऐसे किसी संदेश के प्रचार-प्रसार से क्यों नहीं बचा गया कि महाकुंभ में स्नान की सबसे पावन बेला मौनी अमावस्या ही है? यह राहतकारी तो है कि भगदड़ के बाद स्थितियां नियंत्रण में कर ली गईं, लेकिन जो अनहोनी हुई, उससे सही सबक सीखने अनिवार्य हैं।

स्मार्टफोन का दुरुपयोग

हर हाथ में मोबाइल ने हमारी कई मुश्किलों को आसान बनाया है। लेकिन, इसके दुरुपयोग से लोगों की जान तक जा रही है, जो गंभीर बात है। इस दिशा में शासन के साथ-साथ समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि नुकसान को रोका जा सके। बिहार के हालिया दो उदाहरणों से समझें कि कैसे मोबाइल का दुरुपयोग भारी पड़ रहा है। मधेपुरा में कुछ युवकों ने एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार इसकी भनक जैसे ही युवती को लगी, उसने अपनी जान दे दी। हालांकि, लोक-लाज के डर से स्वजन कह रहे कि उनकी बेटी ने जान नहीं दी है, एक हादसे में उसकी जान चली गई। लेकिन, जिस गोपनीय तरीके से उसे दफना दिया गया, वह सारी कहानी बयां कर रहा। वहीं, दूसरी ओर बिहार के ही बक्सर में दो युवा तब मौत की आगोश में समा गए, जब वे तेज रफ्तार बाइक पर स्मार्टफोन से अपनी रील बना रहे थे। बाइक से दुर्घटना हुई और एक झटके में जिंदगी खत्म हो गई। रील के चस्के ने उनकी रियल लाइफ खत्म कर दी। दोनों घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। शासन को तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था विकसित करनी जानी चाहिए जो आपत्तिजनक वीडियो के प्रसार को पकड़कर उस पर रोक लगा दे। अभिभावकों एवं शिक्षकों को इस तरह के मामलों पर नजर रखने की जरूरत है। हम सभी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करें। विद्यालयों को भी चाहिए कि अब वे पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था में मोबाइल के प्रयोग को न्यूनतम करें। रील या इंटरनेट मीडिया का उनको चस्का न लगे। यह समस्या किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश की समस्या बन चुकी है। लिहाजा समेकित प्रयास से ही इस तरह की घटनाएं रुकेंगी।

तकनीक का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए शासन-समाज दोनों को पहल करनी होगी

तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा

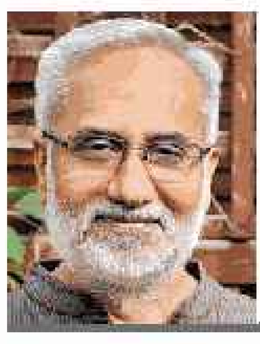

शिवकांत शर्मा

यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शोध एवं विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा

जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प ले रहे थे, उसी दिन चीन के 40 वर्षीय युवक लियांग वेनफिंग ने अपना जेनरेटिव एआइ का चैटबाट डीपसीक लांच किया। उसने अमेरिका के सैकड़ों करोड़ डालर की लागत और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद बने चैटजीपीटी, जेमिनी, लामा और क्लोद जैसे चैटबाट को धूल चटा दी और हफ्ते भर में अमेरिका का सबसे लोकप्रिय चैटबाट बन बैठा। जब यह पता चला कि डीपसीक का विकास जेजियांग यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के स्नातक ने 60 लाख डालर से भी कम की लागत से साल भर में ही कर दिखाया है तो अमेरिकी बाजारों में हड़कंप मच गया। चीनी कंपनी के तकनीकी विकास से ऐसी घबराहट पहली बार फैली। ऐसा नहीं है कि डीपसीक अमेरिका के चैटजीपीटी जैसे जेनरेटिव एआइ माडलों से आगे निकला हो। गणित, कोडिंग और सहज भाषा तर्क में वह अमेरिकी माडलों की बराबरी पर ही है, पर अमेरिका और यूरोप में हड़कंप इसलिए मचा कि चीन के इंजीनियर ने कुछ लोगों और मामूली लागत से साल भर में ऐसा माडल तैयार कर दिखाया, जो ऊंची लागत और वर्षों के शोध के बाद बने माडलों को टक्कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीपसीक ओपन सोर्स माडल है यानी इसका प्रयोग, परिष्कार और वितरण मुफ्त में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चिपों और कम ऊर्जा की खपत से चल सकता है।

ट्रंप ने इस प्रसंग पर चिंता जताने की जगह इसे अमेरिकी एआइ उद्योग के लिए चेतावनी बताया और अमेरिकियों से कहा कि यदि आप इसी गुणवत्ता के माडल कम लागत पर बना सकें तो वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। इससे एक तो अमेरिकी एआइ माडलों की लागतों पर सवाल उठे, जिससे उनकी फंडिंग का संकट खड़ा हो सकता है। दूसरे यह सवाल उठा कि सस्ते और किफायती चीनी माडल मिलने पर अमेरिका के महंगे और अधिक ऊर्जा की खपत वाले माडल को कोई क्यों लेगा? इससे एआइ उद्योग पर अमेरिका की जगह चीन का वर्चस्व कायम हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर सैलों के निर्माण पर हो चुका है। मशीन लर्निंग, रोबोट विज्ञान और ड्रोन निर्माण में भी चीनी कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को भी रक्षा सामान के लिए घरेलू कंपनियों को तमाम आर्थिक प्रोत्साहन देने के बावजूद चीन पर निर्भरता समाप्त करने में दिक्कत आ रही है।

अवधेश राजपूत

अमेरिका और यूरोप में अभी तक चीन की छवि नकल में पारंगत और सस्ता माल बनाने वाले देश की रही है। इसे बदलने और 2030 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व का अग्रणी बनने के लिए चीन ने 2006 में शोध और विकास यानी आरएंडडी की एक रणनीति बनाई थी, जिसे उसने अंजाम तक पहुंचाया। चीन अपना 2.5 प्रतिशत से अधिक बजट शोध एवं विकास पर लगाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास में उसका योगदान 60 प्रतिशत हो। इस मामले में अमेरिका विश्व का अग्रणी देश रहा है, लेकिन अब चीन उससे बहुत पीछे नहीं है। अमेरिका शोध एवं विकास पर अपने जीडीपी का 3.4 प्रतिशत खर्च करता है तो चीन 2.41 प्रतिशत खर्च कर रहा है। भारत इस मामले में फिसड्डी है और जीडीपी का मात्र 0.64 प्रतिशत ही शोध एवं विकास पर खर्च करता है। यानी शोध एवं विकास पर चीन भारत से चौगुना बजट खर्च करता है। चीन का जीडीपी भी भारत से पांच गुना अधिक है, जिसके कारण शोध एवं विकास पर चीन का खर्च भारत से 20 गुना बैठता है और यह अंतर पिछले 20 साल से चल रहा है।

शोध एवं विकास पर विश्व में सबसे अधिक खर्च करने और आर्थिक विकास में उसका योगदान सुनिश्चित करने के कारण ही अमेरिका पिछले 50 वर्षों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी बना हुआ है। अब चीन उसी राह पर और भी सुनियोजित ढंग से चल रहा है। डीपसीक माडल के विकास से पश्चिमी देशों की नींद उड़ा देने वाले चीनी इंजीनियर वेनफेंग ने हाल के एक इंटरव्यू में कहा था, 'हम अक्सर सुनते हैं कि चीनी और अमेरिकी एआइ के बीच एक या दो साल का फासला है, पर असली फासला नकल और मौलिकता का है। वह नहीं बदला तो चीन हमेशा पिछलग्गू बना रहेगा और चीन हमेशा पिछलग्गू बना नहीं रह सकता।' वेनफेंग जैसे सैकड़ों अन्वेषक गुणवत्ता और लागत में पश्चिम को चुनौती दे सकने वाली तकनीक का विकास करने में जुटे हैं। स्वच्छ ऊर्जा उपकरण, बिजली की कारें, कंप्यूटर गेम और एआइ माडलों में भी चीन की कंपनियां इतनी आगे निकल चुकी हैं कि उन्हें रोकने के लिए अमेरिका-यूरोप को व्यापार संरक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है।

मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण दौर से अब संरक्षणवाद और क्षेत्रीय गुटबंदी के दौर में प्रवेश करती दुनिया में विकास करने और वर्चस्व कायम करने के लिए शोध एवं विकास पर बल देने की जरूरत और बढ़ गई है। इसके बिना न अपनी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है और न अपना माल बेचकर व्यापार बढ़ाया जा सकता है। दूसरे देशों में अपना माल और सेवाएं बेचे बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जो अपना माल बाहर बेचे बिना संपन्न बना हो। इसलिए भारत को यदि अपनी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शोध एवं विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक प्रगति में उसका योगदान अधिक से अधिक रहे। इसके लिए उसे आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी, जिन्हें आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता। करीब 25 से 40 करोड़ वाले मध्यवर्ग और लगभग 6.5 करोड़ लघु उद्यम वाले देश में दो-ढाई करोड़ लोगों के आयकर से यह सब नहीं हो सकता। कर्ज उठाने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और जीएसटी से मांग घटती है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

सबके हित की चिंता करे सरकार

राजीव सचान

सरकार को यह देखना चाहिए कि अधिकाधिक लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कैसे आएं

दिल्ली में विधानसभा चुनावों के चलते राजनीतिक दलों में मुफ्त या रियायती सुविधाएं देने की घोषणा करने की होड़ मची है। सभी घोषणाओं को रेवड़ी नहीं कहा जा सकता। कुछ घोषणाएं समय की मांग भी हैं, जैसे भाजपा का यह वादा कि वह दिल्ली के गिग वर्करों के लिए 10 लाख के जीवन बीमा और पांच लाख रुपये के दुर्घटना बीमा की व्यवस्था करेगी। यह अच्छी घोषणा है, लेकिन यह सुविधा तो सारे देश के गिग वर्करों को मिलनी चाहिए। एक ऐसे समय जब गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तब सरकारों को यह देखना ही चाहिए कि वे अपना जीवनयापन सही तरह और सम्मानजनक ढंग से कर सकें। ई कामर्स कंपनियों के सामान के साथ खाने-पीने की सामग्री की डिलिवरी करने वाले गिग वर्कर कहे जाते हैं। वे स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि फ्रीलांसर के रूप में काम करते हैं। उन्हें न तो कोई छुट्टी मिलती है और न ही अन्य सुविधा। जितना काम, उतना पैसा। काम नहीं तो पैसा नहीं। कंपनियां गिग वर्करों पर कम समय में सामान की डिलिवरी करने का दबाव तो बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन वे उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने को तत्पर नहीं। उनके काम के घंटे तय नहीं। यदि वे किसी घटना-दुर्घटना के शिकार होते हैं तो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं।

पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के साथ कुछ राज्य सरकारों की ओर से यह सुनने को मिल रहा है कि वे गिग वर्करों के कल्याण और विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं लाने वाली हैं, लेकिन अभी तक वे आश्वासन के स्तर पर ही हैं। देश में गिग वर्करों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग की एक रपट के अनुसार 2020-21 में गिग वर्करों की संख्या 77 लाख थी, जिसके 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सरकार को उनके हित की चिंता करनी ही चाहिए। जैसे गिग वर्कर तेजी से बढ़ रहे हैं, वैसे ही निजी सुरक्षा कर्मी भी। एक आंकड़े के अनुसार देश में इस समय सवा करोड़ निजी सुरक्षा गार्ड हैं। उनकी मांग बढ़ती ही जा रही है। आज हर कहीं और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी निजी सुरक्षा गार्ड दिखते हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त सुध नहीं ली जा रही है।

अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शनरत गिग वर्कर। प्रेट्र

पिछले से पिछले लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है का नारा लगा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान चलाया था और चौकीदारों यानी निजी सुरक्षा गार्डों को संबोधित किया था, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं हो सकी, जिससे उनकी कार्यदशाएं बेहतर होतीं। हालांकि सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने वाली कंपनियों को पंजीकरण कराना पड़ता है, लेकिन वे गार्डों को क्या सुविधाएं देती हैं, इसके लिए कोई ठोस नियम-कानून नहीं। देश में रजिस्टर्ड निजी सुरक्षा कंपनियों की संख्या 23 हजार से अधिक है, लेकिन चंद ही सुरक्षा गार्डों को साप्ताहिक अवकाश और वे सुविधाएं देती हैं, जो उन्हें मिलनी चाहिए। अधिकतर निजी सुरक्षा कंपनियां गार्डों से 12 घंटे काम लेती हैं और उन्हें कोई छुट्टी नहीं देतीं। ये कंपनियां उनकी वर्दी का पैसा भी उनके वेतन से काट लेती हैं। सरकारें चाहें तो आसानी से ऐसी व्यवस्था कर सकती हैं, जिससे सभी कंपनियां सुरक्षा गार्डों के काम के घंटे कम करने के साथ उन्हें साप्ताहिक छुट्टी दें। हाल में दिल्ली में चुनाव प्रचार के बीच अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि यदि उनकी सरकार बनी तो राजधानी में सभी आरडब्ल्यूए को सुरक्षा गार्ड रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन आखिर इससे निजी सुरक्षा गार्डों को कोई राहत कैसे मिलेगी? गिग वर्करों और निजी सुरक्षा गार्डों की अनदेखी यही बताती है कि किस तरह समाज का एक बड़ा तबका सामने होते हुए भी नीति-नियंताओं की आंखों से ओझल सा है।

हाल में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खुश कर दिया। इस वेतन आयोग का लाभ राज्यों के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को भी मिलेगा। पिछले सप्ताह यह खबर भी आई कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन स्कीम को अधिसूचित कर दिया। यह योजना इसी एक अप्रैल से लागू होने जा रही है। नई पेंशन स्कीम को अनाकर्षक पा रहे सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और एकीकृत पेंशन स्कीम लेकर आई। इस पेंशन योजना को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब अंतिम वेतन का करीब 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन स्कीम लाकर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक पुरानी मांग पूरी कर दी, लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन साढ़े सात हजार करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपये है। यह सर्वथा अनुपयुक्त है।

सरकारें सबके लिए होती हैं। उन्हें जितनी चिंता सरकारी कर्मचारियों की करनी चाहिए, उतनी ही अन्य लोगों की भी। इसलिए और भी, क्योंकि अपने देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है, जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर है। सरकार को बजट या फिर उससे इतर यह देखना चाहिए कि अधिकाधिक लोग सामाजिक सुरक्षा की दायरे में कैसे आएं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

वाद-विवाद

अध्ययन के दौरान बुद्धि विकास हेतु वाद-विवाद प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। उनमें पक्ष या विपक्ष में विचार रखे जाते हैं। इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि प्रतिभागियों के सोचने की परिधि में विस्तार हो। सामान्य जीवन में वाद-विवाद बुद्धि की कसरत से अधिक अहम की तुष्टि का विषय बन जाता है। वाद-विवाद का कोई प्रयोजन होना चाहिए। बिना प्रयोजन और अहम को तुष्ट करने के लिए की गई बहस वास्तव में निरर्थक होती है।

विद्वान प्रायः युक्ति और तर्क की अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं। वे बोलते कम और सुनते अधिक हैं। यदि उन्हें कोई वाद-विवाद के लिए बाध्य भी करे तो वे शांतचित्त से संक्षिप्त उत्तर देकर उसमें बहुत समय तक उलझे नहीं रहते। उनके जीवन का लक्ष्य अस्थायी बहस जीतना नहीं, बड़े लक्ष्यों के लिए ऊर्जा बचाना होता है। अनावश्यक वाद-विवाद मनोदशा को नकारात्मक बनाता है।

बहस उत्तेजना को जन्म देती है। मन को चंचल करती है। विवेक को हर लेती है। कब एक स्वस्थ विचार-विमर्श तर्क-वितर्क के रास्ते चलता हुआ विवाद का रूप धारण कर लेता है, यह पता ही नहीं चलता। निरर्थक बहस से समय की बर्बादी होती है। संबंधों में कटुता आती है तथा चित्त में हलचल मच जाती है। अंत में प्रतीत होता है कि हाथ में कुछ आया भी नहीं।

अतः यदि कोई अकारण ही बहस करने के लिए बाध्य करे तो अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं होता। पात्र व्यक्ति देखकर ही उसके समक्ष तर्क रखने चाहिए, जो उन तर्कों को स्वस्थ बुद्धि से ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। वैसे भी मौन से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं होता। तर्क-वितर्क का लक्ष्य बुद्धि को तीक्ष्ण करना होना चाहिए न कि दूसरे के मस्तिष्क पर बढ़त बनाना। अमेरिकी विद्वान राबर्ट क्विलेन ने कहा है कि चर्चा ज्ञान का आदान-प्रदान है, जबकि बहस अज्ञान का।

ट्विंकल तोमर सिंह

लिव-इन रिश्तों में धोखाधड़ी पर लगाम

डा. मोनिका शर्मा

लिव-इन रिश्तों में महिलाएं अधिक ठगी जाती हैं, सो उन्हें बचाने की व्यवस्था की जा रही है

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद सहजीवन संबंधों में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। ध्यातव्य है कि यूसीसी नियमावली के प्रविधानों में विवाह और तलाक के पंजीकरण के साथ ही उत्तराधिकार से जुड़े नियम भी महिलाओं के जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। इसी में लिव इन रिश्तों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने वाला पक्ष भी शामिल है। लिव-इन में रहने वाले या सहजीवन रिश्ते में साथ रहने की तैयारी करने वालों से जुड़े प्रविधान के तहत शादी के साथ-साथ लिव-इन में रहने वाले जोड़ों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है।

यूसीसी कानून के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया के तहत जो जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इसके बारे में जिले के रजिस्ट्रार के सामने घोषणा करनी होगी। साथ ही, लिव-इन रिलेशनशिप को समाप्त करने की स्थिति में भी इस विषय में घोषणा करना आवश्यक है। मनचाहे रिश्तों को दायित्वबोध से जोड़ने वाले इन प्रविधानों के अनुसार उत्तराखंड का जो निवासी राज्य के बाहर रहता है, वह भी अपने जिले में अपने सह-जीवन संबंध के विषय में जानकारी दे सकता सकता है। यूसीसी में सहजीवन रिश्तों से जुड़ा एक अहम पक्ष यह भी है कि समान नागरिक संहिता नियमों के अंतर्गत लिव-इन रिलेशनशिप में जन्म लेने वाले बच्चों को भी वैध बच्चा घोषित किया गया है।

वस्तुतः बीते कुछ वर्षों में महानगरों में ही नहीं दूर-दराज के कस्बों और छोटे शहरों में भी सहजीवन संबंधों की ओर झुकाव बढ़ा है। दुखद है कि मनमर्जी से जोड़े गए सहजीवन संबंधों में धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। साथ रहने-जीने से जुड़ी तयशुदा नियमावली न होने से यौन शोषण, जालसाजी, घरेलू हिंसा और एक दूसरे पर झूठे केस दर्ज करवाने की घटनाएं देशभर में हो रही हैं। बर्बरता से लिव इन साथी का जीवन छीनने के वाकये तो स्पष्ट बताते हैं कि वर्षों के साथ में भी भावनात्मक धरातल पर कोई जुड़ाव नहीं होता। लिव इन के नाम पर झूठी पहचान बताकर बच्चियों और महिलाओं को भरमाने का खेल भी खेला जाता है।

उत्तराखंड में यूसीसी नियमों के अनुसार, अब उन लोगों का लिव-इन रिलेशनशिप भी वैध नहीं हो सकता जो अवयस्क हैं, पहले से शादीशुदा हैं या धोखे से ऐसा कर रहे हैं। धोखाधड़ी के कई मामलों में बर्बरता होने के बाद महिला के स्वजनों को उसके लिव इन में रहने की जानकारी मिलती है। ऐसे में 21 साल से कम उम्र के लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक-युवतियों का अपने स्वजनों को इस बारे में सूचित करने का नियम सुरक्षा से जुड़ा अहम पहलू है। असल में सह-जीवन संबंधों में महिलाएं ज्यादा ठगी जाती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भी एक निर्णय में लिव-इन संबंधों को वैधानिक बनाने और सहजीवन संबंध स्थापित करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही जा चुकी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजनीति को स्वच्छ बनाना आवश्यक

'शर्मिंदगी की बात' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में उचित ही लिखा है कि दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए छह दिन की कस्टडी पैरोल मिलने से एक गलत परंपरा स्थापित होगी। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि देश में कोई आरोपित व्यक्ति चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। इस मामले में चुनाव आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर कानून की इस खामी को सुधारना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेल में बंद किसी भी प्रकार के आरोपित को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे न केवल चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता घटती है, बल्कि यह लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध भी है। हमारे संविधान में चुनाव लड़ने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित हैं। अब इन प्रविधानों की समीक्षा करनी होगी, ताकि आरोपितों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। मतदाताओं को भी ऐसे प्रत्याशियों को नकारना चाहिए। भारतीय राजनीति को स्वच्छ बनाए रखने के लिए यह अपरिहार्य हो गया है।

budawanwalas55@gmail.com

मेलबाक्स

देश के लिए घातक नकारात्मक राजनीति

विपक्षी दलों की वर्तमान राजनीति का स्तर काफी हल्का हो गया है। जबकि राजनीति में शुचिता, परिपक्वता के साथ एक-दूसरे नेता के प्रति मान-सम्मान राजनीतिक गहने होते हैं, ताकि राजनीति में ओछापन न पनपने पाए। जहां राजनीति स्तरहीन और छिछली हुई, समझो राजनीति के मापदंड समाप्त हो चुके हैं। झूठ फरेब की राजनीति और अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। नेताओं के लिए मानव मूल्यों का महत्व व जनकल्याण केवल नारों में स्थापित हो जाता है। सत्ता हस्तांतरण येन-केन प्रकारेण एक मात्र ध्येय बन जाता है। वर्तमान में जनसाधारण का दिमाग तब शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जब एक राज्य के नेताओं द्वारा दूसरे राज्य की सरकार पर नदी के पानी में जहर मिलाना और सामूहिक नरसंहार की योजना जैसे अत्यंत गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। यह पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाली घटना है। इन गंभीर आरोपों की उच्चस्तरीय सघन जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जनसाधारण का सरकार के प्रति विश्वास बना रहे। निश्चित ही ऐसे संगीन आरोप देश के संघीय ढांचे के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसा स्तब्ध कर देने वाला बयान ऐसे समय आया जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। निश्चित ही स्तरहीन, जहरीली और नकारात्मक राजनीति देश के लिए घातक ही सिद्ध होगी।

दीपक गौतम, सोनीपत।

शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य पर पाबंदी

हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (असर) के संदर्भ में मध्य प्रदेश के परिणाम निराशाजनक आए हैं। आश्चर्य की बात है कि केंद्र और प्रदेश सरकार का संपूर्ण ध्यान स्कूली शिक्षा को मजबूती प्रदान करने की ओर दिया जा रहा है, बजट आवंटित किया जा रहा है, और शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं। फिर भी, ''असर'' के सर्वे में दूसरी और तीसरी कक्षा के 52 प्रतिशत छात्र-छात्राओं में अक्षर ज्ञान नहीं पाया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम अगर इस प्रकार से आते हैं, तो जिम्मेदारों को यह विचार करना होगा कि खामी कहां हो रही है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हो सकते हैं- शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाना। स्कूल के शिक्षकों को मतदाता सूची को अपडेट करने समेत निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न करना। वहीं, उन्हें शासन की कई योजनाओं का सर्वे घर-घर जाकर करना होता है। इस कारण छात्र-छात्राएं पढ़ाई के लिए कक्षा में बैठे रह जाते हैं। यदि अच्छे परिणाम चाहिए, तो शिक्षकों से केवल पढ़ाई का कार्य लिया जाना चाहिए। दूसरा, छात्र-छात्राओं के पढ़ने के स्थान, यानी स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं, जिसे सुधारा जाना चाहिए। कई अन्य कारण भी हैं जिन कारणों से स्कूल में बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है। इन कुछ प्रमुख बिंदुओं पर सरकार को ध्यान देना होगा।

प्रदीप कुमार संघवी, शिक्षाविद, झाबुआ, एमपी।

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

40 प्रतिशत सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं, जबकि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में ऐसे 30 प्रतिशत प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए थे, वहीं 2014 में इनकी संख्या 34 प्रतिशत और 2019 में 43 प्रतिशत थी, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार।

आजकल

स्वच्छ छवि वालों को ही चुनाव लड़ने का अवसर

आगामी बुधवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के एक आरोपित एवं हालिया विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ताहिर हुसैन को कुछ शर्तों के साथ चुनाव प्रचार के लिए छह दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है। आरोपित अब प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार करेगा और स्वाभाविक है कि जनता के बीच स्वयं को वह निर्दोष भी बताने का प्रयास करेगा। लिहाजा चुनाव में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि जनता को केवल साफ-सुथरी छवि वाले लोगों को ही चुनने का विकल्प मिल सके

लालजी जायसवाल
सामाजिक मामलों के जानकार

प्रतीकात्मक

राजनीति से अपराध को समाप्त करने के विमर्श पर देश में निरंतर चर्चा होती रहती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंगों के आरोपित एक व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने की अनुमति देना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिलहाल यह स्थिति इसलिए बन रही है, क्योंकि मौजूदा जन प्रतिनिधित्व कानून विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यह विडंबना ही है कि कोई विचाराधीन कैदी वोट तो नहीं डाल सकता, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। कानून की इस खामी का लाभ वे भी उठाते रहे हैं, जो गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं। बता दें कि फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में करीब 50 लोग मारे गए थे। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप न केवल दंगों से जुड़े हैं, बल्कि गृह मंत्रालय के अधिकारी की हत्या से भी जुड़े हैं। चिंता की बात है कि भीषण दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता था, यदि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव को मान लेते कि संगीन धाराओं में आरोपित ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की छूट न मिले, जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई हो। राजनीतिक दलों ने इस उचित प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि दोष सिद्ध न होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए।

लिहाजा इस दलील ने राजनीति के अपराधीकरण का दरवाजा खोलने का काम किया। कई ऐसे लोग निर्वाचित हो रहे हैं, जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस सबके बाद भी आरोपित को चुनाव प्रचार की सुविधा मिल जाना घोर निराशा की बात है। निराशाजनक यह भी है कि दंगों के पांच साल बाद भी ताहिर हुसैन को सजा नहीं हो सकी। उचित होता कि सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत देने के पहले यह सब देखता और इसकी परवाह करता कि इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त को चुनाव प्रचार करने की छूट देने से समाज में क्या संदेश जाएगा?

चुनाव सुधार गंभीर मुद्दा : वास्तविकता यह है कि चुनाव सुधार की मांग समय-समय पर उठती रही है और खासकर उस समय जब चुनाव नजदीक आए अथवा चुनावी प्रक्रियाओं के समय ज्यादा ही चुनाव में सुधारात्मक कदम उठाने की बात की जाती रही है। मालूम हो कि कुछ दिन बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होना निर्धारित है।

अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन मसलों का हल चुनाव से पहले ही क्यों नहीं निकाल लिया जाता? इसका उत्तर यह कदापि नहीं है कि चुनाव आयोग शक्तिहीन हो चुका है, आज भी चुनाव आयोग में संपूर्ण शक्तियां विद्यमान हैं और वह निष्पक्षता से काम भी कर रहा है। लेकिन कुछ दशक से यह देखा जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो सदैव चुनाव सुधार की बात की जाती है, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां सदैव इसमें असहयोग और विरोध ही प्रकट करती रही है। शायद यह कयास लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चुनाव सुधार से राजनीतिक दलों को यह भय सता रहा होगा कि उनके मनमानी और आपराधिक संलिप्तता तथा धन का अथाह उपयोग पर रोक लग जाएगा। वैसे भी भारत में होने वाले चुनावों में बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता एक कड़वी सच्चाई है। इसके लिए निर्धारित खर्च की सीमा निरर्थक साबित होती रही है और जिसका शायद ही कभी पालन किया जाता है।

चुनावी प्रक्रिया में एक गंभीर मुद्दा भड़काऊ भाषणों का भी है जिस पर नियंत्रण लगाने के लिए चुनाव आयोग को कठोर होना होगा। आज के नेता युवाओं को भड़काने के लिए उग्र नारे देते हैं जिससे वे चर्चा में बने रहें। वास्तव में यह हाल की राजनीतिक अपरिपक्वता को दिखाता है। सवाल उठता है कि क्या नेताओं की जुबान अनजाने में फिसलती है या फिर जानबूझ कर जुबान फिसलाई जाती है। बहरहाल, मालूम हो कि नेताओं की जुबान का फिसलना जिसे हम लोग विवादित बयान भी कहते हैं, वह जुबान जानबूझ कर चर्चा में रहने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। लिहाजा, अब ध्यान रखना होगा कि जब हम स्वयं को दुनिया का श्रेष्ठ लोकतंत्र कहते हैं, तब ऐसे राजनीतिक अपरिपक्वता को भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्थान देना कितना सही होगा?

चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध : अपराधी करार दिए जा चुके जनप्रतिनिधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना राजनीति के निरपराधीकरण में सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः निरंतर राजनीति में अपराधीकरण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह कदम उचित ही कहा जा सकता है। यह भविष्य में चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक निवारक कारक की तरह कार्य करेगा और वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से बचेंगे। राजनीति में स्वच्छ पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का प्रवेश होगा। इससे जनता का राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी।

जहां तक आजीवन प्रतिबंध का सवाल है तो यह भारतीय राजनीति को स्वच्छ करने की दिशा में एक दूरगामी कदम साबित हो सकता है, लेकिन पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रविधानों का दुरुपयोग न हो। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 40 प्रतिशत वर्तमान सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जनप्रतिनिधित्व कानून को सख्त करने से राजनीति के अपराधीकरण की समस्या दूर नहीं होगी। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई कमजोरियां हैं। लिहाजा कमजोर आधार पर सजा को बढ़ाने से सरकार को प्रतिद्वंद्वियों को ठिकाने लगाने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग करने का ही अवसर मिलेगा।

विचाराधीन कैदियों को मिले कानूनी सहायता

सुमन कुमार
अधिवक्ता और नीतिगत मामलों के जानकार

मानव अधिकार की रक्षा से जुड़े विषयों पर आए दिन चर्चा होती रहती है। ऐसे में जेल के अंदर वर्षों से बंद विचाराधीन कैदी के संदर्भ में बात करना स्वाभाविक है। खासकर जब भारत में जेलों में बंद लगभग दो-तिहाई कैदी विचाराधीन श्रेणी में हैं। वस्तुतः विचाराधीन कैदी उन्हें कहा जाता है जिन्हें उन आरोपों के लिए अब तक दोषी नहीं ठहराया गया है जिनके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। माना जाता है कि उन्हें 'न्यायिक हिरासत' में रखा गया है, परंतु आमतौर पर उन्हें जेलों में रखा जाता है। विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई से जुड़ा है, ताकि वे गवाहों को प्रभावित न कर सकें।

एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो) के अनुसार, देश की जेलों में चार लाख से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, जो कुल कैदी के दो-तिहाई से भी अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को देश के सभी जिलों में जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को शामिल करते हुए विचाराधीन समीक्षा समितियों की स्थापना के लिए राज्य अधिकारियों और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है। विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संबंध में विमर्श यह है कि कानून की प्रक्रिया द्वारा अपराध स्थापित होने से पहले कोई सजा कितनी होनी चाहिए? जेल में बंद विचाराधीन कैदी की अवधारणा दोषसिद्धि से पहले की सजा के समान है, क्योंकि उसे संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसे में हमें विचाराधीन कैदियों और दोषियों के बीच के अंतर को समझना होगा। विचाराधीन 'पीड़ितों' के बीच कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टिकोण भी एक कारक है। बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी के बाद विचाराधीन कैदियों की संख्या काफी बढ़ी है, जिसका एक पक्ष आर्थिक, बेरोजगारी और सामाजिक है। एकमात्र तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है आरोपी द्वारा उचित संदेह से परे किए गए कृत्य की स्थापना। विचाराधीन कैदियों के लिए उपलब्ध 'न्याय प्रणाली' में कैसे मजबूती और त्वरित न्याय मिले इस पर सोचना होगा।

विचाराधीन कैदियों के पास त्वरित सुनवाई के साथ-साथ निष्पक्ष सुनवाई का संवैधानिक अधिकार है। अमानवीय व्यवहार के खिलाफ उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए या किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, उन्हें जेल से अदालत में स्थानांतरित करते समय हथकड़ी लगाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि इसके लिए वैध कारण न हो। अपने मामले में सहायता के लिए कानूनी सहायता का वे लाभ उठा सकते हैं। यदि उनके पास इसका लाभ उठाने का साधन नहीं है, तो वे अदालत में आवेदन करके मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।

वर्तमान में जेल प्रणाली में एक बड़े सुधार की गुंजाइश है। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बुनियादी मानवीय मानकों तक लाने की जरूरत है। इसके लिए प्रत्येक अपराध में सजा काटने की अवधि के अनुसार एक वर्गीकरण होना चाहिए और कैदियों को उसी के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। देश में कानूनी सहायता की समीक्षा के लिए स्वायत्त निकाय की स्थापना होनी चाहिए जो विचाराधीन कैदियों को न्याय के दायरे में ला सके और उन्हें न्याय का लाभ मिल सके।

खरी-खरी

आज मौसम बड़ा बेईमान है...

शरद उपाध्याय

आज मौसम बड़ा बेईमान है... जब भी यह गीत सुनता हूं तो लगता है कोई गड़बड़ होने वाला है। मौसम पर आजकल भारतीय राजनीति की छाया पड़ गई है। पता ही नहीं चल पाता कि कब कौनसी करवट ले बैठे। जिस तरह हम किसी राजनीतिज्ञ के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसी तरह मौसम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्लोबल वार्मिंग की भीषण गर्मियों की चेतावनी के बाद जमती ठंड मुझे हैरान कर रही है। मुझे मौसम विज्ञानियों पर तरस आता है। मौसम विज्ञानी और मौसम, दो असमान विचारधाराएं हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। वो भविष्यवाणी कुछ करते हैं, पर हो कुछ और जाता है।

पहले मैं मौसम विभाग की बात को बहुत गंभीरता से लेता था। जब भी वो कहता, 'जोरदार बारिश की संभावना है, बरसाती, छाते से लैस होकर निकलता था। पत्नी कहती, 'ये क्या, आसमान तो साफ है।'

मैं मन ही मन हंसता। मैं साहसी योद्धा की तरह निकल जाता। बस में, दफ्तर में लोगों की फब्तियां सुनता। पर हिम्मत नहीं हारता कि कभी तो बरसेगा। पर कमबख्त सुबह से शाम तक एक बूंद भी नहीं टपकती।

बाद में मौसम विज्ञानी भी दयनीय भाव लिए बयान दे देता था। इसमें हमारी क्या गलती है। हमने तो बिल्कुल सही आकलन किया था, पूरा माप-तौल सही था।

बेचारा वह भी क्या करे, मौसम भी नैतिकता की पटरी से उतर गया है। मैं देख रहा हूं, विज्ञानी ग्लोबल-वार्मिंग की चेतावनी दे रहे हैं। वे गर्मी को लेकर परेशान हैं, भयभीत हैं। इतना खतरनाक वर्णन करते हैं कि गर्मी से सारी बर्फ पिघल जाएगी।

लेकिन लोग हक्के-बक्के हैं। चारों तरह ठंड ही ठंड है। आदमी कपड़े पहने रहा है, गरम चीजें खा रहा है और ठंड से कांप रहा है। ठंड जो है, हड्डियों तक को जमा देने वाली है। रोज मैं उठता हूं, मौसम विज्ञानियों को स्मरण करता हूं। घरवालों से कहता हूं, 'चिंता मत करों। ठंड अब जाने ही वाली है, विज्ञानी कह रहे थे, बर्फ बस पिघलने वाली है। हमारे अस्तित्व को खतरा है। लेकिन फिर सोचता हूं, मौसम का क्या? वह तो बेईमान है...

पोस्ट

मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई वह दुखद है, लेकिन जिस शीघ्रता से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया, वह सराहनीय है।
मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

महाकुंभ में उमड़ रही भीड़ को संभालने का दायित्व सिर्फ शासन-प्रशासन का ही नहीं है। आपसी सहयोग और मानवता की भावना से एक-दूसरे का सहयोग भी करें।
जिंदगी गुलजार है@Gulzar_sahab

वीवीआइपी दर्शन का मामला हमारे मंदिरों और धार्मिक स्थलों में एक बीमारी की तरह फैल गया है। यह महाकुंभ में भी दिखा। भगदड़ की दुखद खबर आई। वक्त की पुकार है वीवीआइपी मुक्त कुंभ, वीवीआइपी मुक्त मंदिर।
संकेत उपाध्याय@sanket

घरेलू क्रिकेट की नाक रणजी ट्राफी में बड़े-बड़े सितारा खिलाड़ियों के मैदान में उतरने से मुकाबलों में नई जान आ गई है। दर्शकों में उत्साह बढ़ा है। कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर की टीम ने सितारों से सजी मुंबई को उसके मैदान पर ही मात दी थी।
सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या महाकुंभ पर मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी से कांग्रेस को नुकसान होगा?

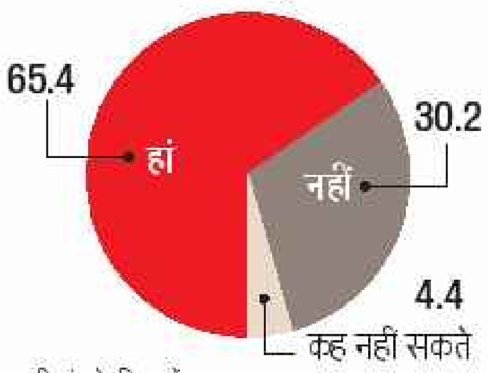

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या चीन तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका को पछाड़ सकता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दुर्घटना जैसे हुई टूट पड़े सब गिद्ध,
ताक लगाए थे सभी यही हो रहा सिद्ध।
यही हो रहा सिद्ध ताकते रहते मौका,
इक गलती पा जायं मारते मिलकर चौका।
पटे पड़े थे घाट न चाहे कोई हटना,
सचमुच है दुर्भाग्य कुंभ की यह दुर्घटना।
– ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

फिर बच जाएंगे भ्रष्टाचार के मगरमच्छ

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, नईदुनिया, मध्य प्रदेश

भ्रष्टाचार अब ऐसा मुद्दा बन गया है, जिस पर कोई न तो बात करना चाहता है, और न ही इस विषय में किसी की रूचि बची है। पहले भ्रष्टाचार की बात आती थी तो चौतरफा बिहार के चारा घोटाले की ही बात की जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश इसमें सबसे आगे निकल गया है। आयकर विभाग के नोटिस और जांच की बात हो तो मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारियों की संख्या ही सबसे अधिक होगी। प्रदेश कैडर के ही आइएएस रहे अरविंद जोशी और टीनू जोशी भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त होने वाले पहले अधिकारी रहे हैं। इसके बाद न जाने कितने घोटाले हुए, सैकड़ों करोड़ का पोषण आहार घोटाला, ई-टेंडर घोटाला, आयुष्मान घोटाला से लेकर व्यापमं घोटाले जैसी दर्जनों कहानियां हैं, जो प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार की गवाही दे रही हैं।

अभी एक बिल्डर राजेश शर्मा के यहां आयकर के छापों में एक मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की पोल खुली, उसने भी अपनी काली कमाई बिल्डर के व्यवसाय में लगा रखी थी। कई अन्य ब्यूरोक्रेट्स भी इस गिरोह में शामिल हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। प्रदेश में लोकायुक्त संगठन ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहां छापा मारा तो कई करोड़ की संपत्ति मिली। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसके घर से 54 किलो सोना और दस करोड़ की नकदी एक गाड़ी से बाहर भेज दी गई। स्पष्ट है कि बिना मिलीभगत के यह संभव नहीं है। आगे देखिए, इसमें प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री होती है और वह भी छापेमार कार्रवाई करती है। लोकायुक्त संगठन से आगे वह कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज हासिल कर लेती है। इसके बाद दोनों एजेंसियां सौरभ शर्मा की तलाश करती हैं। 41

लोकायुक्त पुलिस की अभिरक्षा में सम्मान से बिठाया गया सौरभ शर्मा। नईदुनिया

दिनों तक सौरभ शर्मा दोनों एजेंसियों की पकड़ से बाहर रहता है और जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। सौरभ तब गिरफ्तार किया जाता है, जब वह अदालत में आत्मसमर्पण करने जा रहा था। उसके अचानक प्रकट होने की घटना भी गले नहीं उतर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा मामला मैनेज होने के बाद ही सौरभ बाहर आया है। इसकी कई वजह भी हैं।

सौरभ तो एक ऐसी छोटी मछली है, जिसे कभी भी कोई भी दबोच सकता है। दरअसल, अब इस मामले को ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि सौरभ के पीछे जो राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स के चेहरे छिपे हैं, कोई भी उन्हें सामने नहीं लाना चाहता है। मध्य प्रदेश का ही दुर्भाग्य कहें, जब भी बड़े घोटाले हुए, सभी सफेदपोश को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश का हनीट्रैप मामला भी इसी में से एक था, जिसमें कई मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, लेकिन वह भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी विचार का प्रश्न है। न्यायालय में भी दोषी बचा लिए गए और हनीट्रैप कर ब्यूरोक्रेट्स से करोड़ों रुपये वसूलने वाली महिलाओं के खिलाफ प्रकरणों में भी वह धीरे-धीरे बरी हो रही हैं। अब यह कौन सा नया समीकरण क्यों बन रहा है, समझा जा सकता है। इस हनीट्रैप मामले का जिक्र इसलिए किया गया, क्योंकि इसमें भी दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। एक मुख्य सचिव ऐसे थे, जिन्होंने आइएएस अधिकारियों के 'अरेरा क्लब' में हनी ट्रैप की दागी महिला को मेंबर बना दिया था। उसी क्लब में जाकर वह महिला अपने शिकार फंसाती थी। खैर अभी बात भ्रष्टाचार के 'परिवहन' यानी सौरभ शर्मा की चल रही है।

जिस नाटकीय घटनाक्रम में सौरभ की गिरफ्तारी हुई, उससे साफ हो गया कि अब मामले में पानी डालकर सारे मगरमच्छ को बचा लिया जाएगा। इसकी कई वजहें हैं। सौरभ शर्मा के जमानत आवेदन में स्पष्ट लिखा है कि 54 किलो सोना, गाड़ी करोड़ों की नकदी से उसका कोई संबंध नहीं है। लोकायुक्त और ईडी ने जिस घर में छापा मारकर करोड़ों की नकदी और 50 से अधिक बेनामी संपत्ति बरामद की है, उससे भी सौरभ ने पल्ला झाड़ लिया। आशय साफ है कि सौरभ को मगरमच्छों ने बचाने का आश्वासन दे दिया है, इसलिए अब वह किसी भी बड़े मगरमच्छ का नाम और उसका राज नहीं बताएगा। इसी भरोसे पर सौरभ अपने बिल से बाहर निकला है। मध्य प्रदेश की सरकार के लिए विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे मसलों पर उसके कमजोर रुख से केवल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब कोई बिहार का नाम नहीं लेता है, बल्कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। वोहरा कमेटी की जो रिपोर्ट कई दशकों से धूल खा रही है, उसे निकालने का समय तो चला गया, लेकिन अब नए सिरे से एक ऐसी कमेटी बनाने का समय आ गया है, जो सिंडीकेट- माफिया के साथ या भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त लोगों को संरक्षण देने वाले अधिकारी-नेताओं की जानकारी जुटाए। अब भी यदि यह कदम नहीं उठाया गया तो भ्रष्टाचार के इस नए गिरोह को रोकना मुश्किल होगा।

हिमाचल प्रदेश डायरी

रेरा को सेब बांटने की क्या जरूरत

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी चर्चा में है। इसलिए नहीं कि भू संपदा नियमन में कोई क्रांति आ गई है। इसलिए कि 10 लाख रुपये के सेब, लगभग देशभर में सरकारी कोष से उपहारस्वरूप भेजे गए। यह उस संस्थान की बात है, जिसके किसी निर्णय से आप रुष्ट हों तो याचिका दायर करने के लिए हरियाणा जाना पड़ेगा। यानी एचपी रेरा की एपीलेट अथारिटी हरियाणा रेरा है। हिमाचल प्रदेश में याचिका सुनने का प्राधिकरण छोटे प्रदेश पर पड़ने वाले वित्तीय संकट की दलील देकर नहीं बनाया गया। वित्तीय संकट का नाम लेकर हिमाचल प्रदेश के आत्मसम्मान और पहचान को छलनी किया गया। क्या पड़ोसी राज्य की उसी संस्था को याचिका सुनने का अधिकार देकर इस विचार को ताकत नहीं दी गई कि वित्तीय संकट और बढ़े तो कल को और महत्वपूर्ण कार्यालय बंद कर पड़ोसी राज्यों के कार्यालयों से काम चलाया जाए?

जी! चर्चा में उपहार के सेब हैं। हाल में एचपी रेरा के पहले अध्यक्ष पद पर कार्यकाल पूरा करके गए, राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ आइएएस अधिकारी श्रीकांत बाल्दी कहते हैं कि 'सेब दिए तो क्या हुआ। अपने संबंधियों को नहीं दिए, अधिकारियों को दिए।' अच्छी बात यह है कि प्रेम कुमार धूमल सरकार, वीरभद्र सिंह सरकार और कुछ समय जयराम ठाकुर सरकार में वित्त सचिव और कालांतर में मुख्य सचिव रहे अधिकारी स्पष्ट हैं कि सेब देकर कुछ गलत नहीं किया। ठीक बात है, उपहार संस्कृति तो व्याप्त है ही। सेब लोकपाल, केंद्र सरकार के कार्यालयों और कई प्रदेशों के मुख्य सचिवों तक गए। किंतु हैरत सेब की उन पेटियों पर होती है जो राजस्थान की ओर थोक में दौड़ीं। काश, सेब की पेटियां बोल पातीं कि वे कि किस महफिल को गुलजार करने का दायित्व लेकर गईं। राजस्थान से हिमाचल प्रदेश का संबंध पौंग बांध से भी है... जहां का पानी रेगिस्तान को शीतल करने का प्रयत्न करता है, किंतु हिमाचल प्रदेश के हिस्से में विस्थापन तो आता है, अनूपगढ़, घड़साना धूप और कांटों पर भी अधिकार इतने दशकों तक नहीं मिला।

शायद, कभी वह प्रयोजन, हित और आवश्यक-आवश्यकता सार्वजनिक हो कि राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग सचिव और मुख्य सचिव, राजस्थान शिक्षा विभाग का हिमाचल प्रदेश रेरा के साथ कौन सा संबंध है। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो संस्था अपने विरुद्ध याचिका सुनने के कार्यालय का खर्च नहीं उठा सकती, वह सेब खरीद के लिए क्यों तैयार हुई। एचपीएमसी से हुई यह खरीद सरकारी दस्तावेजों का अभिन्न अंग है। एचपीएमसी वही निगम है, जिसका जूस चेन्नई, कोलकाता और मुंबई रेलवे जंक्शन समेत देश के कई अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी मिलता था। अब यह निगम भी सहोदर निगमों और बोर्डों की तरह घाटे में है। लेकिन उसे तो एचपी रेरा के रूप में ग्राहक ही नहीं, गुणग्राहक भी मिला। अब यह भी सामने आना चाहिए कि सरकारी पैसे से हुई यह खरीद आडिट में आपत्ति की पात्र बनी या नहीं। दोनों ही स्थितियों में सरकार को सक्रिय होना चाहिए।

बात दस लाख रुपये के सेब भेजने की नहीं, वरिष्ठ नौकरशाहों की उस अधिकार की भावना की है, जिसके अंतर्गत चाय का कप भी सरकारी धन से पीया जाना जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। आखिर वेयरएज आई... आइएएस... कोई शब्द हैं। उपहार की प्रकृति है कि वह एक दिशा में जड़ या स्थिर नहीं रहता, वह किसी न किसी रूप में पलट कर आता है। एचपी रेरा को यह बता कर जनता का भ्रम दूर करना चाहिए कि जिन स्थानों पर उपहार भेजे गए हैं, हिमाचल प्रदेश को उनसे क्या लाभ हुआ। जिस प्रदेश का वित्तीय संकट राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा हो, वहां लंबा समय वित्त को देखते रहे अधिकारी के नेतृत्व में यह सब होना, प्रश्नों को अवसर देता है।

आइएएस भारत की वह शानदार सेवा है जो अब भी अधिसंख्य का सपना है। पहले दिन से प्राप्त वाहन और चालक और साथ ही सुरक्षाकर्मी सेवाकाल तक बने रहते हैं। उस सेवाकाल के कानूनन समाप्त होने के बाद यानी बादशाहत का एक दौर समाप्त होने के बाद, वहीं छोटी-छोटी जागीरों और सूबेदारियों के पीछे भाग कर प्रासंगिक बने रहना और ऐसे अनुरोधों का स्वीकार होना हिमाचल प्रदेश या किसी अन्य प्रदेश ही नहीं, स्वयं व्यक्ति के हित में भी नहीं होता। वह कौन सा ऊंचा स्तंभ होता है और कितना ऊंचा होता है जिस पर बैठ कर प्रश्नों को समाप्त करने के बजाय, उनकी पैदावार की जाती है। शायद अखिल भारतीय सेवाएं यह नहीं बताती कि जब भूमिका समाप्त हो जाए, रंगमंच को छोड़ देना चाहिए। यह वही हिमाचल प्रदेश है, जहां कुछ सपने आउटसोर्स पर हैं, जितनी पगार तय है, उससे कम पर हस्ताक्षर करते हैं। जहां पटवारी ही नहीं, चपरासी बनने के लिए भी इंजीनियर और पीएचडीधारक तक कतार में होते हैं कि आउटसोर्स के डंक से बच जाएं।

हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी का शिमला स्थित कार्यालय। जागरण

अच्छी बात यह है कि शहरी विकास मंत्री राजेश धर्माणी ने माना है कि रेरा का काम अन्य राज्यों के अधिकारियों को सेब बांटना नहीं है। जांच के लिए भी कहा है। क्योंकि दूध में पानी अधिक है, इसलिए मुहावरा बदलते हुए आशा है कि जांच में सेब का सेब और संतरे का संतरा अवश्य किया जाएगा।

****

152 अरब डालर का हो जाएगा खाद्य सेवा बाजार

बेंगलुरु : एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 80 अरब डालर मूल्य का भारतीय खाद्य सेवा बाजार 2030 तक 10-11 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 144-152 अरब डालर तक पहुंचने की संभावना है। रेडसीर स्ट्रैटजी कंसल्टेंसी के पार्टनर रोहन अग्रवाल ने कहा, 'क्लाउड किचन का प्लग एंड प्ले माडल मात्रा को तेजी से बढ़ाने का काम करता है, जिससे नए ब्रांड दो से तीन सालों में ही 100 करोड़ रुपये के राजस्व तक पहुंच जाते हैं।' (आइएएनएस)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के चैटजीपीटी जैसे प्लेटफार्म इंसान की आलोचनात्मक सोच का विकल्प नहीं हैं और देश लोगों की बुद्धिमता के जरिये ही प्रगति करेगा।
– मुकेश अंबानी, चेयरमैन, रिलायंस इंडस्ट्रीज

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डालर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
76,532.96	23,163.10	₹83,750	₹93,000	₹86.55	$76.77
▲ 631.55	▲ 205.85	▲ ₹910	▲ ₹1,000	▼ ₹0.02	

एक नजर में

मारुति सुजुकी इंडिया का शुद्ध लाभ 16 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली : मारुति सुजुकी इंडिया का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 16 प्रतिशत बढ़कर 3,727 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का गत वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में मुनाफा 3,207 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 38,764 करोड़ रुपये हो गई जो गत वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 33,513 करोड़ रुपये थी। (प्रेट्र)

तीन कंपनियों को मिली आइपीओ की मंजूरी

नई दिल्ली : तीन कंपनियों (वरिंदर कंस्ट्रक्शन, संभव स्टील ट्यूब्स और एलेनबैरी इंडस्ट्रियल गैसेस) को आइपीओ से 2,100 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। प्रस्तावित आइपीओ में नए जारी किए गए इक्विटी शेयरों और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयरों की बिक्री पेशकश का मिश्रण होगा। (प्रेट्र)

टाटा मोटर्स का तिमाही लाभ 22 प्रतिशत घटा

मुंबई : टाटा मोटर्स का तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 22 प्रतिशत घटकर 5,578 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,145 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ अर्जित किया था। कंपनी की परिचालन आय 1,13,575 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 1,10,577 करोड़ रुपये थी। (आइएएनएस)

डिजिटल भुगतान में वर्ष-दर-वर्ष 11.11% की वृद्धि

मुंबई : सितंबर 2024 तक देशभर में डिजिटल भुगतान में साल-दर-साल 11.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सितंबर 2024 के लिए आरबीआइ का डिजिटल भुगतान सूचकांक 465.33 है, जबकि मार्च 2024 के लिए यह 445.5 था। केंद्रीय बैंक ने मार्च 2018 में देशभर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को मापने के लिए आधार के तौर पर एक समग्र आरबीआइ-डीपीआइ का एलान किया था। (प्रेट्र)

बजट में मिल सकती है एक लाख करोड़ रुपये की राहत

राजकोषीय घाटे में कमी और अनुमान से कम पूंजीगत खर्च से सरकार के पास बनी आम लोगों की मदद करने की गुंजाइश

राजीव कुमार ● जागरण

नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे में कमी और अनुमान से कम पूंजीगत खर्च के रहने से आगामी बजट में सरकार के पास लोगों को एक लाख करोड़ रुपये तक की राहत देने की गुंजाइश दिख रही है। यह राहत इनकम टैक्स में छूट से लेकर रोजगार से जुड़ी स्कीम में दी जा सकती है। एक फरवरी को आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्च के मद में बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन अप्रैल से नवंबर तक 46 प्रतिशत ही खर्च किया जा सका है। पूंजीगत खर्च कम रहने और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान से कम रह सकता है। बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.7 प्रतिशत रह सकता है। चालू वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी से भी टैक्स छूट से लेकर अन्य स्कीम के माध्यम से लोगों की खर्च क्षमता बढ़ाने में सरकार को मदद मिलेगी। राजस्व उगाही के लिहाज से विनिवेश के मोर्चे पर निराशा के बावजूद चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह में मजबूती से 32 लाख करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में टैक्स का संग्रह जीडीपी के अनुपात में 11.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में यह अनुपात 11.7 प्रतिशत का था।

वर्ष 2015-23 के दौरान विभिन्न देशों के कर्ज की वृद्धि दर (प्रतिशत में)

देश	वृद्धि दर
चीन	9.0
ब्राजील	2.2
भारत	2.1
मलेशिया	2.0
थाईलैंड	4.8
इंडोनेशिया	4.6
रूस	3.0
मैक्सिको	1.4
वियतनाम	(-3.4)

स्रोत : एचडीएफसी बैंक

- इनकम टैक्स में छूट से लेकर रोजगार से जुड़ी स्कीम में मिल सकती है राहत
- बजट अनुमान से कम रह सकता है चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटे के साथ पूंजीगत खर्च में कमी से सरकार के पास एक लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय गुंजाइश है। सरकार इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट की सीमा बढ़ा सकती है। गरीब और किसान से जुड़ी पीएम-किसान, मनरेगा जैसी स्कीम के तहत भी आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि खपत बढ़ाई जा सके।
-साक्षी गुप्ता, प्रमुख अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक

कर्ज और ब्याज भुगतान में भी आ रही है कमी

अधिक जानकारों के मुताबिक जीडीपी के मुकाबले भारत के कर्ज का अनुपात भी कम हो रहा है। कोरोना काल में सरकार का कुल कर्ज जीडीपी का 88.4 प्रतिशत तक पहुंच गया था जो पिछले वित्त वर्ष में 83 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना महामारी के बावजूद वर्ष 2015-23 के दौरान देश की सरकार पर कर्ज की बढ़ोतरी दर 2.1 प्रतिशत है जबकि चीन की सरकार पर पिछले आठ सालों में कर्ज के बोझ में नौ प्रतिशत का इजाफा हुआ है। राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान की हिस्सेदारी भी कम हो रही है। कोरोना काल के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्ति का 41.6 प्रतिशत हिस्सा ब्याज भुगतान में चला जाता था जो चालू वित्त वर्ष में 37.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

वित्त वर्ष	हिस्सेदारी
2020-21	41.6
21-22	37.1
22-23	39
23-24	39.4
(अनुमानित) 24-25	37.2

अनधिकृत सलाह देने वालों से लेनदेन नहीं कर सकेंगे मध्यस्थ

नई दिल्ली, प्रेट्र : मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बुधवार को कहा कि पंजीकृत मध्यस्थों को अनधिकृत सलाह देने या अस्वीकृत रिटर्न दावे करने में लगे किसी भी व्यक्ति के साथ लेनदेन करने या ग्राहक की जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है। सेबी ने एफएक्यू का ब्योरा जारी करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया है। सेबी ने कहा, 'ग्राहक की जानकारी साझा करना' ग्राहक का नाम सुझाने जैसी प्रकृति का हो सकता है। इसलिए, ऐसे किसी भी व्यक्ति से भुगतान लेना-देना या ग्राहक की जानकारी साझा करने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जानकारी से एक प्रकार जुड़ाव होगा और इसकी अनुमति नहीं है।' सेबी के मुताबिक, जुड़ाव शब्द में पैसे का कोई भी लेनदेन, ग्राहक का नाम सुझाना, जानकारी साझा करना या किसी भी समान प्रकार का संबंध शामिल है। हालांकि सेबी ने कहा कि उसके द्वारा विनियमित व्यक्ति और उनके एजेंट ब्रांडिंग, विपणन या प्रचार गतिविधियों के लिए दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं, बशर्ते दूसरा व्यक्ति अनधिकृत सलाह देना या अस्वीकृत रिटर्न का दावा करने जैसी निषिद्ध गतिविधियों में शामिल न हो।

आइटी के शेयरों में खरीदारी से बाजार लगातार दूसरे दिन चढ़ा

मुंबई, प्रेट्र : वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी), पूंजीगत उत्पाद और औद्योगिक शेयरों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 631.55 अंक उछलकर 76,532.96 पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी 205.85 अंक बढ़कर 23,163.10 पर पहुंच गया। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, 'आगामी बजट की प्रत्याशा में भारतीय बाजार ने लचीलापन दिखाया है। माना जा रहा है कि इसमें उपभोग और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जा सकते हैं।'

सोना नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली, प्रेट्र : आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की भारी खरीदारी से बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 910 रुपये बढ़कर 83,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक जनवरी से अब तक सोने के दाम 4,360 रुपये की वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग में निवेश किए गए एक रुपये से जीडीपी में तीन गुने की वृद्धि

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में किए गए निवेश से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इससे ना केवल अर्थव्यवस्था में अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है बल्कि लोगों की आय भी बढ़ी है।

आइआइएम-बैंगलोर द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि राजमार्ग निर्माण पर व्यय किए प्रत्येक एक रुपये ने देश की जीडीपी में 3.21 गुना का योगदान दिया है। 2013 से 2022 तक किए गए अध्ययन के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से घरेलू आय में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि घरेलू व्यय में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, कार बिक्री में 10.4 प्रतिशत की दोहरे अंकों की वृद्धि हुई है। देश में राजमार्गों के विकास से कारखानों और कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले स्त्रोतों के बीच परिवहन लागत में लगभग तीन प्रतिशत की कमी आई है और कारखानों और तैयार उत्पाद खरीदने वाले ग्राहकों के बीच 1.33 प्रतिशत की कमी आई है।

- घरेलू आय में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि घरेलू व्यय में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी

100 से अधिक जिलों में किए गए सर्वे पर आधारित है अध्ययन

अध्ययन 100 से अधिक जिलों में किए गए व्यापक सर्वे पर आधारित है। राजमार्ग प्राधिकरण ने 2023-24 में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर रिकार्ड 2.07 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। यह अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय और 2022-23 में खर्च किए गए 1.73 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.72 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई पिछले 10 वर्षों में 60 प्रतिशत बढ़कर 2014 के 91,287 किमी से 2024 में 146,195 किमी हो गई है।

उद्योग जगत को अगले वित्त वर्ष में 6-6.9% वृद्धि की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : उद्योग जगत को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 6.0-6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जिसे उन्नत प्रौद्योगिकी और कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के लिए सुधारों से समर्थन हासिल होगा। यह रिपोर्ट ग्रांट थार्नटन की तरफ से कराए गए बजट-पूर्व सर्वेक्षण पर आधारित है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकांश लोगों को वित्त वर्ष 2025-26 में 6.0-6.9 प्रतिशत के बीच वृद्धि होने की उम्मीद है। लगभग 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तो 7.0-7.9 प्रतिशत की सीमा में मजबूत वृद्धि दर की उम्मीद जताई है। उत्तरदाताओं का मानना है कि प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और कारोबारी सुगमता को बेहतर बनाने के सुधार अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें कहा गया है, 'राजकोषीय नीतियों को इन प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर, आगामी बजट अर्थव्यवस्था में समानता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए वृद्धि के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है।'

ग्रांट थार्नटन के बजट पूर्व सर्वे में 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं को 2025-26 में 7.0-7.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि की उम्मीद

राष्ट्रीय फलक

राज्यों में आपदा शमन परियोजनाओं के लिए 3,027 करोड़ रुपये मंजूर

- अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने दी मंजूरी
- सबसे अधिक सूखा प्रभावित 12 राज्यों को 2022.16 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में आपदा शमन के लिए 3027.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केन्द्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली इस समिति ने 10 राज्यों के ऐसे 50 जिलों में बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के लिए बिजली सुरक्षा से संबंधित शमन परियोजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा की जो बिजली गिरने की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित हैं। साथ ही, उच्च स्तरीय समिति ने सबसे अधिक सूखा प्रभावित 12 राज्यों के 49 जिलों को उत्प्रेरक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से फंडिंग के प्रस्तावों पर भी विचार किया।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उच्च स्तरीय समिति ने सबसे अधिक सूखा प्रभावित 12 राज्यों को उत्प्रेरक सहायता के लिए 2022.16 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 1200 करोड़ रुपये होगा। जिन 12 राज्यों के लिए यह धनराशि मंजूर की गई है उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

समिति ने 10 राज्यों में कुल 186.78 करोड़ रुपये की लागत से बिजली सुरक्षा से संबंधित शमन परियोजना को भी मंजूरी दी है। इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

गृह मंत्री ने 19 राज्यों के उच्च प्राथमिकता वाले 144 जिलों में 818.92 करोड़ रुपये के कुल व्यय के वन अग्नि प्रबंधन हेतु शमन परियोजना को भी मंजूरी दी है।

अमित शाह। फाइल

एमएसएमई के लिए नई ऋण गारंटी योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज को कवर करने वाली एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। एमएसएमई के लिए म्युचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (एमसीजीएस-एमएसएमई) को शुरू करने का उद्देश्य राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए पात्र एमएसएमई को मंजूर 100 करोड़ रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए 60 प्रतिशत गारंटी कवरेज प्रदान करना है। योजना का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उनके पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या होनी चाहिए, गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना परिचालन दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से चार साल की अवधिक के दौरान या सात लाख करोड़ रुपये की संचयी गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगी।

बिहार में राजद विधायक ने खरीदी श्रीराम-जानकी के नाम से दर्ज जमीन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

- दाखिल-खारिज के लिए विधायक की ओर से दिए आवेदन की जांच में मामला उजागर
- विधायक ने कहा- उनके साथ की गई धोखाधड़ी, विक्रेता के विरुद्ध दर्ज कराएंगे मुकदमा

बिहार में देवी-देवताओं के नाम की जमीन की बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। जमीन की खरीद-बिक्री राजस्व कर्मचारी से लेकर माननीय भी कर रहे हैं। ताजा मामला मुशहरी अंचल के फतेहपुर मौजा का है। यहां श्रीराम-जानकी मठ की 12 डिसमिल (5,226.72 वर्ग फीट) बेशकीमती जमीन 45.35 लाख रुपये में बोचहां के राजद विधायक अमर कुमार पासवान ने पिछले साल खरीदी। मामला तब उजागर हुआ जब मुशहरी के अंचलाधिकारी महेंद्र शुक्ला ने विधायक की खरीदी गई उक्त जमीन के दाखिल-खारिज आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया कि यह भूमि श्रीराम-जानकी के नाम से सरकारी दस्तावेज में दर्ज है।

आवेदन अस्वीकृत करने से पहले विधायक को जमीन के विक्रेता के स्वामित्व का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। विधायक की ओर से इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। विधायक ने पिछले साल 23 फरवरी को मुशहरी अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज का आवेदन दिया था। 23 जनवरी को सीओ ने स्वामित्व का साक्ष्य नहीं मिलने पर विधायक के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। इस संबंध में विधायक अमर पासवान ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं ठगा गया हूं। मेरी बड़ी राशि भी गई और जमीन भी मेरे नाम नहीं हुई। इसके लिए मैं विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा।

मणिपुर के चूड़चंदपुर में सुरक्षाबलों ने छह राकेट जब्त किए

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर के चूड़चंदपुर जिले में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने छह राकेट जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, हेंगलेप पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लोइलमकोट और नालोन क्षेत्र से सुरक्षाबलों ने मंगलवार को छह राकेट, एक लांचर, एक देशी मोर्टार, एक-एक 7.62 एमएम स्नाइपर राउंड और स्नाइपर मैगजीन तथा अन्य सामान जब्त किया। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी)-पीडब्ल्यूजी के दो कार्यकर्ताओं को मंगलवार को इंफाल पूर्वी जिले के मोरोक इनखोल गांव से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि वे इंफाल के विभिन्न इलाकों में आम जनता, सरकारी अधिकारियों और दुकानों से जबरन वसूली में शामिल थे। उनके कब्जे से नौ एमएम की एक पिस्तौल, मैगजीन के साथ नौ एमएम के सात कारतूस जब्त किए गए हैं।

शिवकुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक से पूछा सवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए सीबीआइ को दी गई सहमति वापस लेने को चुनौती देने के सिलसिले में भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल (यतनाल) से सवाल किए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा के विधायक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर से कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता राजनीतिक लाभ के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप यहां क्यों हैं? राजनीतिक लाभ के लिए? परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है और यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, क्योंकि सीबीआइ ने भी अपील दायर की है।

महाराष्ट्र में जीबीएस से महिला की मौत का संदेह, 16 नए मामले मिले

- राज्य में अभी तक मिले जीबीएस के 127 संदिग्ध मरीज
- 72 मरीजों में हुई है जीबीएस की पुष्टि, 20 वेंटिलेटर पर

पुणे, प्रेट्र : महाराष्ट्र में गुलियन बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि राज्य में बीमारी के 16 नए मामले मिले हैं। रविवार को भी सोलापुर के एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जीबीएस से मौत हो गई थी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुणे की एक 56 वर्षीय महिला की सरकारी ससून जनरल अस्पताल में जीबीएस से मौत हो गई है, उसे अन्य बीमारियां भी थीं। स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में बताया कि अभी तक जीबीएस के 127 संदिग्ध मरीज मिले हैं और इनमें से नौ पुणे जिले से बाहर के हैं। 72 मरीजों में जीबीएस की पुष्टि हो चुकी है और 20 मरीज फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। बयान के अनुसार, अभी तक मल के 121 नमूने शहर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी (एनआइवी) में भेजे गए हैं और सभी का परीक्षण किया गया है। 21 नमूनों में नोरो वायरस और पांच नमूनों में कैंपिलोबैक्टर की पुष्टि हुई है। रक्त के 200 नमूने भी एनआइवी भेजे गए हैं और सभी नमूनों में जीका, डेंगू व चिकनगुनिया की पुष्टि नहीं हुई है।

जीबीएस न्यूरोलाजिकल आटोइम्यून बीमारी है। जीबीएस मरीजों में प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ नसों पर हमला करती है, जिससे नसें कमजोरी हो जाती हैं।

प्रतीकात्मक

एंबुलेंस पलटने के बाद भाग रहे कर्मी की भीड़ ने पीटकर कर दी हत्या

जासं, अतरी (गया) : बिहार में गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र अंतर्गत ढकनी-बी गांव से मंगलवार की रात गर्भवती एवं आशा समेत पांच महिलाओं को लेकर अस्पताल जा रही एंबुलेंस पलट गई। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने उसे घेर लिया। एंबुलेंस का एक कर्मी हत्थे चढ़ा तो उसे भीड़ ने पीटकर मार डाला। नीमचक बथानी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि एंबुलेंस सवार गर्भवती समेत अन्य महिलाएं सुरक्षित हैं।

एंबुलेंस चालक मुन्ना कुमार ने मामले में सात लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई है। चालक ने बताया कि ग्रामीणों के तेवर देख वह और तकनीकी कर्मी कुंदन कुमार एंबुलेंस से निकलकर भागने लगे। कुछ लोगों ने पीछाकर उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस उसे गंभीर स्थिति में स्थानीय अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

****

आर्टिफिशियल नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करो चैटजीपीटी : मुकेश अंबानी

- पं. दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन

अहमदाबाद, प्रेट्र : दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से जुड़े नए-नए अपडेट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने छात्रों को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने कहा, ''अगर बात करें एआइ की तो मेरे पास हमारे युवा छात्रों के लिए एक सुझाव है। आपको एक टूल की तरह एआइ का इस्तेमाल करने में अच्छा होना चाहिए, लेकिन आपको खुद की गंभीर सोच नहीं खत्म करनी चाहिए। चैटजीपीटी का जरूरत से इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो आर्टिफिशियल बुद्धि से नहीं खुद की बुद्धि से। हम आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ सकते हैं।''

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह बात पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा, 'एआइ आधारित चैटजीपीटी जैसे टूल, इंसान की अपनी असल सोच का पर्याय नहीं हैं। हमारा देश हमारे लोगों की खुद की बुद्ध से तरक्की करेगा, एआइ से नहीं। तेजी से बेहतर होती तकनीक के इस वक्त में लगातार सीखते रहने की इच्छा एक विकल्प नहीं है, यह बने रहने और सफल होने के लिए जरूरी है। इसलिए उत्सुकता को अपनाइए और कभी भी सीखना मत बंद कीजिए।'

यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा और दुनिया की कोई ताकत भारत की इस तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकती। इस सदी के अंत तक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध राष्ट्र बनेगा, लेकिन इस तरक्की से हमारे ग्रह को खतरा नहीं होना चाहिए और जलवायु संकट और ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। इसलिए जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। इस दौरान मौजूद कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और निदेशक उदय कोटक ने छात्रों से कहा, ''आप जीवन में जो भी करें, हमेशा गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर फोकस रखें। अगर हम यह दोनों हासिल कर लेते हैं, तब पैसों समेत हर चीज का नतीजा आएगा। पैसों के पीछे मत भागिए, उत्कृष्टता के पीछे भागिए।

मुकेश अंबानी। फाइल

ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों को आठ महीने का वेतन लेकर नौकरी छोड़ने का दिया विकल्प

बड़ा कदम ▸ कर्मचारियों की संख्या कम करने की कवायद, लाखों को भेजे गए ईमेल

छह फरवरी तक विकल्प चुनने का दिया समय

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड प्रशासन की ओर से सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने की कवायद शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को सभी संघीय कर्मचारियों को करीब आठ महीने का वेतन लेकर नौकरी छोड़ने का विकल्प दिया है। लाखों कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि जो स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे उन्हें लगभग आठ महीने का वेतन मिलेगा, लेकिन उन्हें छह फरवरी तक ऐसा करने का विकल्प चुनना होगा।

मानव संसाधन एजेंसी की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो कर्मचारी वर्क फ्राम होम कर रहे हैं उन्हें पूर्णकालिक रूप से कार्यालयों में लौटने का आदेश दिया गया है। ईमेल में कहा गया है कि अगर आप संघीय कार्यबल में वर्तमान भूमिका को जारी नहीं रखना चुनते हैं तो हम देश के लिए आपकी सेवा करने के लिए धन्यवाद देंगे और इस इस्तीफा कार्यक्रम का उपयोग कर संघीय सरकार से सम्मानजनक तरीके से नौकरी छोड़ने का अवसर दिया जाएगा। यह योजना छह फरवरी तक सभी संघीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। अगर आप इस योजना के तहत इस्तीफा देते हैं, तो आप अपने दैनिक कार्यभार की परवाह किए बिना सभी वेतन और लाभ बरकरार रखेंगे और 30 सितंबर तक सभी कार्य से छूट दी जाएगी। ईमेल में इसे स्वीकार करने के निर्देश भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो ईमेल पर उत्तर देना चुनें। अपने सरकारी अकाउंट से उत्तर दें। इस ईमेल के मुख्य भाग में इस्तीफा शब्द टाइप करें और भेजें पर क्लिक करें।

ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर निकालने का आदेश

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सेना से सभी ट्रांसजेंडर सैनिकों को बाहर निकालने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि जो कोई भी जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित है, वह सेना में सेवा नहीं कर सकता। इस आदेश की कई कार्यकर्ता समूहों ने निंदा की है। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश में कहा कि लिंग शब्द को हटाकर इसे सेक्स शब्द से बदलकर संघीय सरकार में बायलाजिकल ट्रूथ को बहाल किया जाएगा। सेना में इनकी संख्या अनुमानतः नौ हजार से 12,000 के बीच है, लेकिन अधिकारियों के लिए उनकी पहचान बेहद मुश्किल होगी। चिकित्सा गोपनीयता कानूनों के कारण जानकारी सीमित है। ट्रंप के नए आदेश से सेना में हलचल मचने की संभावना है।

संघीय अनुदानों, ऋणों और विदेशी सहायता रोकने के ट्रंप के आदेश पर अस्थायी न्यायिक स्थगन

संघीय न्यायाधीश ने वित्त पोषण को रोकने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यायाधीश लारेन एल. अलीखान का आदेश फंडिंग पर रोक लागू होने से कुछ मिनट पहले आया। ट्रंप ने मंगलवार को सभी संघीय अनुदानों एवं ऋणों पर रोक लगा दी थी। उनके इस फैसले से शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आवासीय सहायता, आपदा राहत और कई अन्य योजनाएं बाधित हो सकती थीं। न्यायाधीश ने कहा कि उनके फैसले का उद्देश्य यथास्थिति बनाए रखना था। यह ट्रंप प्रशासन को नए कार्यक्रमों के लिए फंडिंग रोकने से नहीं रोकता या पहले ही समाप्त हो चुकी फंडिंग को फिर से शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

अमेरिका ने शुरू की अगली पीढ़ी की मिसाइल रक्षा योजना

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से अपने देश को बढ़ते खतरों को देखते हुए मिसाइल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने का आदेश दिया है। कार्यकारी आदेश में इसे इस तरह तैयार करने कहा गया है, जिससे इन खतरों से बचाव हो सके। योजना का एक प्रमुख घटक यह सुनिश्चित करना होगा कि मिसाइल हमले की स्थिति में प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की जा सके।

व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में इंटरनेट मीडिया के लोगों को भी मिलेगी जगह

- ब्रीफिंग रूम में आगे की पंक्ति की सीट अब 'न्यू मीडिया सीट' कहलाएगी
- यहां पाडकास्टर, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर आदि को दी जाएगी जगह
- राष्ट्रपति ट्रंप के संदेश को व्यापक रूप से साझा करना है इसका उद्देश्य

व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट। रायटर

वाशिंगटन, प्रेट्र : बड़ी संख्या में लोग, खासकर युवा खबरों से जुड़े रहने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं। इसे देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वह पाडकास्टर, कंटेंट क्रिएटर सहित अन्य इंटरनेट मीडिया आउटलेट के प्रतिनिधियों को व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग रूम में सीटें आवंटित करेगा। उन्होंने इन सभी के लिए 'न्यू मीडिया' नाम दिया है।

27 वर्षीय प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के नेतृत्व में इस कदम का उद्देश्य उन समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, जिनकी पहले ब्रीफिंग रूम में उपस्थिति नहीं थी। लेविट अमेरिकी इतिहास में सबसे कम उम्र की व्हाइट हाउस प्रेस सचिव हैं।

लेविट ने मंगलवार को अपनी पहली दैनिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि लाखों अमेरिकी, विशेष रूप से युवा टेलीविजन और समाचार पत्रों से दूर पाडकास्ट, ब्लाग, इंटरनेट मीडिया के अन्य माध्यम से समाचार प्राप्त कर रहे हैं। हमारी टीम के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के संदेश को व्यापक रूप से साझा करना और व्हाइट हाउस को 2025 के उभरते मीडिया परिदृश्य के अनुकूल बनाना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने स्वतंत्र पत्रकारों, पाडकास्टरों, इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को वेबसाइट Whitehouse.gov/newmedia के माध्यम से व्हाइट हाउस प्रेस क्रेडेंशियल्स के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। ब्रीफिंग रूम में आगे की पंक्ति की सीट को अब 'न्यू मीडिया सीट' नामित किया जाएगा।

अब तक यह परंपरागत रूप से प्रेस सचिव के कर्मचारियों के लिए आरक्षित होती थीं। आवेदनों की समीक्षा लेविट की टीम द्वारा की जाएगी और जो लोग मानदंडों को पूरा करेंगे और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मानकों आवश्यकताओं को पूरा करेंगे उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

दुर्घटनावश घायल हुए भारतीय मछुआरे : श्रीलंकाई नौसेना प्रमुख

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका की नौसेना के प्रमुख ने बुधवार को भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की घटना को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटनावश हुई फायरिंग में भारतीय मछुआरे घायल हुए। मंगलवार की सुबह डेल्फ्ट द्वीप के निकट श्रीलंकाई नौसेना द्वारा की गई फायरिंग में पांच भारतीय मछुआरे घायल हुए थे। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना 13 भारतीय मछुआरों को पकड़ने के दौरान हुई। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई दिल्ली में श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया और अपना विरोध दर्ज कराया है। भारत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी परिस्थिति में बल का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है।

फायरिंग के बाद श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल कंचना बनगोडा ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, नौसेना के एक जवान द्वारा दुर्घटनावश चलाई गई गोली से दो भारतीय मछुआरे घायल हो गए।

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि नौसैनिकों ने संदेह के आधार पर श्रीलंकाई जलक्षेत्र में एक भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाज पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उसने क्षेत्र छोड़ने के निर्देश का पालन नहीं किया था। इधर, जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने अस्पताल में घायल मछुआरों से मुलाकात की। उन्होंने मछुआरों के जल्द ठीक होने की कामना की।

ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाने में जुटे किम जोंग उन

परमाणु सामग्री बनाने वाले एक संयंत्र के निरीक्षण के दौरान उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन। रायटर

सियोल, एपी : उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने परमाणु सामग्री बनाने वाले एक संयंत्र का निरीक्षण किया और देश की परमाणु क्षमता को मजबूत करने की अपील की। उनके इस कदम को अमेरिका के ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह कूटनीति को फिर से शुरू करने के लिए किम से बात करने को तैयार हैं।

उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी केसीएनए के अनुसार, किम ने परमाणु सामग्री उत्पादन संयंत्र और परमाणु हथियार संस्थान जाकर निरीक्षण किया। हालांकि उसने इसे नहीं बताया कि ये केंद्र कहां स्थित हैं और कब इन जगहों का दौरा किया।

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान किम से तीन बार मुलाकात की थी। गुरुवार को फाक्स न्यूज पर प्रसारित एक इंटरव्यू में ट्रंप ने किम को एक समझदार व्यक्ति बताया। किम से संपर्क करने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह उनसे बात करेंगे।

अंतरिक्ष से सुनीता को मार्च तक वापस लाने का आदेश

- सात महीने से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हैं विलियम्स व विल्मोर
- 237 दिनों में चलना भूलीं सुनीता, आज कर सकती हैं स्पेसवाक

नई दिल्ली, आइएएनएस : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को कहा कि वह नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को मार्च अंत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापस ले आए। इन अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय से वापसी का इंतजार है। वहीं, एलन मस्क ने भी अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि यह बहुत ही भयावह है कि बाइडन प्रशासन ने इन अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय से वहां पर छोड़ दिया है। सुनीता विलियम्स जून 2024 में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर आने के बाद वापस धरती पर इसलिए नहीं लौट पाईं थीं कि उन्हें लाने वाला अंतरिक्षयान स्टारलाइनर खराब हो गया था। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अगस्त तक लौटना था।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नासा की 59 वर्षीय अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने विगत 27 जनवरी को अमेरिका के नीधम हाइस्कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि लगातार 237 दिनों से स्पेस स्टेशन में रहते हुए कैसा लगता है। विलियम्स ने कहा, 'अब मुझे याद करना पड़ रहा है कि चलना कैसे है? मैं अरसे से चली नहीं हूं। नीचे बैठी नहीं हूं। मैं लेटी भी नहीं हूं। हालांकि यहां ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप बस आंखें मूंदे रखिये और यहां तैरते रहिये।'

सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में दो बार के मिशनों को मिलाकर कुल 322 दिन रहीं हैं। उम्मीद की जा रही है कि सुनीता विलियम्स इस गुरुवार को स्पेसवाक कर सकती हैं।

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ डोनाल्ड पेटिट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। इसका वीडियो ग्रैब नासा ने 26 नवंबर 2024 को जारी किया था। फाइल/रायटर

सऊदी अरब में सड़क हादसे में नौ भारतीयों की मौत

- पश्चिमी सऊदी अरब के जीजान के पास हुई सड़क दुर्घटना
- जयशंकर ने हादसा व जानमाल के नुकसान पर जताया दुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : पश्चिमी सऊदी अरब के जीजान में एक सड़क दुर्घटना में नौ भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। दूतावास ने कहा कि वह पूरी सहायता प्रदान कर रहा है और अधिकारियों तथा पीड़ित परिवारों के संपर्क में है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वह दुर्घटना और जानमाल के नुकसान के बारे में जानकर 'दुखी' हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'जेद्दा में हमारे महावाणिज्यदूत से बात की, जो संबंधित परिवारों के संपर्क में हैं। वह इस दुखद स्थिति में पूरा समर्थन दे रहे हैं।'

दूतावास ने एक्स पर कहा, 'हम सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र में जीजान के पास एक सड़क दुर्घटना में नौ भारतीय नागरिकों की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं। जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास

एस जयशंकर। फाइल

पूरी सहायता प्रदान कर रहा है और अधिकारियों तथा परिवारों के संपर्क में है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8002440003 (टोल फ्री), 0122614093, 0126614276, 0556122301 (वाट्सएप) स्थापित की गई है।'www

ब्रिटेन की रिपोर्ट में कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद और खालिस्तान परस्त चरमपंथ को बताया खतरा

- ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की एक लीक रिपोर्ट में इन्हें खतरे के रूप में चिह्नित किया गया
- गृह सचिव कार्यालय ने बताया, रिपोर्ट के निष्कर्षों पर मंत्रियों की अभी औपचारिक सहमति नहीं

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के गृह मंत्रालय की लीक हुई एक रिपोर्ट में 'कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद' और 'खालिस्तान समर्थक चरमपंथ' को ब्रिटेन में चरमपंथ के नए खतरों के रूप में दर्शाया गया है। मंत्रालय की यह रिपोर्ट फिलहाल ब्रिटिश सरकार की नीति नहीं है। यह रिपोर्ट गृह सचिव यवेट कूपर द्वारा तैयार की गई थी। उनके कार्यालय ने कहा है कि रिपोर्ट के निष्कर्षों पर मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप से सहमति नहीं दी गई है।

गौरतलब है कि ब्रिटेन सरकार की 'चरमपंथ समीक्षा' पर लीक हुई रिपोर्ट में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न दो प्रकार के चरमपंथ - खालिस्तान समर्थक चरमपंथ और हिंदू राष्ट्रवादी चरमपंथ - को खतरे के रूप में चिह्नित किया गया है। पालिसी एक्सचेंज थिंक टैंक के लिए एंड्रयू गिलिगन और डा पाल स्काट द्वारा लिखित चरमपंथ समीक्षा रिपोर्ट को इस सप्ताह की शुरुआत में जारी किया गया। ऐसी समीक्षा रिपोर्ट में पहली बार 'हिंदू राष्ट्रवादी चरमपंथ' का उल्लेख किया गया है।

बहरहाल, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के सुरक्षा मंत्री डैन जार्विस ने मंगलवार को हाउस आफ कामंस को बताया कि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि रिपोर्ट का कौन सा संस्करण लीक हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके दावे सरकारी नीति को प्रतिपादित नहीं करते हैं। गृह सचिव यवेट कूपर ने पिछले साल अगस्त में लेबर पार्टी की सरकार की चरमपंथ पर नीति निर्धारित करने के लिए 'रैपिड एनालिटिकल स्प्रिंट' का आदेश दिया था।

लीक हुई रिपोर्ट के अनुसार, इसमें नौ प्रकार के चरमपंथ - 'इस्लामवादी, चरम दक्षिणपंथी, महिलाओं के प्रति द्वेष, खालिस्तान समर्थक चरमपंथ, हिंदू राष्ट्रवादी चरमपंथ, पर्यावरण चरमपंथ, वामपंथी, अराजकतावादी और एकल-मुद्दा चरमपंथ, हिंसा एवं षड्यंत्र के सिद्धांत' - सूचीबद्ध किए गए हैं।

पालिसी एक्सचेंज थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिपोर्ट के पेज 17-18 पर दो तरह के चरमपंथ का जिक्र है जिनकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। इन्हें खालिस्तान समर्थक चरमपंथ और हिंदू राष्ट्रवादी चरमपंथ के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि, खालिस्तान समर्थक चरमपंथ के बारे में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह जरूरी नहीं कि सिख राज्य के लिए खालिस्तान के समर्थन को चरमपंथ की श्रेणी में रखा जाए, लेकिन समस्या तब होती है जब उद्देश्य पूर्ति के लिए यह दृष्टिकोण हिंसा की वकालत करे।

एअर इंडिया बम धमाके के संदिग्ध की हत्या में एक को उम्रकैद

ओटावा, प्रेट्र : कनाडा की एक अदालत ने 1985 के एअर इंडिया बम धमाके के संदिग्ध की हत्या करने वाले एक सिख कारोबारी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बीस साल तक उसे बिना पैरोल ही यह सजा काटनी होगी।

सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सिख कारोबारी रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या में ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट के जज ने मंगलवार को टैनर फाक्स को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस दौरान बीस साल तक फाक्स को कोई पैरोल नहीं मिलेगी। उल्लेखनीय है कि 15 जुलाई, 2022 को ब्रिटिश कोलंबिया के सुरे में मलिक और सह आरोपित अजायब सिंह बागरी को तब गोली मारी गई थी जब वह अपनी कार में बैठे थे। इन दोनों को इस बम धमाके और उसकी साजिश के आरोप से 2005 में मुक्त कर दिया गया था। मलिक की हत्या के दो हफ्ते बाद कनाडा की पुलिस ने फाक्स को गिरफ्तार किया था।

भारत के साथ सीमा समझौतों को रद करने की मांग करेगा बांग्लादेश

- अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार ने कही यह बात
- अगले महीने भारत-बांग्लादेश के बीच होने वाली है सीमा वार्ता

ढाका, प्रेट्र : बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा कि अगले महीने भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के महानिदेशकों की वार्ता होने जा रही है। इसमें भारत के साथ सीमा को लेकर कुछ 'असमान समझौतों' को रद करने की मांग की जाएगी। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगुआई वाली अवामी लीग सरकार के दौरान भारत के साथ हुए सभी 'असमान समझौतों' पर भी चर्चा की जाएगी।

अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा, 'भारत के साथ सीमा से संबंधित सभी तरह के समझौतों पर चर्चा होगी। बांग्लादेशी पक्ष सीमा से संबंधित कुछ 'असमान समझौतों' को रद करने की मांग करेगा।' उन्होंने भारत के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बार्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के प्रमुखों के बीच होने वाली आगामी सीमा वार्ता को लेकर पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों पर मादक पदार्थ बनाने और सीमा पार उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया है। सलाहकार ने कहा कि सीमा के 150 गज के अंदर किसी भी गतिविधि के लिए दोनों पक्षों की आपसी मंजूरी जरूरी है और इसमें एकतरफा कार्रवाई का कोई प्रविधान नहीं है। अगर विकास के मकसद से मस्जिद या मंदिर का निर्माण किया जाना है तो दोनों देशों की सहमति आवश्यक है। चौधरी ने बताया कि सीमा वार्ता के दौरान सीमा पर कथित हत्याओं और निहत्थे बांग्लादेशी नागरिकों पर गोलीबारी रोकने के संबंध में भी चर्चा की जाएगी।

बता दें कि बीएसएफ और बीजीबी के महानिदेशकों के बीच यह वार्ता 17-20 फरवरी को नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। इसमें सीमा पर बाड़ लगाने और बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी का मुद्दा चर्चा का प्रमुख एजेंडा रहेगा। यह वार्ता दो बार स्थगित हो चुकी है।

अवामी लीग करेगी विरोध प्रदर्शन

शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर फरवरी में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है।

इमरान की पार्टी ने दी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। पीटीआइ की खैबर पख्तूनख्वा इकाई के अध्यक्ष जुनैद अकबर ने राजनीतिक तनाव को बातचीत के जरिये दूर करने में सरकार की प्रतिबद्धता में कमी को लेकर यह चेतावनी दी है।

एक्सप्रेस टिब्यून समाचारपत्र के अनुसार, अकबर ने कहा कि विपक्ष की सरकार के साथ बातचीत की इच्छा को कमजोरी का संकेत माना गया है। पीटीआइ वार्ता को सफल बनाना चाहती है, लेकिन मौजूदा हालात गतिरोध का संकेत दे रहे हैं। उनके इस बयान से एक दिन पहले मंगलवार को पीटीआइ सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता में शामिल नहीं हुई थी।

हमास अब तीन इजरायली व पांच थाई बंधकों को छोड़ेगा

- युद्धविराम समझौते के तहत इन बंधकों की आज होगी रिहाई
- उत्तरी गाजा में लौटे हजारों लोगों की खुशी निराशा में बदली

यरुशलम, एपी : इजरायल के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि हमास अब तीन इजरायली और पांच थाई नागरिकों को मुक्त करेगा। गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इन लोगों की रिहाई गुरुवार को होगी। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। इससे पहले 25 जनवरी को हमास ने चार इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया था। जबकि 19 जनवरी को तीन इजरायली महिला को मुक्त किया था। इन बंधकों के बदले इजरायल करीब 300 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है।

इजरायली अधिकारी के अनुसार, रिहा होने वाले तीन इजरायली बंधकों में दो महिलाएं 29 वर्षीय अर्बेल येहुद और 19 वर्षीय अगम बर्गर और 80 वर्षीय पुरुष गादी मोजेस शामिल हैं। हालांकि उन्होंने थाइलैंड के नागरिकों के नाम नहीं बताए। हमास ने सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल में बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। उसी समय से इजरायल ने गाजा में हमास के सफाए सैन्य अभियान चला रखा था। इसमें 47 हजार से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। 15 महीने की लड़ाई के बाद यह समझौता हुआ है। इसी समझौते के तहत इजरायल की ओर से 15 महीने बाद फलस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा की ओर लौटने की अनुमति मिली है। हजारों लोग इस क्षेत्र में लौट चुके हैं, लेकिन उनकी खुशी निराशा में बदल रही है।

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे पर धोखाधड़ी का आरोप

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे नमल पर भारतीय निवेश से हेराफेरी के लिए कोलंबो हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला वर्ष 2015 से पहले का है। 38 वर्षीय नमल राजपक्षे को जून 2016 में रग्बी खेल को विकसित करने के लिए कृष होटल परियोजना के पैसे से सात करोड़ श्रीलंकाई रुपयों के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार किया गया था।

नमल राजपक्षे श्रीलंका के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। कोलंबो में स्थित कृष होटल परियोजना को निरस्त कर दिया गया तथा अधूरा निर्माण यथास्थिति में है। हाल में एक अन्य अदालत में लोगों के लिए खतरे के कारण इसकी असुरक्षित स्थिति पर सवाल उठाया गया था। अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) सरकार द्वारा 2016 से रुके हुए कृष मामले की दोबारा जांच करने के बाद पुलिस ने नमल से पूछताछ की थी।

****

राष्ट्रीय फलक

डल्लेवाल के चिकित्सा सहायता लेने की इच्छा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

- एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली, प्रेट्र : किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल द्वारा चिकित्सा सहायता लेने और चंडीगढ़ में 14 फरवरी को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें यह मांग की गई थी कि कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए।

जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता गुनिन्दर कौर गिल से कहा कि डल्लेवाल ने 28 जनवरी को मीडिया को एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे चिकित्सा सहायता ले रहे हैं

जगजीत सिंह डल्लेवाल। फाइल

और यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो 14 फरवरी को होने वाली बैठक में भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति पर भी भरोसा जताया है और उम्मीद है कि निर्धारित बैठक से कुछ समाधान निकल सकता है।" कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी भ्रम से बचने के लिए चंडीगढ़ में बैठक होने तक मामले की सुनवाई नहीं करना चाहता।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बंकर मामले में कई और तस्करों के नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : बंगाल के नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास कृष्णगंज थाना इलाके में तस्करी के लिए बनाए गए प्रतिबंधित फेंसेडिल कफ सिरप के भंडारण वाले चार बंकर मिलने के बाद इससे जुड़े प्रमुख तस्कर सुशांत घोष उर्फ लाल के बाद कई और तस्करों का नाम सामने आया है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सीमा पर और भी बंकर हैं? क्योंकि, कृष्णगंज में कफ सिरप की तस्करी का आरोपित लाल अकेला नहीं है, बल्कि कुछ अन्य नाम भी लंबे समय से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) व पुलिस की नजर में हैं।

मालूम हो कि बीएसएफ ने गत शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश सीमा के पास कृष्णगंज इलाके के नागहटा गांव में तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे चार बंकरों का राजफाश किया था।

वरुण की गेंदबाजों की रैंकिंग में लंबी छलांग, तिलक नंबर दो पर पहुंचे

वरुण चक्रवर्ती • एपी

आइसीसी टी-20 रैंकिंग

दुबई, प्रेट्र: भारत के प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा आइसीसी की बुधवार को जारी पुरुष टी-20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 25 स्थान की लंबी छलांग लगाकर गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पांच में शामिल हो गए हैं। वर्मा अब बल्लेबाजों की सूची में ट्रेविस हेड के ठीक पीछे हैं। आस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ने तिलक पर 23 अंक की बढ़त बना रखी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक इस समय शानदार लय में हैं।

भारत और इंग्लैंड के बीच अभी दो मैच बाकी हैं और तिलक के पास हेड से आगे निकलने और रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का मौका है। यह रिकार्ड वर्तमान में पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम पर दर्ज है, जो 23 साल और 105 दिन की उम्र में नंबर एक पर पहुंचे थे। तिलक की 832 अंकों की वर्तमान रेटिंग टी-20 क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा हासिल की गई चौथी सबसे बड़ी रेटिंग है। खेल के सबसे छोटे प्रारूप में भारत की तरफ से केवल सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली और केएल राहुल ही उनसे अधिक रेटिंग अंक हासिल कर पाए। अभिषेक शर्मा 59 स्थान की छलांग लगाकर 40वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन (पांच पायदान ऊपर 32वें स्थान पर) और बेन डकेट (28 पायदान ऊपर 68वें स्थान पर) को भी अच्छे प्रदर्शन का फायदा मिला है। इंग्लैंड के विरुद्ध तीसरे मैच में 24 रन देकर पांच क्रिकेट लेने वाले चक्रवर्ती अपने इस करिश्माई प्रदर्शन से गेंदबाजों की रैंकिंग में चोटी के पांच गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। उनके साथी स्पिनर अक्षर पटेल पांच पायदान ऊपर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद भारत के खिलाफ अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर टी20 अंतरराष्ट्रीय कि गेंदबाजों की रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इससे पहले वह 2023 में पहले नंबर पर पहुंचे थे। इस बीच, बार्डर गावस्कर ट्राफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। टेस्ट क्रिकेट में आलराउंडर की सूची में वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन 24वें स्थान पर पहुंच गए।

25 स्थान के लाभ के साथ टी-20 गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंचे चक्रवर्ती

चोट के कारण बाहर रहे रिंकू की पुणे में वापसी संभव

नई दिल्ली, जेएनएन: शुरुआती दो मुकाबले जीतने के बाद राजकोट में खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिली और इंग्लैंड ने सीरीज में वापसी की। पांच मैचों की सीरीज का अगला मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। पुणे की काली मिट्टी की पिच स्पिनरों की मददगार रहती है। यहां शुरुआत में बल्लेबाजों को मदद मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है तो यह स्पिन के अनुकूल होती जाती है।

भारत ने पिछले दो मैचों में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वाशिंगटन सुंदर को खिलाया है। वाशिंगटन को खिलाना समझ से परे है क्योंकि उन्होंने दो मैच में केवल दो ही ओवर गेंदबाजी की है। हालांकि चेन्नई में उन्होंने बल्ले से रन जरूर बनाए थे, लेकिन राजकोट में वह ऊपर बल्लेबाजी करने के बावजूद विफल रहे। राजकोट में मोहम्मद शमी को खिलाने के लिए अर्शदीप को बाहर किया।

पुणे में टीम संयोजन में बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार रिंकू सिंह फिट हैं और उनका पुणे में खेलना तय है। ऐसे में उनकी जगह उतरे ध्रुव जुरैल को बाहर किया जा सकता है। वहीं सुंदर की जगह अर्शदीप सिंह को फिर मौका दिया जा सकता है।

पिछले दो मुकाबलों में गेंद से प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर

रिंकू सिंह • फाइल फोटो

रशीद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी : बटलर

राजकोट: इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर का मानना है कि उनकी टीम में लेग स्पिनर आदिल रशीद सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया। बटलर ने कहा, आदिल हमारे लिए सबसे अहम खिलाड़ी है और उसके प्रदर्शन में लगातार निखार आ रहा है। उसके पास काफी विविधता है। एक कप्तान के लिए वह ट्रंपकार्ड से कम नहीं है। पिछले दोनों मैचों में उसने शानदार प्रदर्शन किया है।

बटलर ने कहा, मैं अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश हूं। लियाम लिविंगस्टन ने जबरदस्त छक्के लगाए। उसके अलावा रशीद और मार्क वुड को भी श्रेय जाता है जिन्होंने अंतिम विकेट के लिए 20 रन जोड़े। मुझे पता था कि 170 का स्कोर अच्छा है। हम इसी शैली में आगे खेलते रहेंगे।

एक नजर में

श्रीकांत थाईलैंड मास्टर्स के दूसरे दौर में पहुंचे

पाथुमथान (थाईलैंड): पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत ने बुधवार को इजरायल के दानी दुवेंको को सीधे गेम में पराजित करते हुए थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। श्रीकांत ने यह मुकाबला 21-13, 31-18 से जीता और इजरायली प्रतिद्वंद्वी पर सीधे गेम में दूसरी बार हराया। अन्य भारतीयों में एस शंकर मुथुस्वामी ने मलेशिया के जून वेई चीम को 15-21, 21-15, 21-19 से हराया। हालांकि अन्य भारतीय आयुष शेट्टी को मलेशिया के जिंग हॉंग कोक 15-21, 17-21 से हार मिली। (प्रेट्र)

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ग्रेग बेल का निधन

वाशिंगटन: अमेरिका के लंबी कूद के महान एथलीट ग्रेग बेल का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया जो एथलेटिक्स में सबसे उम्रदराज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। विश्व एथलेटिक्स के अनुसार बेल ने 25 जनवरी को अंतिम सांस ली, जिन्होंने 1956 ओलंपिक लंबी कूद के स्वर्ण पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स ने बेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह सुनकर गहरा दुख हुआ है कि 1956 मेलबर्न ओलंपिक में लंबी कूद के चैंपियन ग्रेग बेल का शनिवार को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एथलेटिक्स में सबसे उम्रदराज ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। (प्रेट्र)

श्रीलंका ने तोड़ी आस्ट्रेलिया की लगातार जीत की लय

कुआलालंपुर: श्रीलंका ने बुधवार को आस्ट्रेलिया पर 12 रन की शानदार जीत से आइसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में अपना अभियान खत्म किया। आस्ट्रेलिया ने पहले ही सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर लिया था लेकिन टीम अंतिम चार से पहले अपनी विजयी लय जारी रखने में असफल रही। चामुडी प्रबोदा की अगुआई वाले गेंदबाजी आक्रमण से श्रीलंका ने लगातार अंतराल पर विकेट झटके जिससे आस्ट्रेलिया टीम 100 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लय हासिल नहीं कर सकी और यह मुकाबला हार गई। (प्रेट्र)

दिल्ली को विजयी विदाई दिलाने उतरेंगे विराट

कोहली 13 वर्ष के बाद घरेलू क्रिकेट में करेंगे वापसी, अंतिम बार 2012 में उप्र के विरुद्ध खेला था मैच

रणजी का रण

लोकेश शर्मा • जागरण

नई दिल्ली: दिल्ली और रेलवे के बीच रणजी ट्राफी लीग मैच के प्रसारण की कोई योजना नहीं थी, लेकिन जैसे ही विराट कोहली की भागीदारी की पुष्टि हुई, इस मैच को टीवी और डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रसारित करने का निर्णय लिया गया। अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार को होने वाले इस मुकाबले को लेकर दर्शकों और प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। बुधवार शाम तक कैमरा क्रू ने प्रसारण सेटअप की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

कोहली के शामिल होने से दिल्ली टीम का मनोबल बढ़ा है। अभ्यास में खिलाड़ी बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण पहले से अधिक चुस्त नजर आए। इस दौरान कोहली खिलाड़ियों को सर्कल बनाकर सलाह देते दिखे, जिसे वे ध्यान से सुन रहे थे। कोचिंग स्टाफ और डीडीसीए में भी कोहली की वापसी को लेकर उत्साह का माहौल है। टीम के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद की जा रही है। रणजी ट्राफी के पहले चरण में खराब प्रदर्शन को भूलकर दिल्ली की टीम अब कोहली के आने से रेलवे के विरुद्ध जीत दर्ज करने के लिए तैयार दिख रही है।

प्रशंसकों के लिए विशेष इंतजाम: डीडीसीए ने दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुफ्त पेयजल की व्यवस्था की है और चार दिनों के लिए उत्तर और पुराने क्लब हाउस स्टैंड को खोलने का निर्णय लिया है। बढ़ती दर्शक संख्या को देखते हुए गेट नंबर 16 और संभावित रूप से गेट नंबर छह को भी खोला जाएगा।

स्पिन व तेज गेंदबाजों के विरुद्ध अभ्यास

विराट कोहली मंगलवार को दिल्ली के अभ्यास सत्र का मुख्य आकर्षण रहे और बुधवार को भी उनकी मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा। मैच से एक दिन पहले वह सुबह 8:00 बजे स्टेडियम पहुंचे और जिम सत्र के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 15 मिनट तक दोस्ताना फुटबाल मैच खेला जिसमें दिल्ली के मुख्य कोच सरनदीप सिंह भी शामिल थे। नेट्स पर अभ्यास से पहले कोहली ने बिना स्टिकर वाले, अपेक्षाकृत पतले बल्ले से अभ्यास किया। उन्होंने 16 गज की दूरी से फेंकी गई थ्रोडाउन गेंदों का सामना करके अपनी बल्लेबाजी शुरू की। नेट्स पर अभ्यास के दौरान कोहली ने तेज गेंदबाज नवदीप सैनी, मनी ग्रेवाल, सिद्धांत शर्मा और राहुल गहलोत का सामना किया। उन्होंने अधिकतर फ्रंट फुट शाट्स खेले और आफ-स्टंप के बाहर जाती गेंदों को छोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान वह सिद्धांत शर्मा और मनी ग्रेवाल की गेंदों से थोड़े असहज भी दिखे। इसके बाद उन्होंने स्पिनरों हर्ष त्यागी, सुमित माथुर और शिवम शर्मा के खिलाफ अभ्यास किया।

विराट कोहली • प्रेट्र

पूर्व कोच ने की कोहली की प्रशंसा

दिल्ली टीम के प्रबंधक और विराट कोहली के अंडर-17 एवं अंडर-19 कोच महेश भाटी ने कोहली की मेहनत और समर्पण को याद करते हुए कहा "विराट कोहली हमेशा एक बड़ा किट बैग लेकर चलते हैं। युवा खिलाड़ी उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस पर मैंने कहा, 'विराट, तेरी मदद कर देते हैं।' तब विराट ने जवाब दिया, 'भैया, क्या बात कर रहे हो? यह मेरे खेलने का सामान है, मैं खुद इसे उठाउंगा और लेकर जाउंगा।'

उप्र-मप्र के चमकविहीन मैच में कुलदीपक पर निगाहें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: क्रिकेट टीम का खेल है, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब टीम से ज्यादा किसी खिलाड़ी पर निगाह टिकी होती है। ऐसा ही मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच गुरुवार से खेला जाएगा। रणजी ट्राफी में दोनों ही टीमों का सफर लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के कुलदीप यादव की फिटनेस होगी। यदि वे अपनी पुरानी रंगत में लौटे तो चैंपियंस ट्राफी में भारत के लिए अहम होंगे। कुलदीप इस सत्र में पहली बार रणजी ट्राफी मुकाबला खेलने उतरेंगे। कुलदीप लंबे समय से एनसीए में रिहैबिलिटेशन में जुटे थे। हार्निया की सर्जरी के चलते वे टीम से बाहर हुए थे और इसी कारण आस्ट्रेलिया के खिलाफ बार्डर गावस्कर ट्राफी में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। अब फिट होकर वे मैदान में लौट रहे हैं और उनकी मैच फिटनेस परखने के लिए फिजियोथैरेपिस्ट भी साथ आए हैं। भारत का चैंपियंस ट्राफी में पहला मैच 20 फरवरी को है जबकि 23 को चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान से सामना होना है। इससे पहले इंग्लैंड के विरुद्ध वनडे सीरीज के लिए कुलदीप को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बुधवार को अभ्यास सत्र के दौरान कुलदीप ने गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में हाथ आजमाए। टीम में उनके अलावा शिवम मावी, बाएं हाथ के स्पिनर सौरव कुमार, कप्तान आर्यन जुयाल और करण शर्मा जैसे कई नाम हैं।

42 बार के चैंपियन मुंबई पर बड़ी जीत दर्ज करने का दबाव

मुंबई, प्रेट्र: पिछले मैच में जम्मू कश्मीर से मिली अप्रत्याशित हार के बाद गत चैंपियन मुंबई को अब गुरुवार से मेघालय के विरुद्ध शुरू हो रहे रणजी ट्राफी एलीट ग्रुप ए के अंतिम मैच में बोनस अंक लेकर बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली मुंबई टीम को जम्मू कश्मीर ने बीकेसी ग्राउंड पर पिछले मैच में पांच विकेट से हराया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी भी मुंबई को जीत नहीं दिला सकी। सिर्फ शार्दुल ठाकुर टिककर खेल सके जिन्होंने दो पारियों में 51 और 119 रन बनाए। उन्होंने दूसरी पारी में आठवें विकेट के लिए तनुष कोटियान के साथ 184 रन की साझेदारी की थी।

हरियाणा के विरुद्ध मैच में कर्नाटक के लिए खेल रहे केएल राहुल पर नजरें

बेंगलुरु: क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी कर्नाटक की टीम को एलीट ग्रुप सी के गुरुवार से शुरू हो रहे अंतिम लीग मैच में शीर्ष पर काबिज हरियाणा के विरुद्ध बोनस अंक के साथ जीत दर्ज करनी होगी और केएल राहुल की वापसी से टीम को मदद मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक के इस समय 19 और हरियाणा के 26 अंक हैं जबकि केरल के 21 अंक हो गए हैं। कर्नाटक अगर बोनस अंक (कुल सात अंक) के साथ जीतता है तो उसके 26 अंक हो जाएंगे। ऐसे में वह शीर्ष या दूसरे स्थान की टीम के रूप में क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा। गत चैंपियन केरल को तिरूअनंतपुरम में बिहार से खेलना है। बोनस अंक के बिना भी जीतने पर केरल के 27 अंक होंगे और शीर्ष पर होगा। ऐसे में हरियाणा बाहर हो सकता है क्योंकि कर्नाटक के उससे ज्यादा अंक होंगे।

स्मिथ ने 35वां शतक जड़ा उस्मान ख्वाजा भी चमके

7 वें बल्लेबाज बने स्मिथ टेस्ट में 35 शतक लगाने वाले

10 हजार रन का आंकड़ा भी छुआ आस्ट्रेलियाई कप्तान ने

15 वें बल्लेबाज हैं स्टीव स्मिथ टेस्ट में 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले

श्रीलंका के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच के पहले दिन आस्ट्रेलिया ने दो विकेट पर बनाए 330 रन

गाल, आइएएनएस: एक रन के साथ ऐतिहासिक 10,000 रन का आंकड़ा छूने के बाद स्टीव स्मिथ ने अपना 35वां टेस्ट शतक बनाया और बुधवार को श्रीलंका के विरुद्ध पहले टेस्ट के पहले दिन आस्ट्रेलिया को 330/2 पर पहुंचने में मदद की। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक स्मिथ 104 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि उस्मान ख्वाजा 147 रन बनाकर अविजित थे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की।

पैट कमिंस की अनुपस्थिति में आस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे स्मिथ चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और सटीकता व धैर्य का परिचय देते हुए ख्वाजा के साथ मजबूत साझेदारी की। 115वां टेस्ट खेल रहे स्मिथ ने 179 गेंदों पर शतक बनाया और तीसरे सबसे तेज 35 टेस्ट शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस मामले में वह केवल रिकी पोंटिंग (195) और सचिन तेंदुलकर (200) से पीछे हैं। स्मिथ अब 35 टेस्ट शतक बनाने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह सचिन, जैक्स कैलिस, पोंटिंग, कुमार संगकारा, राहुल द्रविड़ और जो रूट की सूची में शामिल हो गए हैं।

उनकी उपलब्धि को उनके कप्तानी रिकार्ड ने और बढ़ा दिया है क्योंकि यह आस्ट्रेलिया के कप्तान के रूप में उनका 16वां टेस्ट शतक था। उन्होंने एलन बार्डर और स्टीव वा को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 15-15 शतक थे। आस्ट्रेलियाई कप्तानों में केवल पोंटिंग (19) ने ही अधिक शतक बनाए हैं। जबकि वैश्विक स्तर पर स्मिथ ग्रीम स्मिथ (25), विराट कोहली (20) और पोंटिंग के बाद चौथे स्थान पर हैं। बतौर कप्तान स्मिथ ने 4,000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं, जिसमें उनका औसत 68 से अधिक है।

इससे पहले दिन में स्मिथ 10,000 टेस्ट रन पार करने वाले 15वें बल्लेबाज बन गए। वह इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले पांचवें सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए, जो तेंदुलकर, लारा, संगकारा और पोंटिंग से पीछे हैं, ये सभी 195 या 196 पारियों में इस मुकाम तक पहुंचे थे। स्मिथ ने 205वीं पारी में यह कारनामा किया।

टेस्ट में सर्वाधिक शतक

बल्लेबाज	मैच	शतक
सचिन तेंदुलकर	200	51
जैक्स कैलिस	166	45
रिकी पोंटिंग	168	41
कुमार संगकारा	134	38
जो रूट	152	36
राहुल द्रविड़	164	36
स्टीव स्मिथ	115	35

तीन स्वर्ण जीत 14 वर्ष की धिनिधि ने रचा कीर्तिमान

जासं, हल्द्वानी: पेरिस ओलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकीं धिनिधि देसिंघु ने उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान कर्नाटक की ही तैराक हाशिका रामचंद्र का 36वें राष्ट्रीय खेलों में बनाया रिकार्ड तोड़ दिया है। धिनिधि देसिंघु ने 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 2:03:24 (दो मिनट तीन सेकेंड 24 माइक्रोसेकेंड) का रिकार्ड अपने नाम कर स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान हाशिका रामचंद्र के नाम 2:07:08 टाइमिंग का रिकार्ड था। धिनिधि ने 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले और 100 मीटर फ्री स्टाइल में भी स्वर्ण पदक झटके।

बुधवार को गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कांपलेक्स के मानसखंड तरणताल में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत महिला व पुरुषों की तैराकी में 200 मीटर फ्री स्टाइल चैंपियनशिप हुई। इसमें नया रिकार्ड बनाकर बेंगलुरु (कर्नाटक) की धिनिधि देसिंघु ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिल्ली की भाव्या सचदेवा को 2:08:68 में रजत पदक तथा महाराष्ट्र की अदिति हेगड़े को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। 100 मीटर फ्री स्टाइल में भी धिनिधि देसिंघु ने स्वर्ण पदक जीत लिया।

धिनिधि • जागरण

कर्नाटक की तैराक देसिंघु ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में बनाया नया राष्ट्रीय रिकार्ड, पहले हाशिका के नाम था यह रिकार्ड

रमिता ने क्वालीफिकेशन दौर में तोड़े कई रिकार्ड

राज्य ब्यूरो, जागरण • देहरादून: हरियाणा की रमिता जिंदल ने 10 मीटर राइफल स्पर्धा के क्वालीफिकेशन दौर में 634.9 अंक हासिल कर क्वालीफाइंग दौर में कई रिकार्ड तोड़ दिए। उन्होंने क्वालीफिकेशन दौर में 634.9 अंक बनाए। इससे पूर्व इस स्पर्धा में क्वालीफिकेशन का राष्ट्रीय रिकार्ड 634.7 अंक था, जो हरियाणा की नैंसी मंधोत्रा के नाम था। यह रिकार्ड भोपाल में आयोजित विश्व कप चैंपियनशिप के दौरान बना था। वहीं, पेरिस ओलिंपिक क्वालीफिकेशन में दक्षिण कोरियाई निशानेबाज बान ह्योजिन ने 634.5 के स्कोर के साथ ओलिंपिक रिकार्ड बनाया था। रमिता ने उनका भी यह रिकार्ड तोड़ दिया। पेरिस ओलिंपिक में वह सातवें स्थान पर रही थीं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में हरियाणा की निशानेबाज रमिता जिंदल के बाद क्वालीफिकेशन दौर में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की आर्या बोरसे (634.5) जबकि तीसरे स्थान पर तमिलनाडु की नर्मदा राजू (634.4) रहीं। इसके अलावा केरल की विदर्सा के विनोद, मध्य प्रदेश की श्रेया अग्रवाल, गुजरात की एलावेनिल वलारियन, कर्नाटक की मेघाना सज्जनार और ओडिशा की मान्यता सिंह ने भी फाइनल दौर के लिए क्वालीफाई कर लिया।

रमिता जिंदल • फाइल फोटो

मेंडोसा को हराकर गुकेश की एकल बढ़त

विज्क आन जी (नीदरलैंड्स), प्रेट्र: विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के नौवें दौर में हमवतन लियोन ल्यूक मेंडोसा को हराकर एकल बढ़त बना ली है। भारत के आर प्रगनानंद को नीदरलैंड्स के अनीश गिरी से हार मिली, जबकि पी हरिकृष्णा भी रूसी मूल के स्लोवेनियाई खिलाड़ी व्लादिमीर फेडोसीव से हार गए। डच खिलाड़ी के विरुद्ध प्रगनानंद की यह पहली हार है। जीत के बाद गुकेश ने कहा, मुझे खुशी है कि आज अच्छा खेल सका। अभी चार दौर बाकी है और मैं तालिका के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा। मैं बस अपने खेल से खुश हूं।

इस जीत के साथ ही गुकेश अब खिताब जीतने की दौड़ में सबसे आगे पहुंच गए हैं। नौ दौर के बाद उनके 6.5 अंक हो गए हैं और वह उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव से केवल आधा अंक आगे हैं। अब्दुसत्तारोव और फेडोसीव के छह अंक हैं।

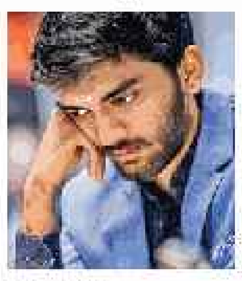
डी गुकेश •

सिटी-पीएसजी पर बाहर होने का खतरा

चैंपियंस लीग

नई दिल्ली, जेएनएन: 2023 के चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और 2020 के उपविजेता पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) पर गुरुवार को होने वाले चैंपियंस लीग मुकाबले में 10 वर्षों में पहली बार शुरुआती दौर में ही बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। पहली बार 36 टीमों के प्रारूप में हो रहे इस टूर्नामेंट में अगले दौर में केवल शीर्ष 24 टीमों को प्रवेश मिलना है। सात दौर के मुकाबलों के बाद वर्तमान रैंकिंग में पीएसजी 22वें, जबकि मैनचेस्टर सिटी 25वें स्थान पर है। बुधवार को सिटी को बेल्जियन टीम ब्रग से भिड़ना है। वहीं, पीएसजी का मुकाबला जर्मन टीम स्टुटगार्ट से होना है।

पीएसजी को यह मैच भले ही ड्रा करने से भी नाकआउट दौर में प्रवेश मिल जाएगा, सिटी के लिए यह मैच करो या मरो का होगा। पीएसजी ने एक सप्ताह पूर्व सिटी के विरुद्ध दो गोल से पिछड़ने के बावजूद 4-2 से मुकाबला जीतकर अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर कर ली है, लेकिन सिटी के लिए यह सत्र आसान नहीं रहा है। उन्हें बैलन डिओर विजेता और स्टार मिडफील्डर रोड्री की बहुत कमी खल रही है, जो चोट के कारण पूरे सत्र से बाहर हैं। 2012-13 सत्र के बाद यह पहला अवसर है जब सिटी पर पहले दौर में ही हार का खतरा मंडरा रहा है।

बदल गया है चैंपियंस लीग का प्रारूप: चैंपियंस लीग में इस बार नए प्रारूप में 32 की जगह 36 टीमें शामिल हैं। पहले ग्रुप चरण में सभी टीमों को अन्य तीन टीमों से दो-दो चरण (घरेलू, बाहर) के मुकाबले खेलने होते थे। हालांकि, इस बार ग्रुप चरण समाप्त कर एक ही लीग में सभी 36 टीमों को रखा गया है। शुरुआती दौर में सभी टीमों को ड्रा के अनुसार किन्हीं आठ टीमों से भिड़ना होगा, जिसमें चार मुकाबले घर पर जबकि चार बाहर खेलने हैं। इसके बाद शीर्ष आठ को सीधा अंतिम-16 में प्रवेश मिल जाएगा। वहीं, नौवें से 24वें स्थान पर रही टीमों को दो चरण वाले नाकआउट मैच में भिड़ना होगा। इनके विजेता अंतिम-16 में शीर्ष आठ टीमों के विरुद्ध खेलेंगे, जहां से क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक का सफर तय होगा।

सालाह, वैन जिक को लिवरपूल देगा विश्राम

लिवरपूल: शीर्ष पर चल रहा लिवरपूल बुधवार को पीएसवी एंड्होवन के विरुद्ध मुकाबले में अपने कुछ स्टार खिलाड़ियों को विश्राम देगा। पहले ही अंतिम-16 में जगह बना चुके लिवरपूल मुख्य टीम की जगह नीदरलैंड्स में 'बी' टीम के साथ उतरेगी। इस मुकाबले में टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सालाह, वैन जिक, ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड, एलिसन बेकर, इब्राहिम कोनाटे समेत कुल नौ खिलाड़ियों को विश्राम दिया गया है।

एटलांटा के विरुद्ध स्जेस्नी करेंगे गोलकीपिंग: फ्लिक

बार्सिलोना: कोच हैंसी फ्लिक एटलांटा के विरुद्ध अंतिम मुकाबले में पोलिश गोलकीपर वोज्शिएक स्जेस्नी पर भरोसा जताएंगे। मार्क आंद्रे स्टेजेन के चोटिल होने के बाद से बार्सिलोना के लिए इनाकी पेना मुख्य गोलकीपर रहे हैं। वहीं, स्टेजेन के चोटिल होने के बाद टीम से जुड़े स्जेस्नी ने पिछले सप्ताह बेनफिका के विरुद्ध मुकाबले में गोलकीपिंग की थी और इस मैच में बार्सिलोना ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच अपने नाम किया था।

गुरुवार, 30 जनवरी, 2025

आनलाइन सिक्योरिटी

डाटा सुरक्षा के लिए नया फीचर

एंड्रायड डिवाइसेज की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए गूगल ने एक महत्वपूर्ण फीचर 'आइडेंटिटी चेक' की शुरुआत की है। यूजर के पासकोड, पिन या पासवर्ड के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने में गूगल का नया फीचर उपयोगी होगा। नया अपडेट ऐसे मामले में पहले यूजर की पहचान को सत्यापित करेगा। संवेदनशील अकाउंट या डिवाइस सेटिंग के एक्सेस के पहले यूजर को अपने फिंगर प्रिंट या फेस रिकग्निशन के जरिए सत्यापित करना होगा। खास बात है कि सिक्योरिटी की अतिरिक्त परत केवल तभी एक्टिव होगी, जब डिवाइस विश्वसनीय लोकेशन से बाहर होगी। इससे सेंध को रोकने में मदद मिलेगी।

ऐसे करें एक्टिव
- सेटिंग को ओपन करें
- सिक्योरिटी व प्राइवेसी आप्शन पर क्लिक करें
- डिवाइस अनलाक पर टैप करें और थेफ्ट प्रोटेक्शन को चुनें।
- अब आइडेंटिटी चेक बटन पर क्लिक करें।
- अंत में एक्टिवेट द फीचर बटन पर क्लिक करें।

न्यू गैजेट

इनफिनिक्स स्मार्ट 9एचडी

देश में एंट्री सेगमेंट खरीदारों को ध्यान में रखते हुए इनफिनिक्स ने स्मार्ट 9एचडी फोन लांच किया है। इस फोन में 6.7 इंच एचडी+ ड्राप डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इनफिनिक्स के इस फोन में मीडियाटेक हीलियो जी50 2.2 गीगाहर्ट्ज आक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। फोन में 3+3 जीबी की रैम और 64 जीबी का इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है। फोन के डिजाइन की बात करें तो मेटीलेयर ग्लास फिनिश बैक, फ्लैट एज के साथ इसमें प्रीमियम डिवाइस जैसा लुक मिलता है। फोन में आइपी 54 स्प्लैश प्रूफ रेटिंग दी गई है। फोन में एलईडी फ्लैश और जूम के साथ 13 एमपी का ड्युअल रियर और आठ एमपी का सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड्रायड 14 गो एडिशन आधारित इस फोन में सी टाइप चार्जिंग पोर्ट के साथ 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। कीमत की बात करें तो 3जीबी/64 जीबी माडल की कीमत 6699 रुपये रखी गई है।

टेक अपडेट

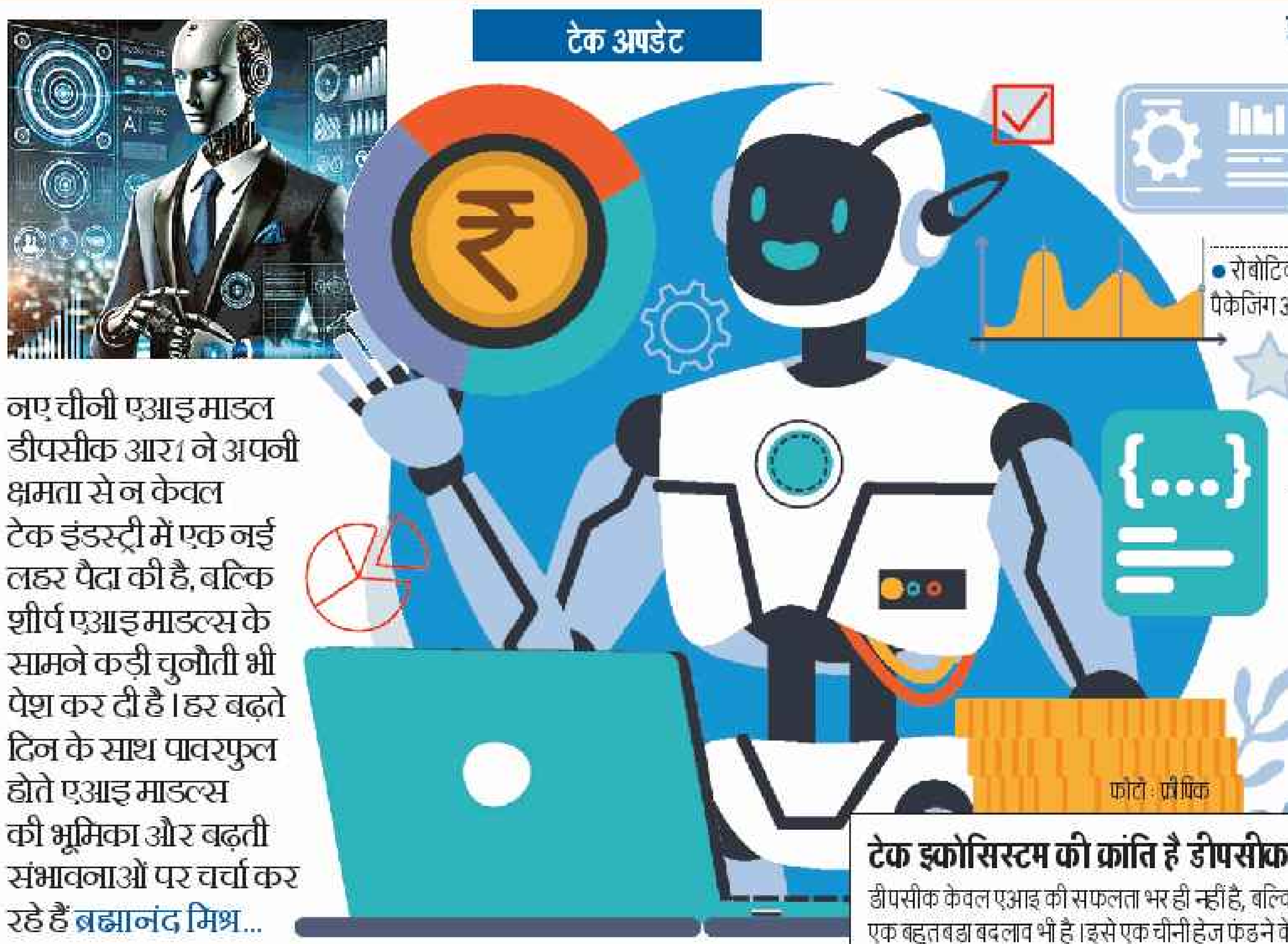

फोटो : फ्रीपिक

नए चीनी एआइ माडल डीपसीक आर1 ने अपनी क्षमता से न केवल टेक इंडस्ट्री में एक नई लहर पैदा की है, बल्कि शीर्ष एआइ माडल्स के सामने कड़ी चुनौती भी पेश कर दी है। हर बढ़ते दिन के साथ पावरफुल होते एआइ माडल्स की भूमिका और बढ़ती संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं **ब्रह्मानंद मिश्र...**

एआइ में अब चीन की चुनौती!

टेक इकोसिस्टम में अब चीनी एडवांस एआइ माडल डीपसीक आर1 की एंट्री हुई है, जो न केवल एक सस्ता और अच्छा विकल्प बन सकता है, बल्कि ओपनसोर्स होने के कारण स्वतंत्र डेवलपर भी इसे टेस्ट और कस्टमाइज कर सकते हैं। बीते दिनों एप स्टोर चार्ट पर डीपसीक ने जिस तरह चैटजीपीटी को मात दी है, उससे वाल-स्ट्रीट की शीर्ष टेक कंपनियों के बीच खलबली मची हुई है। अमेरिका द्वारा चीन को हाइ पावर एआइ चिप की आपूर्ति को रोकने के बावजूद डीपसीक ने इसे कम लागत में ही एनवीडिया के पूर्ववर्ती चिप एच800 पर ट्रेंड किया है। इससे भी सिलिकान वैली के प्रभुत्व को चुनौती मिलती दिख रही है। हालांकि एलएलएम (लार्ज लैंग्वेज माडल) की अपनी सीमाएं भी हैं, जो डीपसीक आर1 के मामले में भी स्पष्ट दिखती हैं। कुल मिलाकर कहें तो एआइ की रेस और भी तेज हो गई है। ओपनएआइ अपने एआइ एजेंट 'आपरेटर' के साथ नई सुविधाएं आफर करने की तैयारी में है। यह 'आपरेटर' जटिल कार्यों को सहजता से पूरा करने के साथ-साथ वेब ब्राउजर को कंट्रोल में लेकर अनेक आनलाइन कार्यों को संपन्न करने में समर्थ होगा। इसके लिए किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप या निगरानी की आवश्यकता नहीं होगी।

डीपसीक की एंट्री से बढ़ा एआइ का दायरा : डीपसीक आर1 की खास बात यह है कि मानव सोच की नकल करने के साथ-साथ किसी प्राम्प्ट पर प्रतिक्रिया देने से पहले तर्क भी देता है, यही खूबी इसे चैटजीपीटी ओ1 और लामा 3.2 जैसे अन्य एआइ माडलों से अलग बनाती है। इसकी तुलना ओपनएआइ की नवीनतम तकनीक के साथ की जा रही है। पारदर्शिता, असरकारक और सभी के लिए उपलब्धता के कारण भी इसे लेकर उत्साह बढ़ रहा है, जबकि ओपेन एआइ ओ1, क्लाउडी सोनेट और गूगल जेमिनी एडवांस वर्जन के लिए यूजर्स को एक निश्चित भुगतान करना होता है।

एआइ की दुनिया में हो रहे हैं नए प्रयोग : अगर पारंपरिक एआइ माडल से तुलना करें तो नए तरह के एजेंटिक एआइ जिस समस्या को हल करते हैं, वे पहले उसका लक्ष्य और यूजर का संदर्भ भी समझने का प्रयास भी करते हैं। पूर्ववर्ती एआइ असिस्टेंट नियमों में बंधे होते हैं और ट्रेंड डाटा पर उनकी काफी निर्भरता है, जिससे उनके स्वतः काम करने की क्षमता सीमित है तो वहीं एआइ एजेंट प्रो-एक्टिव माडल की तरह काम करते हैं। स्वयं के स्तर पर निर्णय लेने के लिए, एजेंटिक एआइ अलग-अलग मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रासेसिंग और आटोमेशन टेक्नोलाजी आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे इनकी यूजर उपयोगिता बढ़ती है।

नए एजेंटिक माडल्स की खूबियां : कंटेंट तैयार करने के बजाय एआइ एजेंट निर्णय लेने पर अधिक फोकस करते हैं, वहीं मानवीय संकेतों पर इनकी निर्भरता बहुत कम होती है। ये मुख्यतः सेल्स बढ़ाने, ग्राहक संतुष्टि और सप्लाई चेन दक्षता जैसे कार्यों के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। जेनेरेटिव एआइ से अलग ये एजेंटिक माडल कार्यों जैसे स्वयं डाटा बेस को सर्च करना या किसी कार्य के लिए वर्कफ्लो तैयार करने में सक्षम होते हैं यानी ये प्रो-एक्टिव प्लानर की तरह कार्य करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगला कदम क्या होगा, यह स्वतः ही तय करते हैं। स्पष्ट है कि चीनी हस्तक्षेप इस क्षेत्र में नए माइलस्टोन स्थापित करने जा रहा है।

इन कार्यों में एआइ एजेंट का प्रयोग

- आटोमेटेड ट्रेडिंग और फ्राडडिटेक्शन जैसे कार्यों में
- उपचार, जोखिम भांपने और मरीज देखभाल में मदद के लिए
- रिटेल और पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर
- होम आटोमेशन सिस्टम में अलग-अलग कार्यों के लिए
- रोबोटिक्स के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल के लिए
- नान-प्लेयर करेक्टर (एनपीसी) के तौर पर गेमिंग के लिए
- कस्टमर इन्क्वायरी के लिए
- नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर कंटेंट रिकमेंडेशन आदि के लिए

एआइ एजेंट्स के लाभ

- हर समय उपलब्धता
- कार्यों में निरंतरता
- लागत में कमी लाना
- त्रुटिरहित और बड़े स्तर पर कार्य करने की क्षमता
- बड़े पैमाने पर डाटा विश्लेषण
- मार्केटिंग जैसे कार्यों में पर्सनलाइजेशन

टेक इकोसिस्टम की क्रांति है डीपसीक आर1

डीपसीक केवल एआइ की सफलता भर ही नहीं है, बल्कि टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव भी है। इसे एक चीनी हेज फंड ने केवल 56 लाख डालर में और पुराने एनवीडिया एच800 चिप्स के साथ बनाया है। खास बात है कि इतनी कम लागत में तैयार होने के बावजूद यह एआइ माडल ओपनएआइ, गूगल जैसे सिलिकान वैली दिग्गजों को टक्कर दे रहा है। डीपसीक पारंपरिक रूप से महंगे हार्डवेयर वाले मानदंडों को भी चुनौती देता है। इससे आइटी कंपनियों को उन्नत, अनुकूलित एआइ एप्लीकेशन प्रदान करने में मदद मिलेगी। डीपसीक का ओपन-सोर्स रिलीज एआइ की स्वीकार्यता का दायरा बढ़ा रहा है। इससे छोटी कंपनियों के लिए भी नवाचार के मौके बनेंगे। इसीलिए इसे एआइ के लिए एक 'स्पुतनिक मोमेंट' की तरह देखा जा रहा है।

जसप्रीत बिंद्रा
सह-संस्थापक, एआइ एंड बियान्ड

कर्मचारियों की तरह होंगे एआइ एजेंट

हरनीत सिंह, चीफ एआइ आफिसर, रैबिट एआइ एवं एमडी, टेक क्यूरेटर्स

कंप्यूटर यूजिंग एजेंट्स (सीयूए) कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ ठीक वैसे ही काम कर सकते हैं, जैसे कोई इंसान करता है। जब आप किसी जानकारी के लिए गूगल सर्च करते हैं तो अलग-अलग साइट पर जाकर जानकारियों को एकत्र करते हैं। ये सभी काम अब चैटजीपीटी के आपरेटर जैसे एआइ एजेंट्स के साथ सहजता से संभव हैं। ये एजेंट स्क्रीन को विजुअली इंटरप्रेट करके, बटन और मेनू आदि की पहचान कर सकते हैं साथ ही वर्चुअल माउस या कीबोर्ड के उपयोग से कार्यों को पूरा कर सकते हैं। जैसे-जैसे कंप्यूटर का उपयोग करने वाले एजेंट लोकप्रिय और सटीक होंगे, वे आगे चलकर हमारे समाज का अभिन्न अंग बन जाएंगे। वे दैनिक जीवन के साथ कारोबारी गतिविधियों को भी प्रभावित करेंगे। हम कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले विशेष एआइ एजेंटों को ग्राहक सहायता, शेड्यूलिंग, इंटरनेट मीडिया कंटेंट क्रिएशन और पोस्टिंग, शोध और विश्लेषण, कोडिंग जैसे कार्यों को करते हुए देखेंगे। यात्रा बुकिंग से लेकर ई-मेल भेजने और रेटिंग्स के आधार पर बेहतर रेस्तरां खोजने जैसे काम एआइ एजेंट्स के जरिए होने लगेंगे। हालांकि डाटा सिक्योरिटी का जोखिम बढ़ेगा। आटोनामस एजेंटों द्वारा अनधिकृत गतिविधियां भी हो सकती हैं, 'एजेंट हाइजैकिंग' का रूप भी दिख सकता है। एआइ एजेंटों के भीतर कोडिंग त्रुटियां सुरक्षा खतरों को जन्म दे सकती हैं।

कितना अलग है चीनी डीपसीक आर1

एडवांस चीनी एआइ माडल डीपसीक आर1 की चर्चाओं के बीच प्रतिद्वंद्वी अन्य एडवांस एआइ माडल लामा 3.2 और ओपनएआइ ओ1 की खूबियों को भी जानना आवश्यक है। रीजनिंग और मल्टीमोडल क्षमताओं के साथ इन माडल्स में अनेक तकनीकी खूबियां, बेंचमार्क और उल्लेखनीय क्षमताएं हैं। डीपसीक आर1 'मिक्स्चर आफ एक्सपर्ट (एमओई)' आर्किटेक्चर का प्रयोग करता है तो वहीं चैटजीपीटी ओ1 मैथ्स, कोडिंग और साइंस के लिए 'एडवांस चेन आफ थाट्स' तकनीक का प्रयोग करता है। कार्य करने से पहले सोचने की क्षमता के चलते ओ1 रीजनिंग कार्यों में अधिक सक्षम है तो वहीं डीपसीक आर1 बेहतर प्रदर्शन और न्यूनतम लागत के चलते प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। लामा 3.2 की बात करें तो यह मल्टीमोडल उपयोगिता, खासकर विजन-एनेबल्ड माडल की खूबियों के लिए अलग पहचान रखता है। इन सभी के उपयोगिता की बात करें तो डीपसीक आर1 का प्रयोग कम लागत में रिसर्च और लीगल एनालिसिस जैसे कार्यों में तो लामा 3.2 का इमेज आधारित सर्च या डाक्यूमेंट एनालिसिस जैसे मल्टीमोडल कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वहीं ओपनएआइ ओ1 कोडिंग, साइंटिफिक रिसर्च और गणितीय गणनाओं में उपयोगी माडल साबित हो सकता है। हालांकि इन सभी की अपनी-अपनी सीमाएं भी हैं। डीपसीक अफोर्डेबल है, लेकिन मल्टीमोडल क्षमताओं का अभाव है, वहीं लामा 3.2 के छोटे माडल्स जटिल कार्यों के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। एक्सटेंडेड चेन आफ थाट्स पर आधारित होने के कारण ओपनएआइ ओ1 के लिए व्यापक कंप्यूटेशनल संसाधनों की आवश्यकता होती है।

स्मार्ट गैजेट्स

कैसे चुनें सही टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स

स्मार्टफोन में अब हेडफोन जैक की जगह ब्लूटूथ आडियो तकनीक, खासतौर पर टीडब्ल्यूएस (ट्रू वायरलेस स्टीरियो) ईयरबड्स लेने लगे हैं। यदि आप नया टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स खरीदने की सोच रहे हैं तो जानते हैं कि किन बातों और फीचर का ध्यान रखना चाहिए?

ईयरबड्स का डिजाइन : टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स दो डिजाइन में आते हैं- स्टेम वाले और स्टेम लेस। स्टेम वाले ईयरबड्स में स्टेम कान के बाहर लटकता है और इसमें माइक्रोफोन होता है। ये कालिंग के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। वहीं स्टेम लेस ईयरबड्स अधिक कांपैक्ट और हल्के होते हैं। यह डिजाइन जिम जाने या खेलकूद में सक्रिय रहने वालों के लिए बेहतर होता है। ये ईयरबड्स छोटे, स्टाइलिश और आरामदायक होते हैं।

चार्जिंग केस का डिजाइन : चार्जिंग केस में ध्यान रखें कि आपके फोन के पोर्ट जैसा चार्जिंग पोर्ट इसमें भी हो। मैट फिनिश वाले केस खरोंच के निशान से बचे रहते हैं। मजबूत हिंज और चार्जिंग इंडीकेटर लाइट वाला केस खरीदना बेहतर होता है।

साउंड और माइक्रोफोन क्वालिटी : बेस और हाइ फ्रीक्वेंसी दोनों नियंत्रित होना चाहिए। कस्टम साउंड ट्यूनिंग का विकल्प भी जरूरी है। ये ईयरबड्स एप से साउंड ट्यूनिंग का विकल्प देते हैं।

कनेक्टिविटी : कनेक्शन स्टेबल और स्ट्रांग होना चाहिए। क्विक पेयरिंग की सुविधा जरूरी है ताकि ईयरबड्स को आन और आफ करने पर यह आसानी से आपके फोन से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो सके।

नाइज कैंसिलेशन : एएनसी (एक्टिव नाइज कैंसिलेशन) बाहरी शोर और ईएनसी (एनवायर्नमेंटल नाइज कैंसिलेशन) तकनीक शोर को कम करती है। जरूरत के हिसाब से सही फीचर चुन सकते हैं।

बैटरी लाइफ और चार्जिंग : ईयरबड्स और उनके चार्जिंग केस दोनों की बैटरी क्षमता अधिक होनी चाहिए। कई ईयरबड्स में अब 10-15 मिनट की चार्जिंग पर घंटों की बैटरी लाइफ मिलती है। टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स खरीदते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। सही ईयरबड्स आपके म्यूजिक और कालिंग अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे।

टीडब्ल्यूएस फीचर

एक्टिव नाइज कैंसिलेशन (एएनसी) : यह तकनीक बाहरी शोर को पहचानकर उसे खत्म करती है, जिससे आप म्यूजिक और काल का बेहतर अनुभव ले सकते हैं। यह ट्रैफिक या भीड़भाड़ वाली जगहों के लिए परफेक्ट है।

ट्रांसपेरेंसी मोड : [illegible]

हाइ-रेस आडियो सपोर्ट : एलडीएसी और एप्टैक्स एचडी कोडेक्स साउंड क्वालिटी और डिटेल साउंड प्रदान करते हैं। यह फीचर म्यूजिक लवर्स के लिए उपयोगी है।

जेस्चर कंट्रोल : यह फीचर म्यूजिक प्ले/पाज, काल मैनेजमेंट, वाइस असिस्टेंट आदि जैसे फीचर को फोन छुए बिना आपरेट करने की सुविधा देता है।

मल्टी-प्वाइंट कनेक्टिविटी : [illegible]

वाइस असिस्टेंट सपोर्ट : गूगल असिस्टेंस, सिरी, एलेक्सा वाइस कमांड की मदद से बिना फोन छुए म्यूजिक, काल और जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं।

फास्ट चार्जिंग : [illegible]

गेमिंग मोड : [illegible]

आइपी रेटिंग : वाटर/डस्ट से सुरक्षा के लिए आइपीएक्स4 से आइपीएक्स7 रेटिंग का ध्यान रखें।

संतोष आनंद

आज का भविष्यफल : 30 जनवरी, 2025 गुरुवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति :
माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा।
आज का राहुकाल : दोपहर 01 बजकर 30 मिनट से 03 बजे तक।
आज का दिशाशूल : दक्षिण
पंचक : सायं 06 बजकर 35 मिनट से प्रारंभ, 03 फरवरी रात्रि 11 बजकर 17 मिनट पर समाप्त।

कल 31 जनवरी, 2025 का पंचांग

कल का दिशाशूल : पश्चिम
विशेष : पंचक
विक्रम संवत 2081 शके 1946 उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु माघ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया 14 घंटे तक तत्पश्चात तृतीया शतभिषा नक्षत्र 28 घंटे 15 मिनट तक तत्पश्चात पूर्वभाद्रपद नक्षत्र वरियान योग 15 घंटे 33 मिनट तक तत्पश्चात परिघ योग, कुंभ में चंद्रमा।

मेष : शासनसत्ता से सहयोग लेने में सफल होंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
वृष : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे।
मिथुन : महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। पिता या गुरु का सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी।
कर्क : संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
सिंह : रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।
कन्या : बुद्धि कौशल से कार्य संपन्न होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा।
तुला : संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किन्हीं कारणों से तनाव मिल सकता है।
वृश्चिक : उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन, सम्मान यश, कीर्ति में वृद्धि होगी।
धनु : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।
मकर : व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। जीविका में व्यवधान आ सकता है। तनाव की स्थिति रहेगी।
कुंभ : पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी।
मीन : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

वर्ग पहेली-2883

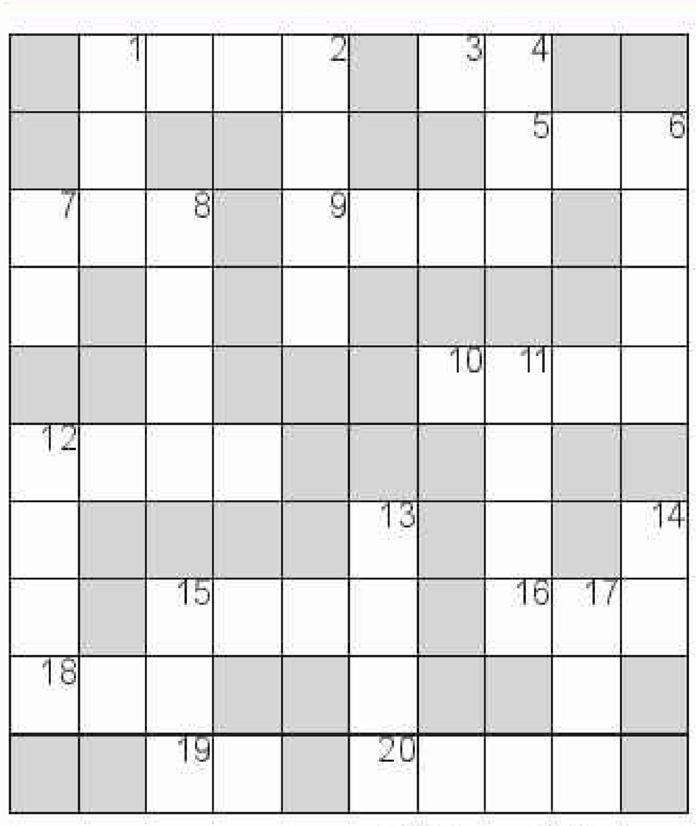

बाएं से दाएं
1. कामचोर, आलसी (4)।
3. जख्म, क्षत (2)।
5. तड़क-भड़क, सौंदर्य (3)।
7. अचानक, हठात (3)।
9. आदि, इत्यादि (4)।
10. परखने का भाव, परिचय (4)।
12. गणेश, जिसका उदर लंबा हो (4)। 15. मेघनाद की पत्नी, सुंदर [illegible]

© Bird Features & Writing Agency

कल का हल

च	म	क	ना				त	म	स
र			रा		फ़	ब	ना		मा
क	ब		ज	लॉ	ना				हा
	ह			ज			शा	ति	र
	स	ता		दं	द	नी	य		
		त	दं	त	र		र	ग	
का	त	र			वा			ह	
ना				है	जा	र		नी	कं

जागरण सुडोकू-2883

9			4					1
	2		6		3		7	
						3		
	4		3		5		2	
2		8			9	1		6
	6		2				4	
				7		9		3
	1		9		4		8	
3		6		5				4

कल का हल

5	8	6	2	1	4	3	7	9
9	7	2	5	8	3	1	6	4
1	3	4	6	7	9	2	8	5
3	2	8	1	5	6	9	4	7
4	6	1	9	3	7	5	2	8
7	5	9	4	2	8	6	1	3
2	1	3	7	4	5	8	9	6
8	9	7	3	6	1	4	5	2
6	4	5	8	9	2	7	3	1

राष्ट्रीय फलक

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'पशु बलि' के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका

मदुरई, एएनआइ : मदुरई के तिरुपरनकुंद्रम में सिकंदर बदुशा दरगाह पर बकरा और मुर्गा सहित अन्य जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है। मदुरई निवासी कन्नन द्वारा हाई कोर्ट की मदुरई पीठ के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की गई है।

याचिका में इस बात पर जोर दिया कि तिरुपरनकुंद्रम मंदिर पंड्या राजवंश के दौरान बनाया गया एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में उमयंदर गुफा मंदिर और 11 पवित्र तीर्थम (पवित्र तालाब) हैं।

उन्होंने तर्क दिया कि मंदिर क्षेत्र के भीतर पशु बलि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित सिकंदर बदुशा दरगाह पर जनवरी में एक सामुदायिक दावत आयोजित की थी, जिसके दौरान बकरा और मुर्गों की बलि दी गई थी। इस बलि से सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

दूल्हे को न दुल्हन मिली न उसका घर

जागरण संवाददाता, ऊना

- हिमाचल के ऊना में बरात सहित पंचायत घर में बैठा रहा दूल्हा, शाम को बिना दुल्हन के ही घर पहुंचा

हिमाचल के ऊना में स्थित हरोली क्षेत्र के गांव सिंगा में मंगलवार सुबह दूल्हा और बराती धूमधाम के साथ शादी के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें न दुल्हन मिली और न ही उसका घर। इसके बाद मामला तनावपूर्ण हो गया। जिस महिला ने रिश्ता करवाया था उससे संपर्क करने का प्रयास हुआ तो उसका भी पता नहीं चला। इसके बाद दूल्हा बरात सहित पंचायत घर में बैठ गया। पता चला कि दूल्हे को पंजाब की एक महिला बिचौलिये ने धोखाधड़ी का शिकार बनाया है।

ऊना के ही नारी अपर गांव के एक युवक की उसके पड़ोस में एक विवाह समारोह के दौरान रिश्ते करवाने वाली पंजाब की एक महिला से पहचान हो गई। युवक खेतीबाड़ी करता है। महिला ने युवक को सिंगा गांव के एक गरीब घर की बेटी की फोटो दिखाई और रिश्ता पक्का किया। कुछ दिन बाद महिला ने युवक के स्वजन से रिश्ते के लिए 50 हजार रुपये लिए और कहा कि लड़की वाले सादगी से विवाह करेंगे। महिला ने 28 जनवरी को सिंगा गांव में बरात लेकर आने का निमंत्रण दिया। मंगलवार सुबह नारी अपर गांव से सिंगा गांव में बरात पहुंची। बरात में शामिल करीब 90 लोग जब सिंगा पहुंचे तो वहां उनका स्वागत करने के लिए न तो रिश्ता करवाने वाली महिला मिली और न ही लड़की पक्ष से कोई आया था। रिश्ता करवाने वाली महिला से फोन पर संपर्क किया गया तो वह टालमटोल करने लगी। उसने बताया कि लड़की ने जहर निगल लिया है और उसे पंजाब के नवांशहर लेकर गए हैं। धोखाधड़ी का संदेह होने पर दूल्हे के पिता पंचायत प्रधान के पास पहुंचे तो पता लगा कि सिंगा गांव में मंगलवार को कोई विवाह समारोह नहीं था। दूल्हे के पिता ने जो फोटो दिखाई, वैसी कोई लड़की गांव में नहीं है। इसके बाद मामला हरोली पुलिस के पास पहुंचा। शाम को दूल्हा बरात लेकर बिना दुल्हन के वापस घर पहुंचा।

महाराष्ट्र में महिला के गर्भ में 'भ्रूण के अंदर भ्रूण' की दुर्लभ स्थिति मिली

बुलढाणा, प्रेट्र : महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक दुर्लभ मामला सामने आया है। यहां जिला महिला अस्पताल में जांच के लिए आई एक गर्भवती महिला के की कोख में पल रहे बच्चे के पेट में भ्रूण होने का पता चला है। इस गर्भावस्था को मेडिकल की भाषा में 'फिटुस इन फिटु' कहा जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ स्थिति है, जिसमें एक विकृत भ्रूण दूसरे भ्रूण के अंदर स्थित होता है। यह मामला तब सामने आया जब तीन दिन पहले बुलढाणा जिला अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए एक गर्भवती महिला आई। डाक्टर ने महिला की सोनोग्राफी की तो बच्चे के गर्भ में भ्रूण साफ दिखाई दे रहा था। डाक्टर बिना जोखिम उठाए महिला की डिलीवरी कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डा प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 'भ्रूण में भ्रूण' दुर्लभतम मामला होता है और यह स्थिति पांच लाख में से एक में पाई जाती है। अब तक पूरे विश्व में ऐसे केवल 200 मामले ही सामने आए हैं और वे भी प्रसव के बाद ही।

'राजद एमएलसी के निष्कासन में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन'

- बिहार विधान परिषद ने निष्कासन के बाबत सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, प्रेट्र : बिहार विधान परिषद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सदन से निष्कासित करने में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था और वह दरअसल परिषद की इच्छा को चुनौती दे रहे थे।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ को वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने सूचित किया कि सुनील कुमार पहले भी कदाचार में शामिल रहे हैं और उनके निष्कासन की सिफारिश करने वाले आचार समिति के फैसले पर सदन में उचित रूप से बहस हुई थी।

राजद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था और सिंह ने केवल इतना कहा था कि लोग कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ''पलटूराम'' हैं। 'आनुपातिकता का सिद्धांत' को आमतौर पर प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े अधिकांश मामलों में न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में माना जाता है।

शंकरनारायणन ने कहा, ''नियमों में क्रमिक दंड का प्रविधान है। मैंने आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर रिपोर्ट पर सवाल उठाया है।''

पीठ ने कहा, ''आप सदन के सम्मानित सदस्य थे। आपको अपने बयानों में कुछ परिपक्वता दिखानी चाहिए। आपको उदाहरण पेश करना चाहिए और इस तरह के बयानों में लिप्त नहीं होना चाहिए।'' सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से अगले तीन दिनों में अपनी लिखित दलीलें पेश करने को कहा और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

सौरभ प्रकरण में जब्त 54 किलो सोना मामले में हवाला का शक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की काली-कमाई का प्रतीक बने पूर्व आरक्षक शर्मा की गिरफ्तारी के साथ ही उसके करीबी चेतन गौर की कार में मिले 54 किलो सोने को लेकर नई जानकारी सामने आई है। सोने की ईंटों में लगे सील से आयकर विभाग को संदेह है कि यह सोना दुबई, आस्ट्रेलिया या स्विटजरलैंड से लाया गया है। दरअसल, सौरभ का दुबई आना-जाना रहा है। लोकायुक्त पुलिस वहां उसका कारोबार होने की संभावना भी जता चुकी है। सोना खरीदी में हवाला का भी संदेह है, ऐसे में जांच के लिए आयकर विभाग ने डीआरआइ को लिखा है। बता दें कि गत 18 दिसंबर 2024 को सौरभ और उसके करीब चेतन गौर के भोपाल स्थित ठिकानों पर लोकायुक्त टीम ने छापा मारा था। भोपाल में मेंडोरी गांव में प्लाट में खड़ी कार में 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये मिले थे। कार चेतन के नाम है।

****

शोधकर्ताओं ने मनुष्यों के सबसे पहले ज्ञात पूर्वज की पहचान की

2017 में आज ही के दिन शोधकर्ताओं ने चीन में मनुष्यों के सबसे पहले ज्ञात पूर्व ऐतिहासिक पूर्वज की पहचान की थी। यह 54 करोड़ वर्ष पुराने बैग जैसा दिखने वाला समुद्री जीव सैकोरहाइटस कोरोनारियस का जीवाश्म था। अनुमान है कि इसकी लंबाई एक मिलीमीटर रही होगी।

इतिहास की बड़ी समुद्री आपदा में गईं नौ हजार जानें

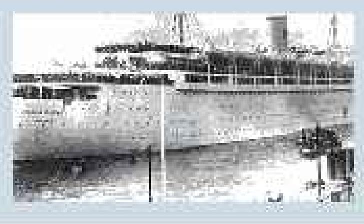

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में आज ही जर्मन समुद्री जहाज विल्हेम गुस्टलाफ को एक सोवियत पनडुब्बी ने डुबो दिया था। इसमें करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी। जहाज बर्लिन से शरणार्थियों को ले जा रहा था। इसे इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदा माना जाता है।

बाघ संरक्षण के लिए आवाज उठाने वाले कैलाश सांखला

भारत के टाइगर मैन कहे जाने वाले कैलाश सांखला का जन्म 1925 में आज ही जोधपुर में हुआ था। 1953 में भारतीय वन सेवा से जुड़ गए और दो दशक तक विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों और दिल्ली जूलाजिकल पार्क में काम किया। उन्हीं के प्रयासों की बदौलत बाघों की आबादी में गिरावट देखते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। इससे पहले निदेशक के रूप में उन्होंने बाघ अभयारण्य बनाने, वन रक्षकों को प्रशिक्षण देने और अवैध शिकार विरोधी कानूनों को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई।

जागरण विशेष

फूंक मारते ही पता चल जाएगा शरीर में शर्करा का स्तर

बालाघाट के विज्ञानी और उनकी टीम का नवाचार, बिना रक्त निकाले हो सकेगी शर्करा की जांच

योगेश कुमार गौतम ● नईदुनिया

बालाघाट: मधुमेह रोगियों को शर्करा (शुगर) की मात्रा का पता लगाने के लिए, अब रक्त का नमूना देने से मुक्ति मिल सकती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी पीजी कालेज के सहायक प्राध्यापक डा. दुर्गेश अगासे और उनकी टीम ने ऐसी डिवाइस तैयार की है, जिसमें मात्र फूंक मारने से मधुमेह रोगी के शरीर में शर्करा के स्तर का पता चल सकेगा। इस नवाचार का नाम 'नान इनवेसिव ब्लड ग्लूकोज मेजरिंग डिवाइस' है।

हाल ही में दिल्ली में संपन्न 'विकसित भारत-यंग लीडर्स डायलाग' कार्यक्रम में देशभर के 72 प्रोजेक्ट के साथ इसे प्रदर्शित किया गया था। इसमें इसे पांचवां स्थान मिला है। पीएम गैलरी में चुने गए देशभर के 12 प्रोजेक्ट में भी इसे शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट का पेटेंट प्रकाशित हो चुका है। इस टीम में विद्यार्थी हर्ष तिवारी, पल्लवी ऐड़े, वर्षा धुर्वे, रश्मि ठरकुड़े और अंकित काले शामिल हैं।

यह यंत्र बेहद अनूठा है क्योंकि इसे विकसित करने के लिए किसी कंपनी से तकनीकी या आर्थिक सहायता नहीं ली गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस यंत्र की सराहना की है। बालाघाट के वरिष्ठ चिकित्सक (कार्डियो डायबिटोलाजिस्ट) डा. बीएम शरणागत का कहना है कि अगर डिवाइस एसीटोन से शर्करा का स्तर बता रही है, तो मधुमेह रोगियों के लिए कारगर साबित होगी। मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा. वेदप्रकाश लिल्हारे का कहना है कि ये डिवाइस उन मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद होगी, जिनके शरीर में कीटोन बनता है। इसी से एसीटोन का उत्सर्जन भी होता है।

50 से ज्यादा मधुमेह रोगियों का अध्ययन कर तैयार की डिवाइस

डा. दुर्गेश अगासे

इस डिवाइस को तैयार करने से पूर्व 50 से ज्यादा मधुमेह रोगियों में एसीटोन की मात्रा और उसी समय उनके ब्लड शुगर के लेवल का अध्ययन किया गया। दोनों के बीच के समीकरण को खोजने के बाद डिवाइस विकसित की गई। इसे एक प्रोग्राम में बदलकर इसमें सेंसर का उपयोग किया। डा. दुर्गेश अगासे का कहना है कि इस सेंसर को और अपडेट किया जा रहा है। डिवाइस को विकसित करने में फंडिंग और तकनीकी सहयोग के लिए भोपाल स्थित मैनिट संस्था के इंजीनियरों ने रुचि दिखाई है। डा. अगासे का कहना है कि अगर एसीटोन के सेंसर का उत्पादन किया जाए, तो यह डिवाइस मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी।

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष माडल को प्रस्तुत करती पल्लवी ऐड़े ● सौजन्य डा. दुर्गेश अगासे

रोगी की निगरानी में मददगार

अगर आइसीयू में भर्ती मधुमेह रोगी के शुगर की लगातार निगरानी रखनी है, तो यह यंत्र उपयोगी सिद्ध होगा। रोगी के मुंह पर मास्क के रूप में इसे रखकर स्क्रीन पर मरीज के शुगर की सतत निगरानी की जा सकेगी। हार्ट बीट की तरह स्क्रीन पर रोगी का शर्करा का स्तर स्क्रीन पर दिखाई देगा। डा. अगासे ने कैंसर बायोलाजी में पीएचडी किया है। उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के 19 प्रकाशन प्रकाशित हो चुके हैं।

ब्रीथ एनालाइजर की तर्ज पर तैयार की डिवाइस: डा. अगासे ने बताया कि इसे बनाने की परिकल्पना मधुमेह के मरीज के मेटाबालिज्म का अध्ययन करने के दौरान की थी। इसमें पता चला कि मधुमेह रोगी का मेटाबालिज्म कीटोजेनिक मेटाबालिज्म की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कीटोन का ही एक प्रकार है एसीटोन, जो मधुमेह रोगी द्वारा श्वास लेने के दौरान नाक से गैस के रूप से निकलता है। टीम ने ब्रीथ एनालाइजर की तर्ज पर यह यंत्र तैयार किया। इसमें लगा सेंसर रोगी की श्वास से निकले एसीटोन से उसके शरीर में शुगर की मात्रा दर्शाएगा। मधुमेह की जांच में यह नवाचार बड़ा बदलाव लाएगा।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

एक दिन की नवजात की ओपन हार्ट सर्जरी कर बचाई जान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : फोर्टिस एस्कार्ट्स ओखला के डाक्टरों ने मात्र एक दिन की नवजात बच्ची की जटिल हार्ट सर्जरी कर उसकी जान बचाने में सफलता हासिल की है। यह बच्ची जन्म से ही दिल की ट्रांसपोजिशन आफ द ग्रेट आर्टरीज नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें हृदय की प्रमुख धमनियां गलत वेंट्रिकल्स से जुड़ जाती हैं।

फोर्टिस एस्कार्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, ओखला के निदेशक डा. नीरज अवस्थी और उनकी टीम ने इस नवजात का सफल आर्टेरियल स्विच आपरेशन किया। यह जटिल ओपन हार्ट सर्जरी तीन घंटे चली और आपरेशन के बाद बच्ची की स्थिति में सुधार हुआ। 16 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई।

इधर-उधर की

पैसे लेकर दे रहा मर्दानगी दिखाने का मौका

कुआलालंपुर, एजेंसी : अब फिल्मों के अलावा असल जिंदगी में लोगों को गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनाने के लिए मलेशिया के 28 वर्षीय शाजाली सुलेमान ने विलेन फार हायर सेवा शुरू की है। सुलेमान ने इंटरनेट मीडिया पर प्रचार करते हुए लिखा है कि वह उचित शुल्क लेकर ग्राहकों को उनकी मर्दानगी दिखाने में मदद कर सकता है। उसने लिखा, 'बस मुझे समय और स्थान बताएं, मैं आपके साथी को परेशान कर हीरो बनने का मौका दूंगा'। विलेन की छवि को निखारने के लिए बड़े बालों के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की है। पोस्ट तेजी से प्रसारित हो रही है। एक यूजर ने लिखा इसे बाद में उपयोग के लिए सेव कर लेता हूं।

सुलेमान ने विलेन जैसे लुक में तस्वीर साझा की। इंटरनेट मीडिया

दो नर चूहों से संतान पैदा करने में कामयाबी

उपलब्धि ▶ बड़े हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा चूहे, समलैंगिक पुरुषों के लिए पैदा कर सकेंगे संतान

लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने की भी जगी उम्मीद

नई दिल्ली, जेएनएन : विज्ञानियों को दो नर चूहों से स्वस्थ संतान पैदा करने में कामयाबी मिली है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिये पैदा किए गए ये चूहे बड़े हो गए हैं। इस उपलब्धि से लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने को रोकने की उम्मीद जगी है। बीमारी या अन्य कारकों से क्षतिग्रस्त ऊतकों या अंगों को बदलना भी संभव हो सकता है। यह सफलता समलैंगिक पुरुषों के लिए संतान पैदा करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इससे मानव शरीर के रोगों का माडल तैयार करना आसान होगा।

चीन के शोधकर्ताओं का कहना है कि केवल दो नर चूहे के जेनेटिक मेटेरियल का उपयोग करके चूहों को पैदा किया है। इसके लिए मादा चूहे का उपयोग नहीं किया गया। इसके लिए 'भ्रूण स्टेम सेल इंजीनियरिंग' तकनीक का उपयोग किया गया। इस तकनीक के जरिये वैज्ञानिकों ने एक चूहे के स्पर्म से अंडे बनाए जिन्हें दूसरे चूहे के स्पर्म से निषेचित किया गया। स्टेम सेल तकनीक नई नहीं है, लेकिन पिछले सभी प्रयासों में पूरी सफलता नहीं मिल सकी थी। स्टेम कोशिकाएं विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विकसित करने की क्षमता होती है।

भ्रूण में मौजूद भ्रूण स्टेम कोशिकाएं, भ्रूण के सभी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखती हैं। यह शोध सेल स्टेम सेल जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग से पैदा चूहे। फाइल

दो नर चूहों से इस तरह बनाए चूहे

- एक नर चूहे से लिया स्पर्म
- इस शुक्राणु से बनाई स्टेम कोशिका
- इन स्टेम कोशिकाओं के जीन को एडिट किया
- एडिट स्टेम कोशिकाओं से अंडे बनाए
- दूसरे नर चूहे से स्पर्म लिया
- स्पर्म को इन अंडे से मिलाया
- भ्रूण को सरोगेट में प्रत्यारोपित किया
- दोनों नर चूहे के संतान पैदा हुए

शोधकर्ताओं ने 20 जीन को किया गया एडिट

भ्रूण स्टेम सेल से भ्रूण के सभी तरह की कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं। शोधकर्ताओं ने चूहों के 20 जीन को एडिट किया। इसके लिए क्लोनिंग तकनीक का उपयोग किया गया। नर जीन के दो सेटों का उपयोग करके प्रजनन किए गए चूहे या तो विकसित नहीं हुए या गंभीर विकृति के साथ पैदा हुए और मर गए। हालांकि, चूहों की स्टेम कोशिकाओं में 20 अलग-अलग जीनों को एडिट करने के बाद शोधकर्ताओं को स्वस्थ चूहे पैदा करने में सफलता मिली। शोधकर्ताओं ने 1,081 भ्रूण बनाए। उनमें से कुल 84 नर और 50 मादा चूहों का जन्म हुआ। इनमें से आधे से अधिक बड़े होने से पहले ही मर गए।

डायबिटीज पीड़ित होते हैं विटामिन डी व मैग्नीशियम की कमी के शिकार

अनुसंधान

एक शोध में पाया कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। यह समस्या 60 प्रतिशत से अधिक लोगों में पाया गया। यह अध्ययन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल न्यूट्रिशन प्रिवेंशन एंड हेल्थ में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने 1998 और 2023 के बीच 52,000 से अधिक लोगों पर किए गए 132 अध्ययनों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों में दूसरी कमी जो सबसे आम है वह मैग्नीशियम की कमी है। डायबिटीज से पीड़ित 42 प्रतिशत लोगों में इसकी कमी पाई गई, 28 प्रतिशत लोगों में आयरन की कमी थी।

भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान राजस्थान सहित अन्य शोधकर्ताओं ने कहा कि अध्ययन सूक्ष्म पोषक तत्वों की टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ितों में कमी के वैश्विक प्रसार का आकलन करने में मदद करता है। इससे शारीरिक कार्य के लिए विटामिन और खनिजों का स्तर बहुत कम है।

टीम ने पाया कि पुरुषों की तुलना में डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का खतरा अधिक होता है। उन्होंने बताया कि डायबिटीज के विकास के जोखिम कारकों में आनुवंशिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ पर्यावरणीय कारक, जैसे जीवन शैली, आहार व मोटापा शामिल हैं। अध्ययनों से पता चला है कि सूक्ष्म पोषक तत्व डायबिटीज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, अध्ययन का उद्देश्य पिछले अध्ययनों से परस्पर विरोधी सुबूतों को हल करना था जो विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्व पर केंद्रित थे। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

शादी को निजी रखा था तापसी ने। फाइल

फिल्में देखते समय यह ख्याल क्यों आना चाहिए कि मेरी शादी हुई है या नहीं : तापसी पन्नू

भले ही कलाकार फिल्में दर्शकों के लिए करते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी निजी जिंदगी होती है, जिसे वह निजी ही रखना चाहते हैं। जब तापसी पन्नू ने पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मैथियास बो से शादी की थी, तो कई सवाल उठे कि उन्होंने शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। अब तापसी ने कहा कि निजी और पेशेवर जिंदगी में अंतर रखना मैंने दूसरों की गलतियों को देखकर सीखा है कि कैसे पति-पत्नी करियर की असफलताओं को एकदूसरे पर डाल देते हैं। करियर के शुरुआत में मैंने गांठ बांध ली थी कि मैं निजी जिंदगी को इंडस्ट्री से दूर रखूंगी। मैं भाग्यशाली थी कि पति भी ऐसे मिले, जो इस इंडस्ट्री से नहीं हैं। मेरे दिमाग में यह बात घर कर ली थी कि इस इंडस्ट्री के किसी इंसान को निजी जिंदगी में नहीं देख सकती हूं। अभी तक खुद के सारे निर्णय ठीक ही लग रहे हैं। मैंने शादी को कभी सीक्रेट नहीं, प्राइवेट जरूर रखा। मुझे नहीं लगा कि एक्टर होने के नाते मेरे टू डू लिस्ट में होना चाहिए कि मैं शादी करूं, तो उसका प्रेस रिलीज करूं। मैं निजी जिंदगी में क्या निर्णय ले रही हूं, मेरे पेशेवर जिंदगी में प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। थिएटर में मेरी फिल्में कोई देखने जा रहा है, तो उसके दिमाग में ये क्यों बात आनी चाहिए कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है या किससे हुई है। मैं चाहती हूं कि मेरी फिल्म देखने जाएं, तो केवल मेरे काम के बारे में सोचें।

जान अब्राहम के साथ दिखेंगी प्रियंका

इन दिनों हालीवुड में सक्रिय देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एक अंतराल के बाद एसएस राजामौली की अगली फिल्म के साथ भारतीय सिनेमा में वापसी करने की तैयारी कर रही हैं। उसका संकेत उन्होंने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दिया था। अब खबर है कि जान अब्राहम भी महेश बाबू के साथ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। दिलचस्प बात यह है कि साल 2008 के बाद प्रियंका और जान की जोड़ी फिर से साथ आएगी। उन्हें आखिरी बार रोमांटिक-कामेडी फिल्म दोस्ताना में साथ देखा गया था। राजामौली की नवीनतम फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। प्री-प्रोडक्शन का काम जोरों पर है।

फिल्मी गलियारों की खबरों के मुताबिक पहले इस भूमिका के लिए पृथ्वीराज सुकुमारन पर विचार किया गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब जान, प्रियंका चोपड़ा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ उनके कई सीन हैं और शूटिंग हैदराबाद में ही होगी। इसके अलावा जान की आगामी फिल्म द डिप्लोमैट सात मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। शिवम नायर द्वारा निर्देशित और रितेश शाह द्वारा लिखित यह फिल्म एक सच्ची कहानी से प्रेरित है।

...शास्त्रीय नृत्य के प्रति मीनाक्षी शेषाद्रि का प्यार न होगा कम

पूर्व बालीवुड अभिनेत्री और प्रसिद्ध नृत्यांगना मीनाक्षी शेषाद्रि ने भले ही अभिनय से दूरी बना ली है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। साल 1983 में 'पेंटर बाबू' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली मीनाक्षी ने चार भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पिछली सदी के आठवें दशक के दौरान हीरो, मेरी जंग और दामिनी जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्हें काफी सराहा गया है। मीनाक्षी इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। बुधवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कई फोटो पोस्ट की जिसमें नृत्य की कई मुद्राएं नजर आ रही हैं, जो कला के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती हैं। साथ ही लिखा कि संगीत और नृत्य की शास्त्रीय कलाओं के लिए सम्मान व्यक्त करती हूं।

इंस्टाग्राम- @iammeenakshiseshadri

खत्म हुआ इब्राहिम अली का इंतजार

पिछले काफी समय से अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान को बालीवुड में लांच करने की खबरें रही है। अब उसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में निर्माता-निर्देशक करण जौहर ने इब्राहिम के माता-पिता के साथ रिश्ते की यादें साझा कीं, साथ ही परिवार के साथ लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को याद किया। हालांकि करण ने फिल्म का नाम अभी घोषित नहीं किया है। करण ने लिखा कि मैं अमृता या डिंगी से मिला, जैसा कि उनके करीबी उन्हें बुलाते हैं, जब मैं सिर्फ 12 साल का था। उन्होंने मेरे पिता यश जौहर के लिए साल 1984 में दुनिया नामक फिल्म की थी और मुझे उनकी ऊर्जा और शालीनता याद है। उन्होंने सैफ से पहली बार मिलने की याद भी ताजा की, उन्होंने बताया कि सैफ के साथ पहली मुलाकात आनंद महेंद्रू के दफ्तर में हुई थी। युवा, सौम्य, आकर्षक और सहज...बिलकुल वैसा ही जैसा पहली बार जब मैं इब्राहिम से मिला था। एक मजबूत दोस्ती, जो हमारी पीढ़ी से लेकर सौभाग्य से हमारे बच्चों तक जारी है। मैं इस परिवार को पिछले चार दशक से जानता हूं। उन्होंने इब्राहिम के लाइमलाइट में आने को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि फिल्में उनके खून, जीन और जुनून में हैं। इब्राहिम की बहन सारा अली खान की फिल्म सिंबा से भी करण बतौर निर्माता जुड़े रहे हैं। सारा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करण की घोषणा को साझा करके हुए लिखा कि इब्राहिम फिल्मों में आपका स्वागत है।

बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं इब्राहिम। इंस्टाग्राम -@iakpataudi

'धड़क' से इस मामले में अलग है 'साले आशिक'

फिल्मों के मुद्दे जब आपस में मेल खाते हैं, तो उनके बीच तुलना हो ही जाती है। इस तुलना के लिए तैयार हैं निर्देशक, लेखक और गीतकार जोड़ी सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल। दुकान फिल्म के बाद दोनों अब साले आशिक फिल्म लेकर आ रहे हैं, जो आनर किलिंग पर बनी है। इससे पहले आई धड़क भी इसी मुद्दे पर बनी थी। ऐसे में तुलना को लेकर वह कहते हैं, 'यह फिल्म आनर किलिंग पर बनी जरूर थी, लेकिन उसमें उसका कोई समाधान नहीं दिखाया गया था। हमने केवल मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि ऐसा समाधान बताया है, जो संभव है। डंके की चोट पर कह सकते हैं कि साले आशिक में प्रेमी पलटकर मारेगा और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।' यह फिल्म एक फरवरी को सीधे सोनी मैक्स चैनल पर रिलीज होगी।

हमने केवल मुद्दा नहीं उठाया है, बल्कि ऐसा समाधान बताया है, जो संभव है। साले आशिक में प्रेमी पलटकर मारेगा और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।

...इसलिए कभी हार नहीं मानते हैं जयेश

टीवी कलाकारों के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है कि उन्हें उनके पात्रों के नाम से लोग याद रखते हैं, जबकि फिल्मों में ऐसा कम ही हो पाता है। सोनी सब चैनल के शो पुष्पा इम्पासिबल के मुख्य कलाकार जयेश मोरे इस बात से खुश हैं कि लोग उन्हें घर से बाहर दिलीप पटेल कहकर बुलाते हैं। इस पात्र की अच्छी बातों का प्रभाव भी जयेश पर हुआ है। वह कहते हैं कि तीन साल से ज्यादा समय से दिलीप का रोल कर रहा हूं। उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति और कभी हार न मानने वाले स्वभाव का मुझ पर प्रभाव पड़ा है। दिलीप जिस तरह हर चुनौती का डटकर सामना करता है, वह मेरे अपने संघर्षों से काफी मिलता-जुलता है। दिलीप के किरदार ने मुझे एक अभिनेता के तौर पर कुछ सिखाया है। इस रोल ने मुझे देश के कोने कोने में पहचान दिलाई है। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, लोग मुझे दिलीप पटेल के नाम से पहचानते हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी यह पात्र इतना प्रसिद्ध है। जब बनारस गया था, तो वहां भी लोग मुझे इसी नाम से बुला रहे थे। यह बातें अहसास कराती हैं कि इस किरदार ने लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव छोड़ा है। लोग मुझे अपने परिवार और समाज का हिस्सा मानते हैं।

पुष्पा इम्पासिबल में दिलीप का पात्र निभाते हैं जयेश। टीम जयेश

आगे की फिल्मों में जरूर रहेगा सिंघम वाला फील

पिछले साल दिवाली पर रिलीज रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित पुलिस यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म सिंघम अगेन को बाक्स आफिस पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। दरअसल, बाजीराव सिंघम की अलग पहचान रही है, जो अकेले दम पर खलनायकों को धूल चटाने और शानदार एक्शन दृश्यों के लिए पहचान रखता है। सिंघम अगेन में वह कहीं नजर नहीं आया। जब अजय देवगन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, 'मुझे कई लोगों से इस तरह की प्रतिक्रिया मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए अपनी आने वाली फिल्मों में किरदार को सही तरीके से पेश करना सुनिश्चित करूंगा। सिंघम का जो फील था, घुस घुस के मारने का, वो आगे जरूर रहेगा।'

सिंघम अगेन में गलतियों को अजय ने स्वीकारा ● जागरण »

करण के साथ लौटे सिद्धार्थ मल्होत्रा

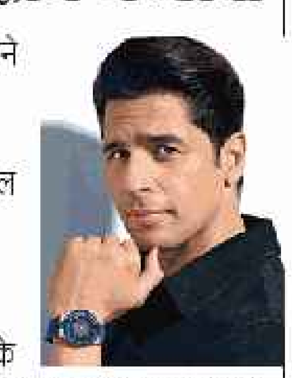

करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट आफ द ईयर से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करने वाले अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर उनके साथ फिल्म करने की तैयारी में हैं। फिल्म शेरशाह की रिलीज के चार साल बाद दोनों साथ आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल गुप्त रखा गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वे शरण शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म के लिए बातचीत कर रहे हैं। शरण इससे पहले जाह्नवी कपूर की गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल और पिछले साल की स्पोर्ट्स ड्रामा मिस्टर एंड मिसेज माही का निर्देशन कर चुके हैं। करण सिद्धार्थ को इस फिल्म के लिए एकदम फिट मानते हैं और सिद्धार्थ ने भी मौखिक रूप से स्वीकृति दे दी है और पूरी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं।

****